



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2005/भाद्र 30, 1927

No. 133]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2005/BHADRA 30, 1927

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या 1-सीए (5)/56/2005.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (5) की व्यवस्थाओं के अनुसार 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) तथा अंकित लेखा की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना हेतु एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

56वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् को 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष की 56वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.), जिसकी स्थापना, 1 जुलाई, 1949 को संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी, इस वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के 56वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। परिषद् इस संस्थान के लिये सदस्यों और छात्रों की प्रशंसा करती है जो चार्टर्ड लेखाकर्म वृत्ति को प्राप्त है और उस भूमिका की प्रशंसा करती है जो इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिये अदा की है। परिवर्तनशील व्यापार क्रम में लेखाकर्म वृत्ति के लिये अनेक संभावनाएं और अवसर प्रदान करने की आशा है जो कि वित्तीय क्षेत्र में बने रहने का मुख्य साधन है।

सार्वभौमिकता ने विश्वभर में अर्थव्यवस्था का पद्धति को बदल दिया है। आज कोई भी अर्थव्यवस्था संकीर्ण होकर नहीं रह सकती। सर्विस सेक्टर जो कि अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं का वृहत्तम और सबसे अधिक फैलने वाला सेक्टर है, विकास के प्रत्येक स्तर पर देशों की आर्थिक गतिविधियों पर छाया हुआ है। रुझान स्पष्ट है, जैसे-जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी और आय में वृद्धि होगी, वैसे ही जीडीपी का एक बड़ा भाग वाणिज्यिक सर्विस सेक्टर को प्राप्त होता है। भारत में भी, सर्विस सेक्टर का अंश 2004-2005 में जीडीपी का 52 प्रतिशत रहा है। सर्विस का निर्यात भी विश्व में सबसे अधिक तेज दर से वृद्धि करने वाला सेक्टर है। सेवाओं के व्यापक प्रकारों में भारत के प्रतिभाशाली व्यवसायियों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप, भारत को सेवाएँ निर्यात करने में अच्छा कौशल प्राप्त है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई सी ए आई) का विश्वास है कि सक्षम ढांचा उपलब्ध होने पर भारत में यह वृत्ति सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी और इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी वृत्ति के रूप में विकसित होने के लक्षण विद्यमान हैं। मेक्रो और माइक्रो स्तर पर क्रियात्मक उपाय पहले से ही किये जा रहे हैं और सार्वभौमिक लेखाकर्म वृत्ति की सभी मांगों को पूरा करने के लिए इन्हें और गति प्रदान की जा रही है। प्राकृतिक उपसाध्य के रूप में इस वातावरण में चार्टर्ड लेखाकर्म की भूमिका बहुरूपी हो जाती है। आई.सी.ए.आई. की दृष्टि से लेखाकर्म सेवाओं का प्रगतिशील उदारीकरण व्युत्क्रम आधार पर होना चाहिये अर्थात् भारत में वृत्ति के लिए एक अवसर, ना की संकट के रूप में।

इस परिप्रेक्ष्य में, रिपोर्ट में परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2004-2005 की महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया गया है तथा संक्षेप में जून 2005 के अंत तक का। रिपोर्ट में वर्ष के दौरान सदस्यों और छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा सांख्यिकीय रूप रेखा भी सम्मिलित की गई है।

रिपोर्ट में परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों की महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्रमुखता से अंकित किया गया है। रिपोर्ट में, आयोजित की गई संगोष्ठियों/सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सदस्यों और छात्रों से संबंधित सुसंगत आंकड़ों एवं वर्ष 2004-2005 के संस्थान के लेखाओं को भी समावेश किया है। जून, 2005 के अंत तक के आई.सी.ए.आई. के महत्वपूर्ण कार्यकलापों और प्रमुख पहलुओं का भी संक्षेप में वर्णन किया गया है।

1. परिषद्

उन्नीसवीं परिषद् का गठन तीन वर्ष के लिए 5 फरवरी, 2004 को किया गया। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 के निबंधनों के अनुसार परिषद् 30 सदस्यों से, 24 निर्वाचित सदस्य और 6 केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य, से मिलकर बनाई जानी चाहिये। वर्ष 2005-2006 वाली परिषद् की संरचना, जो 5 फरवरी, 2005 को प्रारंभ हुई, को अलग से दर्शाया गया है।

2. परिषद् की समितियाँ

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 5 फरवरी, 2005 को किया। तत्पश्चात् स्थानीय निकायों के लिये एक लेखाकर्म मानक समिति का गठन भी किया गया। 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 164 बैठकें आयोजित की गई, जबकि 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के दौरान 132 बैठकें की गई थीं।

3. संपरीक्षक

श्री शशी कुमार एफ.सी.ए. और श्री मनु चड्ढा, एफ. सी.ए. वर्ष 2004-05 के लिये आई.सी.ए.आई. के संयुक्त संपरीक्षक थे। परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है।

4. स्थायी समितियाँ

4.1 कार्य - समिति

यह समिति छात्रों / सदस्यों / फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनः स्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र के निर्गमन समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों / सदस्यों / फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल है, शाखाओं से सम्बद्ध विषयों, जिनमें नई-नई शाखाएं खोलना, नये चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों, लेखा रखने आदि विषयों पर भी यह समिति विचार करती है।

समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं :-

- आई.सी.ए.आई. के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्मों में नेटवर्क के संबंध में सी.ए. फर्मों के क्षमता पूरक उपाय, फर्मों का विलेयन और निर्विलेयन
 - व्यवसाय में चार्टर्ड एकाउंटेंटों को बीमा अभिकर्ता / सलाहकार / ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना (बीमा समिति की सिफारिश पर आधारित)
 - चार्टर्ड एकाउंटेंट की विलयित / विलयन फर्मों की विशिष्टताओं को अभिलिखित करना जिसके अंतर्गत विलयन फर्मों में जुड़ने वाले भागीदारों की तारीखें भी है।
 - छात्रों को ऐसे अन्य एस.ए.एफ.ए. सदस्य निकायों में अधिकतम तीन मास की अवधि तक आबद्ध परीक्षण लेने के लिए अनुज्ञात करना, जो अपने-अपने देश में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये पात्र है और ऐसे प्रशिक्षण को संबंधित कानून के आधीन सदस्य बनने के लिए छात्रों द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण के समतुल्य बनाना।
 - शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों को साधारण प्रबंध और संचार कौशल का पाठ्यक्रम करने के लिए रियायत प्रदान करना (अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर आधारित)
 - प्रथम बार फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये शर्त की छूट (अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर आधारित)
 - पी.ई.ई. के अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रीकरण / पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए साधारण / विशिष्ट शर्तों में छूट।
- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा पूर्ण किए गए / शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित से संबंधित हैं:-
- कार्यवाही में मारे गये सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों के बच्चों को ट्यूशन और रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय में छूट।
 - प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के संदेय विभिन्न अनुदानों का पुनरीक्षण और पुस्तकालय तथा वाचनालय अनुदान जारी करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पुनर्विलोकन।
 - नाइजीरिया में संस्थान का एक चैप्टर खोलना।
 - पश्चिमी क्षेत्र में वसई और थाणे में शाखाएं स्थापित करना।
 - चंडीगढ़, इन्दौर, सूरत, वडोदरा और एर्नाकुलम में विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित करना।
 - पश्चिमी क्षेत्र में पिम्परी में निर्देश पुस्तकालय स्थापित करना।
 - मध्यक्षेत्र में, गोरखपुर में निर्देश पुस्तकालय स्थापित करना।
 - संस्थान के सभी भवनों को 'आईसीएआई भवन' के रूप में नामित करना।
 - केन्द्रीय परिषद् समितियों, प्रादेशिक सीपीई समिति और

शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय तथा बढ़ती गतिविधियों के निष्पादन के लिये प्रादेशिक परिषदों में सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) प्रकोष्ठ की स्थापना।

- आईसीएआई के लिये सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिभूति नीति और संपरीक्षा का विकास।
- उद्योग में आईसीएआई के सदस्यों के लिये सर्वोत्तम सीएमडी / सीईओ/सीएओ के लिये वार्षिक पुरस्कारों का संस्थानीकरण।
- वृत्ति में शामिल होने वाले नए प्रवेशकों का स्वागत करने के लिए एक वर्ष में दो बार प्रादेशिक परिषद् स्तर पर प्रवेश समारोह आयोजित करना।
- सेक्टरों के कार्यकरण के लिये पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत।
- छात्र संबंधी शैक्षिक गतिविधियों के लिये शाखाओं का अनुदान जारी करना।

4.2 परीक्षा समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल, वृत्तिक शिक्षा—II और वृत्तिक शिक्षा—I परीक्षाएं नवम्बर, 2004 में दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त 94 शहरों में क्रमशः 143, 157 और 136 केन्द्रों पर आयोजित की गईं और मई 2005 में दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त 94 शहरों में क्रमशः 150, 163 और 151 केन्द्रों पर आयोजित की गईं।

नवम्बर, 2004 में आयोजित फाइनल, वृत्तिक शिक्षा—II और वृत्तिक शिक्षा—I परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 29427, 51057 और 14695 थी और मई 2005 में क्रमशः 30027, 49326 और 26508 थी।

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान जून, सितम्बर, दिसम्बर 2004 और मार्च और जून 2005 में सूचना पद्धति संपरीक्षा पर अर्हता पर पाठ्यक्रम निर्धारण परीक्षाएं भी आयोजित की गईं। साथ ही, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) और कर प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाओं के अलावा, जो मई 2005 में छात्रों की परीक्षाओं के साथ आयोजित की गईं, प्रबंध लेखाकर्म पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाएं मई, 2004 और नवम्बर 2004 में आयोजित की गईं। बीमा और जोखिम प्रबंध में अर्हता पर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवम्बर, 2004 और मई 2005 में हुआ।

अमरावती, जामनगर, सांगली और थाणे में नवम्बर 2004 की परीक्षाओं से तथा गुन्तूर, पिम्परी-चिंचवाड और श्रीगंगानगर में मई, 2005 की परीक्षाओं से नए परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रही:-

- ओ.एम.आर प्रारूप में परीक्षा आवेदन-पत्र जारी रखे गए और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिए गए जिनमें उनके स्केण्ड फोटो चित्र और नमूना हस्ताक्षर थे। इससे अभ्यर्थियों को अलग से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रही।
- परीक्षा आवेदन पत्र संस्थान के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं के अलावा, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराए गए। अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में उनके द्वारा बताए गए निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा को आगे बढ़ाया गया।
- परीक्षाफल संस्थान की आई.वी.आर. प्रणाली पर उपलब्ध रहेंगे। परीक्षाफल और अंकों को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट पर योग्यता सूची को भी परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही प्रदर्शित किया गया।
- परीक्षाफल और अंक वेबसाइट के अलावा दिल्ली और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर साथ-साथ उपलब्ध रहेंगे।
- संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं द्वारा परीक्षाफल और अंक डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही उपलब्ध कराई गई।
- स्वयं अभ्यर्थियों द्वारा उनके ओ.एम. आर./आई.सी.आर. परीक्षा फार्म में उपदर्शित निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके अंकों का विवरण ऑन लाईन मुद्रित करने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
- घोषणा होने पर, परीक्षा फल का पता लगाने के लिए अग्रिम अनुरोध दर्ज करने की सुविधा जारी रखी गई है और उसे दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा फल

की घोषणा के तुरंत बाद ई-मेल से उनके परीक्षाफल उपलब्ध कराए गए।

- नवम्बर, 2004 और मई, 2005 परीक्षाओं के दाखिला कार्ड के प्रश्नों को ई-मेल के द्वारा विद्यार्थियों तक बढ़ाया गया।
- नवम्बर 2004 के परिणाम एसएमएस तरीके से उपलब्ध कराए गए।
- नवम्बर, 2004 परीक्षा से वृत्तिक शिक्षा परीक्षा-I के छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र ऑन लाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई।
- परीक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कुछ विदेशी संस्थाओं को बराबर परामर्श दिया जाता रहा। नेपाल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने आई.सी.ए.आई. की निरंतर तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से जून, 2004 और नवम्बर, 2004 की फाउंडेशन और इण्टरमीडियट परीक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित कीं। श्रीलंका चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ने आई.सी.ए.आई. के तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से मार्च और जून 2004 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की।

4.3 अनुशासन समिति

यह समिति आई.सी.ए.आई. द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता का स्तर और मानक बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है। 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 की अवधि में उन सदस्यों के खिलाफ जिनके मामले प्रथम दृष्टया राय पर परिषद् द्वारा उसके पास भेजे गए हैं, अनुशासनिक जांच करने के अपने कृत संकल्प उत्तरदायित्व का निर्वाहन करने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर 20 दिन तक 13 अवसरों पर अपनी बैठकें की। वर्ष के दौरान, समिति ने 100 मामलों में अपनी जांच पूरी की। इसमें वे भी शामिल थे जो परिषद् द्वारा पूर्व वर्षों में भेजे गए थे।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक

आईसीएआई की परिषद् ने भारत में प्रयुक्त विभिन्न लेखांकन नीतियों और व्यवसायों को संगत बनाने की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 1977 में लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) की स्थापना की। अपनी स्थापना किए जाने के समय से ही

बोर्ड, लेखांकन मानक विकसित करके और उन मानकों के उपयोग के संवर्धन से देश में वित्तीय रिपोर्टिंग में समुच्चय गुणवत्ता संबंधी सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड ने अभी तक 29 लेखांकन मानक बनाए हैं। जिन्हें आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार से जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) और भारतीय लेखांकन मानक के बीच अंतर को कम करने के लिए आई एफ आर एस के तत्समानी, भारतीय लेखांकन मानकों पर कार्य पर प्रगति हुई है। इसके अलावा बोर्ड का एकमात्र उद्देश्य था लेखांकन मानक जारी करके भारतीय लेखांकन मानकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के मध्य अंतर को कम करना ही नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भारतीय लेखांकन व्यवसाय विभिन्न बिन्दुओं पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में हुए परिवर्तनों के अनुरूप हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड, समय-समय पर पुनरीक्षित लेखांकन मानक जारी करता रहता है, वर्तमान वर्षों में पुनरीक्षित मानक हैं - एएस 7, निर्माण संविदाएं, एएस 11, विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव और एएस 15, कर्मचारी फायदा इसके अलावा कतिपय अन्य विद्यमान लेखांकन मानक भी पुनरीक्षणाधीन हैं।

बोर्ड, नए/पुनरीक्षित लेखांकन मानकों के कारगर क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयत्नशील है। नए लेखांकन मानक जारी करने और विद्यमान मानकों के पुनरीक्षण से व्याख्या और मानकों में प्रतिपादित लेखांकन सिद्धांतों के लागू करने संबंधी कतिपय मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं। इन समस्याओं का समाधान करने और लेखांकन मानकों के कारगर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने लेखांकन मानक संबंधी मामलों पर लेखांकन मानक व्याख्या (एएसआई) तैयार करके अनेक क्रियात्मक कदम उठाए हैं। एएसआई की वही प्रस्थिति है जो कि सुसंगत लेखांकन मानक की। अभी तक नए लेखांकन मानकों को क्रियान्वित करने में उत्पन्न व्याख्या संबंधी अनेक जटिल बिन्दुओं पर 28 लेखांकन मानक व्याख्याएं जारी की गई हैं। इसके अलावा, इसने मानकों के कतिपय उपबंधों को स्पष्ट करते हुए अनेक उद्घोषणाएं भी की हैं। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने नए / पुनरीक्षित लेखांकन मानक जारी करने और जहां अपेक्षित हुआ, व्याख्या देने के अपने प्रयास जारी रखे। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:-

5.1.1 पुनरीक्षित लेखांकन मानक जारी किए गए।

लेखांकन मानक (एएस) 15 (2005 में पुनरीक्षित) कर्मचारी फायदा जारी किया गया है।

5.1.2 प्रस्तावित /पुनरीक्षित लेखांकन मानक व्याख्याओं के शीघ्र जारी किए जाने की संभावना।

बोर्ड ने, लेखांकन मानकों से उत्पन्न विभिन्न लेखांकन मामलों पर तीन लेखांकन मानक व्याख्याओं के प्रारूप को परिषद् के विचारार्थ अन्तिम रूप दे दिया है। इन नई / पुनरीक्षित व्याख्याओं के शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है एवं इससे यह सुनिश्चित होगा कि सुसंगत लेखांकन सिद्धांतों की व्याख्या इस रीति में हो कि वह सभी सम्बद्ध एककों को समान रूप से लागू हों। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मामलों पर भी व्याख्याएं तैयार की जा रही हैं।

5.1.3 लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को लेखांकन मानक लागू होना

लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को लेखांकन मानक लागू करने के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, गत वर्ष के दौरान बोर्ड ने लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों प्रकटन अपेक्षाओं से छूट देने का उपबंध करने के लिए विनिर्देश किया था। संस्थापन की परिषद् ने लेखांकन मानकों में अंतर्विष्ट पहचान और माप सिद्धांतों से, जहां समुचित हो लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को छूट/रियायत देने के संबंध में अपनी अनुदेशात्मक मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए जहां लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमों को पहचान और या माप सिद्धांतों से छूट/रियायत दी जा सके, सभी लेखांकन मानकों की जांच हेतु एक अध्ययन समूह गठित किया है।

5.1.4 लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण

ए.एस.बी. ने ऐसे मामलों में कतिपय लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण भी किया है। जहां यह महसूस किया गया है कि अंतर्वलिप्त मामलों और बहुत से रुचिबद्ध समूहों से प्राप्त जानकारी के संबंध में परिवर्तित सोच को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित स्थिति अधिक समुचित है। लेखांकन मानक एएस 26 अमूर्त आस्तियां का सीमित पुनरीक्षण किया गया है।

5.1.5 उद्घोषणाएं जारी करना।

सदस्यों और अन्य के द्वारा उठाए गए स्पष्टीकारक प्रकृति के मामलों पर विचार करने की दृष्टि से ए.एस.बी. ने विभिन्न लेखांकन मानकों से उत्पन्न लेखांकन मामलों पर उद्घोषणाएं जारी की हैं। इसके अलावा, कतिपय लेखांकन मामलों पर उद्घोषणाएं तैयार की जा रही हैं और शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी।

5.1.6 अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर प्रतिक्रिया

बोर्ड ने लेखांकन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने

वाले विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आई.ए.एस.बी.) द्वारा जारी विभिन्न अपावरण प्रारूपों पर टिप्पणियां देना, आई.ए.एस.बी. द्वारा जारी नए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर प्रोजेक्ट लेना, आई.ए.एस.बी. द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों में किए गए पुनरीक्षणों पर विचार करना, ताकि उन पुनरीक्षणों को भारतीय लेखांकन मानकों में लागू करने पर विचार किया जा सके, शामिल हैं।

5.1.7 लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) से विचार-विमर्श

बोर्ड ने लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा प्रस्तुत अनेक सुझावों पर विचार किया और इन सुझावों का निपटारा समुचित रीति में किया।

5.1.8 विनियामक निकायों के साथ विचार-विमर्श

बोर्ड ने समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) जैसे विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट अनेक लेखांकन मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक महत्वपूर्ण मामला यह था कि आर.बी.आई. ने अपने परिपत्रों से पुनरीक्षित लेखांकन मानक एएस 11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव को बैंकों से अपनाए जाने की अपेक्षा की थी।

5.1.9. प्रगति में परियोजनाएं

अनेक परियोजनाओं में, विशेषतः, वित्तीय लिखतों, मूर्त स्थिर आस्तियों और वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण के लिए लेखांकन के संबंध में प्रयाप्त प्रगति हुई है।

5.1.10 लेखांकन मानकों का सार संग्रह

1. जुलाई, 2005 तक के लेखांकन मानकों के सार संग्रह का अद्यतन संस्करण तैयार किया जा रहा है और इसे सी.डी. के साथ शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

5.1.11 बोर्ड द्वारा ली गई नई परियोजनाएं

बोर्ड ने आईएएस - 40 निवेश संपत्ति के तत्सामनी निवेश संपत्ति पर लेखांकन मानक तैयार करने के लिए एक नई परियोजना ली है।

5.2 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

किसी वृत्ति की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर

करती है कि पूरा समाज उसमें कितना विश्वास व्यक्त करता है। समाज की आशाओं पर पूरा उतरने की किसी भी वृत्ति की पूर्व अपेक्षा यह है कि वृत्ति को उस वातावरण में जिसमें यह कार्य करती है होने वाले अद्यतन विकास से परिचित और क्रियात्मक रूप से उन्हें क्रियान्वित करने में सक्षम होना चाहिए। समाज की आशाओं को पूरा करने के लिए आईसीएआई ने हमेशा देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आसपास के गतिशील, तकनीकी, विधायी, आर्थिक वातावरण को समझने में कारगर और समयबद्ध कदम उठाए हैं। आईसीएआई ने अन्य समितियों और बोर्ड के अलावा संपरीक्षा आश्वासन मानक बोर्ड (ए.ए.एस.बी.) स्थापित किया है। ए.ए.एस.बी. का गठन एक अस्थाई समिति के रूप में सितंबर 1982 में आईसीएआई के एक तकनीकी भाग के रूप में किया गया था।

5.2.1 मिशन और उद्देश्य

बोर्ड का सर्वप्रथम मिशन भारत में विद्यमान संपरीक्षा प्रेक्टिसों का पुनरीक्षण और संपरीक्षा तथा आश्वासन मानक जारी करना रहा है। संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रेक्टिसों के संहिताबद्ध होने का प्रतिनिधित्व करता है। ए.ए.एस.बी. संपरीक्षा से जुड़े मुद्दों पर, चाहे वे साधारण प्रकृति के हों या उद्योग विशिष्ट, मार्गदर्शक टिप्पण भी तैयार करता है। हाल ही में ए.ए.एस.बी. ने संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने का कार्य भी प्रारंभ किया है। आज की तारीख में ए.ए.एस.बी. के पास तीन विवरण, चौतीस संपरीक्षा तथा आश्वासन मानक और चालीस मार्गदर्शक टिप्पण हैं जिनमें चार उद्योग विशिष्ट मार्गदर्शक टिप्पण हैं।

5.2.2 कम्पनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर वक्तव्य।

आईसीएआई ने वर्ष 2003 में बेहतर तालमेल के साथ सदस्यों की सहायता करने की दृष्टि और कम्पनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के समुचित रूप में पूरा करने के लिए कम्पनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर वक्तव्य निकाला। तथापि, आधारीक वास्तविकताओं को समझने और व्यावहारिक क्रियान्वयन में अंतर्वर्तित कठिनायियों और जटिलताओं का समाधान करने के लिए एवं आदेश की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु ए.ए.एस.बी. ने सीएआरओ, 2003 पर संस्थान के सदस्यों के विचार और राय जानने के लिए उनसे संपर्क करने की पहल की। सदस्यों से सीएआरओ से उत्पन्न होने वाले ऐसे मुद्दों पर दृष्टिकोण / राय भेजने की अपेक्षा की गई थी, जो उनकी राय में सीएआरओ, 2003 पर कथन के अलावा और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

कम्पनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 पर मुद्दों का प्रकाशन

सीएआरओ, 2003 पर सदस्यों से प्राप्त पुनर्निवेशन का खंड प्रतिखण्ड संकलन है और उन मुद्दों पर ए.ए.एस.बी. की सुविचारित प्रतिक्रिया तैयार निर्देशन हस्तपुस्तिका के रूप में है।

5.2.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक

वर्ष के दौरान ए.ए.एस.बी. ने दो संपरीक्षा और आश्वासन मानक निकाले हैं, अर्थात:-

- संपरीक्षा और आश्वासन मानक (ए.ए.एस.) 33 - वित्तीय विवरण पुनर्विलोक के लिए नियोजन,
- संपरीक्षा और आश्वासन मानक (ए.ए.एस.) 34 - संपरीक्षा साक्ष्य - विनिर्दिष्ट मदों के लिए अतिरिक्त विचारण।

5.2.4 मार्ग दर्शक टिप्पण

- बैंकों की संपरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण (पुनरीक्षित)

मार्च, 2005 में ए.ए.एस.बी. ने बैंकों की संपरीक्षा पर पूर्णतया पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत का अंक जारी किया है। यह अंक 2001 में निकाले गये अंक तथा 2003 में निकले इसके परिपूरक को अद्यतन करके निकाला गया है। मार्गदर्शक टिप्पण के पूर्व अंक को बैंक उद्योग कार्यकरण को प्रभावित करने वाली अनेक गतिविधियों और परिणाम स्वरूप आय-पहचान आस्ति वर्गीकरण, उपबंधन और निवेश मूल्यांकन, ऋण पर निर्बंधक और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में विवेकी मार्गदर्शक सिद्धांतों की बाबत आरबीआई के नए/ पुनरीक्षित परिपत्र जारी करने जैसे बैंकों के संपरीक्षक के फलस्वरूप पुनरीक्षित किया गया था।

पुनरीक्षित मार्ग दर्शक टिप्पण के बैंकिंग सैक्टर में सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शक सिद्धांत और बेसल -II सिफारिशें अंकित हैं यह 2003 के परिपूरक के बाद बैंकों को जारी किए गए अनेक लेखांकन मानक के लागू करने के पहलू और बैंकों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन पर एन डी गुप्ता समिति की रिपोर्ट की विवताओं से भी संबंधित है। "अपने ग्राहक को जाने" मार्गदर्शक सिद्धांत से संबंधित आरबीआई के परिपत्रों पर भी मार्गदर्शक टिप्पण में विचार किया गया है।

- धारा 227 (3) (ड) और (च) पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण (निदेशक नियमों की निरर्हताओं के अनुसरण में)

वर्ष 2001 में ए.ए.एस.बी. ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3) (ड) और (च) पर मार्गदर्शक टिप्पणी जारी किया था। मार्गदर्शक सिद्धांत का उद्देश्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (3) के खण्ड (ड) और (च) की बाबत वृत्तिक दायित्वों के निर्वहन में सदस्यों की सहायता

करना था।

वर्ष के दौरान ए.ए.एस.बी. ने तत्कालीन कंपनी विभाग द्वारा संपरीक्षक के रूप में सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों पर जारी कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) के अधीन निदेशकों की निरर्हता) नियम, 2003 की विवक्षाओं को समुचित रूप में समझने में उनकी सहायता करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3) (ड) और (च) पर पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण निकाला है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षित मार्गदर्शक टिप्पण अन्य नियमों की भी पूरी जानकारी देता है जो यद्यपि उपरोक्त नियमों में उल्लिखित नहीं हैं किन्तु उनका संपरीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन में महत्वपूर्ण स्थान है।

5.2.5 धनशोधन पर अध्ययन : एक लेखाकर का परिप्रेक्ष्य—ए.ए.एस.बी. ने संस्थान के सदस्यों को शिक्षित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए और अर्थव्यवस्था से धनशोधन को उखाड़, फेंकने में समर्थ बनाने के लिए 'ए स्टडी ऑन मनी लॉडरिंग, एन अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव' के शीर्षक से अपने तत्वावधान में एक प्रकाशन निकाला है। यह पुस्तक धन शोधन के अनेक आलोचनात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करती है जिससे कि उन्हें संकल्पना को बेहतर तौर पर समझने में सहायता मिले और अपने अनुभवों का उचित दिशा में प्रयोग कर सकें।

अध्ययन धनशोधन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहलों की चर्चा करता है जिसके अंतर्गत ओईसीडी के वित्तीय कार्यवाही की टास्क फोर्स की 40 सिफारिशें, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिये बैंक की बेसल समिति की ग्राहक सम्यक् तत्परता मार्गदर्शक सिद्धांत आदि हैं। भारतीय पहलों पर चर्चा करते हुए, अध्ययन में धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के कतिपय महत्वपूर्ण उपबंधों तथा वाणिज्य बैंकों एवं गैरबैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक को जानें मार्गदर्शक सिद्धांतों की प्रमुख अपेक्षाओं पर भी चर्चा की गई है। धनशोधन के संबंध में इसमें एक्सटर्नल संपरीक्षकों के कर्तव्यों और दायित्वों पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

5.2.6 संपरीक्षा उद्घोषणा हस्त पुस्तिका

ए.एस.एस.बी. ने संपरीक्षा उद्घोषणा की एक पुनरीक्षित हस्तपुस्तिका भी निकाली जिसमें संपरीक्षा पर विवरण का पाठ, संपरीक्षा और आश्वासन मानक और संपरीक्षा पर 1 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त साधारण मार्गदर्शक टिप्पण अंतर्विष्ट हैं। हस्तपुस्तिका में अपजल्लिखित के अब तक के पाठ वाली काम्पैक्ट डिस्क (सी.डी.) भी है।

5.2.7 कंपनी विधि पर डा. जे.जे. ईरानी समिति की रिपोर्ट

भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 के पुनरीक्षण से उत्पन्न होने वाले अनेक मुद्दों पर सिफारिश करने और पणधारियां एवं लघुनिवेशकों सहित निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए डा. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में 2 दिसंबर 2004 को कंपनी विधि पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। ए.ए.एस.बी. ने कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी विधि पर संकल्पना पत्र के विश्लेषण, जहां तक वह कंपनियों की संपरीक्षा और संपरीक्षकों से संबंधित था, कर अपना योगदान दिया तथा यू.एस.ए., यू.के., आस्ट्रेलिया और कनाडा में तुलनात्मक स्थिति के विस्तृत विश्लेषण की रिपोर्ट भी तैयार की थी। ए.ए.एस.बी. सचिवालय द्वारा किए गए विश्लेषण और टिप्पणियां, ईरानी समिति के समक्ष आईसीएआई द्वारा प्रस्तुतिकरण, का भाग रूप थी। 30 मई, 2005 को जारी कंपनी विधि पर डा.जे.जे. ईरानी की रिपोर्ट में आईसीएआई की सिफारिशों /टिप्पणियों को स्थान प्राप्त हुआ।

5.2.8 अन्य क्रियाकलाप

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

गत वर्ष ए.ए.एस.बी. ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक सामान्य प्लेटफार्म से विचार करने के लिए तथा संपरीक्षा और बीमा उद्योग से संबंधित अन्य सुसंगत मुद्दों पर राय बांटने की दृष्टि से आई.आर.डी.ए. के साथ काम करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की थी। ए.ए.एस.बी. के प्रतिनिधियों ने आई.आर.डी.ए. के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की तथा बीमा कंपनियों के मामले में, बैंकों को लागू रीति के अनुसार दीर्घ फार्म संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह गठित किया गया है। अध्ययन समूह ने बीमा कंपनियों के लिए एक दीर्घ फार्म संपरीक्षा रिपोर्ट प्रारूप विकसित कर लिया है।

5.2.9 प्रगति में परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा ए.ए.एस.बी. ने बहुत सी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखाकर परिसंघ (आईएफएसी) द्वारा जारी संपरीक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने के लिए विद्यमान संपरीक्षा और आश्वासन मानक निकालना पुनरीक्षण, संपरीक्षा आदि के क्षेत्र में उभरते अनेक मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करना। ए.ए.एस.बी. ने पूर्व में जारी अनेक मार्ग दर्शक टिप्पणों के पुनरीक्षण और इस प्रयोजन के लिए इसके द्वारा पहचान गए सुसंगत नए विषयों पर मार्ग दर्शक टिप्पण बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

5.3 अनुसंधान

अनुसंधान समिति संस्थान के सदस्यों को उनके वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में मार्गदर्शन और प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य में वृद्धि प्रदान करने की दृष्टि से मार्गदर्शक टिप्पणों, अनुसंधान अध्ययन, विनिर्दिष्ट उद्योगों में लेखांकन और संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांतों, के रूप में अनेक प्रकाशन निकालती हैं। यह वर्तमान और निरंतर आधार पर अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं पर भी कार्य करती हैं एवं और ऐसे अनेक लेखांकन मामलों पर अम्यावेदन तैयार करती हैं जिससे वृत्ति प्रभावित हो और जो अनुसंधान की परिधि में आते हैं। वर्ष के दौरान, समिति ने चार मार्गदर्शक टिप्पण तैयार किए हैं अर्थात् राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण, कर्मचारी अंशधारित संदाय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण, सीमांत फायदा कर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण और विद्यालयों द्वारा लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण जिन्हें संस्थान की परिषद् के प्राधिकार से जारी किया गया है।

राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण वेट के लिए सुदृढ़ लेखांकन सिद्धांतों की सिफारिश करने की दृष्टि से निकाला गया है। कतिपय राज्यों में वेट स्कीम प्रारंभ होने के साथ ही साथ मार्गदर्शक टिप्पण जारी किए जाने व्यवहारी सामयिक आधार पर समुचित लेखांकन प्रणाली विकसित करने में समर्थ हुए हैं और इससे देश भर में वेट का एकसमान लेखांकन सुनिश्चित हुआ है। कर्मचारी अंश आधारित संदाय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कर्मचारी स्टॉक क्रम योजना और व्यापक रूप से किसी उद्यम के अंश की कीमतों पर आधारित कर्मचारियों को संदाय की वैसी ही अन्य योजनाओं से संबंधित हैं, मार्गदर्शक टिप्पण यह पहचान करता है कि कर्मचारी अंश आधारित संदाय के लिए लेखांकन की दो रीतियां हैं अर्थात् उचित मूल्य रीति या मूलभूत रीति और उद्यम को इनमें से कोई एक रीति का प्रयोग ऐसे संदायों के लेखांकन के लिए करना अनुज्ञात करता है।

वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में सीमांत फायदों पर आयकर का एक नया अध्याय 12 अ जोड़ा गया है। सीमांत फायदा कर प्रारम्भ किए जाने से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति पर इस दायित्व का भार भी आ गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिए सीमांत फायदा कर हेतु समुचित लेखांकन करें। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमांत फायदा कर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक टिप्पण निकाला गया है जो सीमांत फायदा कर के लिए लेखांकन से और विशेषतः वित्तीय विवरणों में सीमांत फायदा कर की पहचान और उसकी प्रस्तुति से संबंधित हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जिसे वर्ष के दौरान

समिति की पूर्विकता प्राप्त रही, विद्यालयों द्वारा लेखांकन है। एक रूपता लाने के उद्देश्य से और विद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धति में सुधार लाने के लिए विद्यालयों द्वारा लेखांकन पर एक मार्गदर्शक टिप्पण निकाला गया है। इस मार्गदर्शक टिप्पण का उद्देश्य है कि निधि आधारित लेखांकन सहित विद्यालयों में अपनाई जा रही अनेक लेखांकन प्रक्रियाओं को संगत बनाया जाए तथा आय और व्यय लेखा एवं तुलन पत्र के एक समान आरूपों की सिफारिश की जाए।

उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान को ध्यान में रखते हुए समिति ने आवास वित्त कंपनियों में लेखांकन और संपरीक्षण पर तकनीकी गाइड निकाली है। तकनीकी गाइड आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कृत्यों, एचएफसी को पेश प्रमुख संकट, एचएफसी के अन्य सुसंगत विनियामक पहलुओं के साथ इन्हें लागू कानूनों पर चर्चा करती है। इनमें ऐसे अनेक लेखांकन और संपरीक्षा पहलुओं पर चर्चा की गई है जो आवास वित्त कंपनी की संपरीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं।

वर्ष के दौरान समिति ने दरों के अवमूल्यन अवधारित करने के प्रयोजन के लिये तेल और गैस पाइपलाइनों के उपयोगी जीवन पर भी एक अध्ययन किया है। अध्ययन का उद्देश्य भारत में तेल और गैस कंपनियों द्वारा उपयोग की जा रही पाइप लाइनों के लिए सही और उचित अवमूल्यन निकालने के आधारों पर विचार करना है। जिसमें पाइपलाइनों के उपयोगी जीवन के लिए अपेक्षित तथ्य भी शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्ट में, जानकारी के प्रस्तुतिकरण में वृहत्तर मानकों के संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए, आईसीएआई अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आई.सी.ए.आई. पुरस्कार हेतु वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करता है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रतियोगिता का उद्देश्य किसी उद्यम की वार्षिक रिपोर्ट को ऐसा बेहतर संचार औजार बनाना है जो उद्यम के बारे में इसके पणधारियों के लिए सही और उचित वित्तीय सूचना प्रदान करें। वर्ष 2003-2004 के लिए प्रतियोगिता तीन प्रवर्गों में आयोजित की गई। प्रवर्ग 1 में गैर वित्तीय सार्वजनिक और निजी सैक्टर के उद्यम शामिल थे; प्रवर्ग 2 में सार्वजनिक, निजी और सहकारी सैक्टर की वित्तीय संस्थाएं शामिल थी; जैसे बैंक, बीमा कंपनियां, एन.बी.एफ.सी.आदि; एवं प्रवर्ग 3 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं तथा न्यासों सहित लाभहीन संगठन शामिल थे। वर्ष 2003-04 की प्रतियोगिता में गैर-वित्तीय सार्वजनिक और निजी सैक्टर उद्यमों से, वित्तीय संस्थाओं और लाभ ही संगठनों आदि से 125 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। गैर वित्तीय सार्वजनिक और निजी सैक्टर उद्यम प्रवर्ग में प्राप्त प्रविष्टियों में से मैसर्स इन्फोसिस टेक्नोलोजीज लि. की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं (वर्ष 2003-04 के लिए)

को सर्वोत्तम न्यायनिर्णीत किया गया और तदनुसार उस कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए रजत शील्ड से पुरस्कृत किया गया। वित्तीय संस्थाओं और लाभ हीन संगठनों के प्रवर्गों में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए रजत शील्ड क्रमशः आवास विकास वित्त निगम लि. (एचडीएफसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) को पुरस्कृत किया गया। भाग लेने वाले उद्यमों में ऐसे उद्यमों को, जिनकी वार्षिक रिपोर्ट और लेखा दूसरे नम्बर पर रहे, अत्यंत सराहनीय वित्तीय रिपोर्ट के लिए ताम्र प्लेक से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2003-04 के लिए ताम्र प्लेक पाने वालों में गैर वित्तीय सार्वजनिक और निजी सैक्टर उद्यमों के प्रवर्ग में साइमन लि. और टाटा कैमिकल्स लि. थे जबकि वित्तीय संस्थाओं के अधीन कोलामेंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड एवं लाभ हीन संगठनों के प्रवर्ग के अधीन फाइनेशियल मैनेजमेंट सर्विस फाउंडेशन थे। उपरोक्त पुरस्कार पाने वालों का चयन भाग लेने वाले उद्यमों के 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 (दोनों दिन शामिल) के बीच किसी भी दिन समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपनाई गई लेखांकन रीति के पुनर्विलोकन पर, उनकी वित्तीय स्थिति और प्रचालन प्रदर्शन पर ध्यान दिए बिना आई.सी.ए.आई. द्वारा नियुक्त जजों के पैनल द्वारा किया गया। 18 जुलाई 2005 को अशोक होटल नई दिल्ली में आयोजित आईसीएआई के एक विशेष समारोह में वर्ष 2003-04 के लिए "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" महामहिम ले.ज.(सेवा निवृत्त) एस.के. सिन्हा, पीवीएसएम, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा दिए गए। माननीय श्री प्रेमचन्द गुप्ता, केन्द्रीय कंपनी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

5.4 निगमित विधियां

वर्ष 2004-05 उपलब्धियों का वर्ष था। समिति द्वारा प्रारंभ की गई अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई। समिति ने डा. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में कंपनी विधि पर विशेषज्ञ समिति के विचार-विमर्श में भाग लिया और 'अकाउंट्स एण्ड ऑडिट', 'माइनारिटी इन्टरेस्ट' और 'इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन' से संबंधित चेप्टरों में प्रस्तुतियां कीं। अधिकतर सुझावों को स्वीकारते हुए उन्हें जे.जे. ईरानी समिति की रिपोर्ट का भाग बनाया गया। समिति ने कंपनी कार्यमंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों द्वारा आईसीएआई को निर्दिष्ट अनेक मामलों पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे:- एमसीए-21 परियोजनाएं, मृत कंपनियों पर आसान निकास स्कीम, 2005, कंपनी विधि पर संकल्पना पत्र, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 का संशोधन, सीमांतदायित्व भागीदारी विधेयक, निरीक्षण मेनुअल और अभियोजन मेनुअल, निगमित शासन के यूएनसीटीडी ओईसीडी सिद्धांत, भारत के निगमित शासन के मानकों और संहिता के अनुपालन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट और भारतीय प्रतियोगिता आयोग के विनियम

बनाना। वर्ष के दौरान समिति ने माध्यस्थ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सदस्यों का विशेषज्ञता प्रतियोगिता बढ़त और वृत्तिक उत्कृष्टता से लैस करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं समिति ने निगमित और सहबद्ध विधियों से संबंधित तत्समानी विषयों पर अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया। समिति ने मुंबई, कोलकता, नई दिल्ली और चैन्नई में वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी विधि सेवा के पदाधिकारियों के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया।

5.5 राजकोषीय विधियां

राजकोषीय समिति ने दूसरा बजटोत्तर, 2004 मई 2004 में प्रस्तुत किया। यह नई सरकार द्वारा बजट प्रस्तुतीकरण की पूर्व संध्या पर किया गया। आईसीएआई के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधि मंडल ने माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री पी.चिदम्बरम से 12 अगस्त, 2004 को भेंट करके उन्हें बजटोत्तर ज्ञापन 2004 प्रस्तुत किया। आईसीएआई के प्रतिनिधि ने श्री डीपी सेन गुप्ता, संयुक्त सचिव (टीपीएल-1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से भेंट करके उन्हें बजटोत्तर ज्ञापन, 2004 की विशेषताओं से अवगत कराया। समिति ने पूर्व बजट ज्ञापन, 2005 को प्रस्तुत किया था एवं यह वर्ष का विषय है कि आईसीएआई के प्रमुख सुझावों में से छः सुझाव स्वीकार किए गए और उन्हें वित्त विधेयक, 2005 में सम्मिलित किया गया। तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार को बजटोत्तर ज्ञापन, 2005 जिसमें सीमांत फायदा कर और बैंकिंग नकद संव्यवहार कर के उपबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण अंतर्विष्ट था, प्रस्तुत किया गया सीबीडीटी ने सीमांत फायदा कर से संबंधित उपबंधों का पुनर्विलोकन करने के लिए एक पैनल गठित किया। माननीय वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2005 के पारित होते समय आईसीएआई द्वारा दिए बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

समिति ने सीबीडीटी को बहुत से अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जिनमें से आकर अधिनियम 1961 की धारा 277 (क) के उपबंधों में उपांतरण के लिए अभ्यावेदन और राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004 पर अभ्यावेदन थे। राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004 के संदर्भ में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। तत्पश्चात, स्थाई समिति के अध्यक्ष की अपेक्षानुसार ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतिकरण से उत्पन्न मुद्दों पर एक विस्तृत अनुरोध प्रस्तुत किया गया था।

समिति ने बजट, 2004 देखने के लिए विशेष प्रबंध किए थे, जिसके बाद पत्रिका का एक विशेष अंक निकाला गया था जिसमें वित्त विधेयक, 2004 के उपबंधों का स्पष्टीकरण करते

हुए देश भर के विख्यात सदस्यों के लेख प्रकाशित हुए थे। एसएएफए समिति की ओर से एसएएफए देशों में वेट के अध्ययन को अंतिम रूप दिया गया था। इस अध्ययन से एसएएफए देशों में प्रचलित वेट प्रणाली का अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। चार्टर्ड अक्काउंटेंट और भारत के संदर्भ में कराधान सेवाएं विषय पर एक पृष्ठभूमि पत्र आईएफएसी बोर्ड के विचारार्थ तैयार किया गया था। अनिवासियों के कराधान के बदले हुए महत्त्व को समझने के पश्चात् समिति ने अनिवासियों के कराधान पर एक प्रकाशन निकाला है जो व्यापक रूप से अनिवासियों के कराधान की बाबत कानूनी और न्यायिक मुद्दों से संबंधित हैं आय कर अपील अधिकरण के सदस्यों के साथ पारस्परिक चर्चा सत्र करने के प्रयोजन के लिए लेखांकन और कराधान पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की गई थी।

भारत संघ के अधिकतर राज्यों में 1 अप्रैल, 2005 से राज्य स्तरीय वेट प्रणाली प्रारंभ हो गई है। समिति ने अनेक क्रियात्मक उपाय किए थे। जिससे आईसीएआई इस ऐतिहासिक सुधार को क्रियान्वित करने में सरकार की सहायता करने से सबसे आगे रहा। आईसीएआई द्वारा प्रकाशित राज्य स्तरीय वेट के लिए लेखांकन पर टिप्पण डा. असिम दासगुप्ता संयोजक राज्य वित्त मंत्री सशक्त समिति द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। मॉडल वेट संपरीक्षा रिपोर्ट सशक्त समिति के सदस्य सचिव श्री रमेश चन्द्र को प्रस्तुत की गई जिन्होंने आईसीएआई द्वारा की गई पहल को अत्यंत सराहा। मॉडल वेट संपरीक्षा रिपोर्ट सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी वेट के लिए संपरीक्षा उपबंध अधिनियमित करते समय समुचित विचारार्थ प्रेषित की गई। समिति ने सतत वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ मिलकर एक प्रमुख प्रकाशन स्टेट लेवन वेट इन इण्डिया - ए स्टडी निकाला।

समिति ने आयकर अधिनियम के अधीन कर संपरीक्षा के संबंध में भारत लागत तथा सकर्म लेखाकार संस्थान के अभ्यावेदन पर आईसीएआई के दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए एक विस्तृत उत्तर कंपनी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया है। समिति के अध्यक्ष ने इलेक्ट्रानिक फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम स्कीम, 2004 से संबंधित मानीटरिंग समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उप-समूह के विनियमों को लोकप्रिय बनाने के लिए समिति के अध्यक्ष ने पैन पर सशक्त समिति के उप-समूह में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया। समिति ने अपने सुझाव काले धन और आस्तियों पर सीबीडीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह को प्रस्तुत किए।

रिपोर्टाधीन वर्ष दौरान, विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। नागपुर में राजकोषीय और निगमित विधि संबंधी अखिल भारत सम्मेलन, चैन्नई में कर संधि संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार, इंदौर में राजकोषीय विधि संबंधी

सम्मेलन और अनेक अन्य सम्मेलन हुये था।

5.6 वित्तीय बाजार और निवेशकर्ता संरक्षण

वित्तीय बाजार में सुधारों के सिलसिले की दृष्टि से, भारत के निवेश के लिए एक संभावित स्थान के रूप में देखा जाता है तथा सरकार और विनियामक देश को विश्वस्तरीय पर एक स्थान दिलाने के लिए चारों तरफ से प्रयास किए गए हैं। सरकार रिटेल व्यक्ति निवेशकर्ता द्वारा कायम भागीदारी प्रदान करने के लिए विभिन्न बजट संबंधी/ कानूनी उपाय आरंभ कर रही हैं तथा भारतीय स्टॉक बाजार में उदारीकृत तथा वृहत विदेशी विनिवेश को बढ़ावा दे रही हैं। वर्तमान विकास की प्रवृत्ति तथा दशा और भविष्यकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समिति ने, वर्ष 2005 के लिए कार्रवाई की अंतिम रूपरेखा योजना पर अपना ध्यान दिया है तथा क्रमबद्ध रीति से उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है।

प्रारंभिक बाजार, गौण बाजार, म्यूचुअल निधि, प्रकटीकरण अपेक्षाएं, निगमित शासन तथा निवेशकर्ता संरक्षण से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञता तथा जानकारी को बांटने के लिए विनियामक प्राधिकारियों (अर्थात्, सेबी और एमसीए) के बीच बातचीत जारी है तथा वर्ष के दौरान निवेशकर्ता जागरूकता कार्यक्रम को पूर्विकता दी गई है। कार्रवाई योजना की वारतविक उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए, पहले चरण के दौरान की गई महत्वपूर्ण पहल तथा की गई उपलब्धियां निम्नलिखित थीं:

- बाजार और निवेशकर्ता: समिति ने बजट 2005 की उद्घोषणा की पूर्व संध्या पर निवेशकर्ताओं के लिए कार्यक्रम की अपनी श्रृंखला का आयोजन किया। दीर्घकालीन पूंजीबाजार के लिए एफआईआई विषय पर 7 मार्च, 2005 को मुम्बई में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। सुविधात पूंजी बाजार विशेषज्ञ तथा निवेश सलाहकारों ने कार्यक्रम को संबोधित किया तथा साधारण जनता ने बड़ चढ़कर इसमें भाग लिया।
- सीए और आईपीओ - बाजार में प्रारंभिक जनता के प्रस्ताव के पुर्नउत्थान को ध्यान में रखते हुए, समिति ने 21 मई, 2005 को मुम्बई में आईपीओ संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसी ही कार्यक्रम 25 जून, 2005 को नागपुर में किया गया था।
- लघु निवेशकर्ताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी: समिति ने 22 और 23 मार्च, 2005 को मुम्बई में निवेशकर्ता शिकायत फोरम ने आयोजित उक्त सम्मेलन में भाग लिया।

- कंपनी विधि संबंधी विशेषज्ञ समिति के विचार-विमर्श में भागीदारी: निवेशकर्ता संरक्षक तथा अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित विषयों पर समिति ने 28 मार्च और 6 और 7 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में कंपनी विधि संबंधी डॉ. जे.जे. ईरानी समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
- सेबी और अन्य विनियामकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय 7 अप्रैल, 2005 को समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन सेबी के पूर्वकालिक सदस्य श्री जी. अनंतरमन से मिले और विभिन्न विषयों जिसमें पूंजी बाजार के क्षेत्र में सेबी को आईसीएआई की सहायता तथा विशेषज्ञता देना भी सम्मिलित है, पर विचार विमर्श किया समिति के अध्यक्ष ने निवेशकर्ता संरक्षण के लिए विभिन्न परिणियमों में उपयुक्त उपबंधों को सुनिश्चित करने की संभाव्यताओं पर श्री भगवत स्वरूप, सदस्य, आयकर समझौता आयोग, नई दिल्ली के साथ परस्पर विचार विमर्श किया था।
- स्वतंत्र निवेशकों संबंधी प्रशिक्षण: कार्यक्रम सूचीबद्ध कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक बोर्ड के लिए आज्ञापक अपेक्षा विनिर्दिष्ट करने वाले वर्तमान सूची बद्ध करने की अपेक्षाओं के साथ तथा संभावित अवसरों को तलाशने में वृत्तिकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से, समिति ने विभिन्न मेट्रो शहरों में स्वतंत्र निदेशकों के लिए निगमित तथा सहबद्ध विधि समितियों के साथ संयुक्त रूप से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समिति की कार्यवाई योजना को प्रारंभ करने के लिए, अगस्त, 2005 को क्रमशः मुम्बई और ऊंटी में पहले दो प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए।
- भावीयुक्ति: धन संबंधी युक्ति धन संबंधी युक्ति पर अखिल भारतीय टीवी विजय कार्यक्रम का विचार किया गया है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पद्धतियों पर कार्य चल रहा है।
- प्रकाशन — (i) निवेशकर्ता संरक्षण संबंधी बुकलेट — दस्तावेज का मूल प्रारूप इस समय समिति के विचाराधीन और (ii) खण्ड 49 संबंधी पुनरीक्षित मार्गदर्शन टिप्पण: दस्तावेज का मूल प्रारूप इस समय समिति के विचाराधीन है।

5.7 विशेषज्ञ राय

लेखांकन या और संपरीक्षा के सिद्धांतों और संबंध क्षेत्रों वाले विषयों पर संस्थान से सदस्यों की आशंकाओं का उत्तर देने के उद्देश्य से आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तथापि, आशंकाओं में विभिन्न तथा वृत्तिक कदाचार का मामला अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन सम्मिलित होता है। तथा उन आशंकाओं पर चिंता व्यक्त की जाती है जो संस्थान की अनुशासनिक समिति या सरकार के समुचित विभाग या आयकर प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हो और जिनका उत्तर समिति ने नहीं दिया है।

मानक लेखांकन पद्धति के निरंतर विकास तथा बढ़ते हुए महत्त्व के युग में, चार्टर्ड लेखांदार की वृत्ति के सदस्य बेहतर कौशल तथा सक्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इस प्रक्रिया में वे कुछ समय उस विलक्षण स्थिति की सामना करते हैं; जहां विभिन्न लेखांकन और संपरीक्षा मानकों को लागू करना कठिन हो जाता है लेखांकन और संपरीक्षा मानकों द्वारा तैयार सारभाग संकल्पनाओं के उच्च स्तर की वृत्तिक विशेषज्ञता के साथ प्रत्येक विशिष्ट मामले में निर्वचन और उनको लागू किया जाता है। समिति जटिल परिस्थिति में सदस्यों को सलाह देती है और उनका मार्गदर्शन करती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति ने व्यापक प्रकार के विषयों से संबंधित 57 राय को अंतिम रूप दिया जोकि हीरों की सामान सूची का मूल्यांकन, विनिर्दिष्ट, आकस्मिकता, आस्थगित कर दायित्व, आस्तियों की हानि, पुर्ज, आज्ञापक लागत, उधार लागत आदि के प्रति विनिर्धान पर अर्जित ब्याज का निरूपण।

समिति द्वारा दी गई रायों को मत संग्रह के एक खंड में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक, जनवरी, 2003 तक समिति द्वारा अंतिम रायों से युक्त मत संग्रह के 23 खंड बिक्री के लिए जारी किए जा चुके हैं। फरवरी, 2004 और जनवरी, 2005 के बीच समिति द्वारा अंतिम राय से युक्त मत संग्रह के खंड 24 को संकलित किया जा रहा है।

समिति की राय, समिति की राय को दर्शाती है न कि अनिवार्य रूप से परिषद् की राय को। ये राय शंकाकर्ता द्वारा उठाई गई शंकाओं के तथ्यों और परिस्थितियों, लेखांकन/ संपरीक्षा सिद्धांतों और प्रैक्टिस तथा उस तारीख को, जिसको समिति विशिष्ट राय को अंतिम रूप देती है, लागू सुसंगत विधि पर आधारित होती है। राय को अंतिम रूप देते समय, समिति सम्बद्ध क्षेत्रों

में राष्ट्रीय गतिविधियों को ही ध्यान में नहीं रखती अपितु विषय पर उभरते विचारों सहित सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य को भी ध्यान में रखती हैं।

समिति द्वारा अंतिम रूप से दी गई कुछ रायों को अधिकांश सदस्यों की जानकारी के लिए संस्थान की पत्रिका 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। और सदस्यों की जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

5.8 अनवरत वृत्तिक शिक्षा

5.8.1 सामान्यावलोकन

रिपोर्टिंग अवधि, आईसीएआई के विश्व के केवल सर्वोत्तम चार्टर्ड अकाउंटेंटों के तुलनीय भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों की प्रास्थिति को बनाए रखने के प्रयासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

वृत्तिक सेवाओं के उच्च मानक बनाए रखने के लिए अनवरत वृत्तिक शिक्षा समिति ने सदस्यों की सहायता करने के लिए प्रत्येक संभव पहल की हैं और उसे क्रियान्वित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रेक्टिसों के अनुसार सी.पी.ई. पर विवरण को ऐसे पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि:-

- प्रेक्टिस वाले सभी सदस्यों (कतिपय अपवादों सहित) द्वारा कलैण्डर वर्ष 2004 के दौरान कम से कम 15 घण्टे और कलैण्डर वर्ष 2005 के दौरान कम से कम 20 घण्टे अपने क्रेडिट में अभिप्राप्त करना अपेक्षित हो।
- प्रेक्टिस से भिन्न कार्यों में लगे सभी सदस्यों के लिए कलैण्डर वर्ष, 2006 से सी.पी.ई. क्रेडिट आज़ापक रूप से अपेक्षित हो।

5.8.2 पीओयू को सशक्त बनाना।

सीपीईपीओयू शामिल किए जाने वाले विषयों में एक रूपता बनाए रखने और आईसीएआई से संपर्क किए बिना सीपीई क्रेडिट घण्टे अवधारित करने के लिए समर्थ बनाने के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सम्यक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात सीपीई कलैण्डर जारी कर दिया गया है। इसमें न केवल प्रेक्टिस वाले सदस्यों बल्कि सेवारत सदस्यों के व्यावहारिक सुसंगत विषयों को भी शामिल किया गया है।

पूर्व वर्षों की भाँति सी.पी.ई. कलैण्डर को दो भागों में विभाजित

किया गया है अर्थात् - आज़ापक विषय और वैकल्पिक विषय।

आज़ापक विषय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

- i) मूल्यवर्धित कर (वैट)
- ii) लेखापरीक्षा और आश्वासन मानक:
 - लेखापरीक्षा को शासित करने वाले ए.ए.एस. 1 बेसिक सिद्धांत
 - वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के ए.ए.एस.-2 उद्देश्य और परिधि,
 - ए.ए.एस. 3 प्रलेखन
 - ए.ए.एस.4 कपिट और त्रुटि
 - ए.ए.एस. 6 जोखिम निर्धारण
 - आंतरिक संपरीक्षा के कार्य पर निर्भर रहने वाले ए.ए. एस.7
 - ए.ए.एस. 8 लेखापरीक्षा योजना
 - प्रबंध द्वारा ए.ए.एस. 11 अभ्यावेदन
 - ए.ए.एस. 13 लेखापरीक्षा विषय
 - ए.ए.एस. 14 विश्लेषणात्मक प्रक्रिया
 - ए.ए.एस. 17 लेखापरीक्षा कार्य के लिए क्वालिटी नियंत्रण
 - ए.ए.एस. 19 पश्चातवर्ती घटनाएं
 - ए.ए.एस. 20 कारोबार की जानकारी
 - ए.ए.एस. 21 विधियों पर विचार-विमर्श और वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में विनियम
 - ए.ए.एस. 24 सेवा संगठनों का उपयोग करने वाली इकाईयों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिफल।
 - ए.ए.एस. 28 वित्तीय विवरण संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
- iii) अंतर्राष्ट्रीय कराधान - विशिष्टतया डीटीए के संदर्भ

के साथ

iv आंतरिक लेखापरीक्षा

v सेवा कर विधि और व्यवहार

vi अंतर्राष्ट्रीय वित्त

vii सरबेन्स आक्सले – लेखा परीक्षाओं के दायित्व।

व्यवहार और उद्योग में संस्थान के सदस्यों के प्रासंगिकता वाले वैकल्पिक विषयों में 85 विषय सम्मिलित हैं। इसके अलावा, कलैण्डर में विषयों में 8 मुख्य शीर्ष भी सम्मिलित हैं जो विशेषकर उद्योग वाले सदस्यों के प्रासंगिक हैं।

सीपीई क्रेडिट घण्टों की बढ़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु, संस्थान के सीपीई कार्यक्रम संयोजित यूनिट विशेषकर क्षेत्रीय परिषद्, क्षेत्रीय परिषद की शाखाएं, सीपीई अध्ययन सर्किल तथा सीपीई चैप्टरों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे सदस्यों, जो ऐसे पीओयू में कार्य कर रहे हैं, के साथ न्यूनतम सीपीई कार्यक्रमों का संचालन करें।

5.8.3 सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखना।

समिति ने अन्य बातों के साथ सीपीई पीओयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीपीई कार्यक्रम की गुणवत्ता को मानिटर करने के लिए क्षेत्रीय सीपीई मानिटरिंग समितियां बनाई हैं। जैसा कि सीपीई एडवाइजरी ऑन मानिटेर्स एण्ड सुपरवाइजर्स के अंतर्गत अपेक्षित हैं, ऊपर कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानिटर और सुपरवाइजर नामनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं।

5.8.4 सदस्यों और पीओयू की सेवाएं

सदस्यों की अनवरत वृत्तिक शिक्षा को पूरा करने के लिए संस्थान की वेबसाइट में जानकारी पृष्ठ डाला गया है। पृष्ठ http://www.icaai.org / knowledge/ cpe_main.hotmail पर उपलब्ध है।

समिति ने आन लाइन सीपीई पोर्टल को विकसित करके आन लाइन सदस्यों के लिए सीपीई क्रेडिट डाटाबेस को बनाए रखने के लिए पहल की है जो शीघ्र ही कार्य करना आरंभ कर देगी। प्रणाली पी.ओ.यू. द्वारा प्रविष्ट सीपीई घण्टों के साथ सदस्यों द्वारा प्रविष्ट सीपीई क्रेडिट घण्टों की मैपिंग और विसंगतियां, यदि रिपोर्ट की जाती हैं, को अनुज्ञात करेंगी।

सी.पी.ई. समिति निम्नलिखित युक्तिगत पहलुओं पर कार्य कर रही है:—

- संस्थान के सदस्यों के लिए उच्च विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का संचालन
- अधिक इन हाउस कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन ताकि उद्योगों में सदस्य सी.पी.ई. अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।
- अन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज पर सी.पी.ई. एडवाइजरी का जारी किया जाना।
- इस प्रकार आयोजित कार्यक्रमों की अपेक्षित क्वालिटी को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए सी.पी.ई. अध्ययन सर्किलों की रचना तथा कृत्यों के संनियमों का पुनरीक्षण।
- अनवरत वृत्तिक शिक्षा संबंधी विवरण का पुनरीक्षण।
- प्रबंध अकाउंटेंसी से संबंधित पर्यावरण अर्द्धता पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण

5.9 वृत्तिक विकास

वृत्तिक विकास समिति ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आईसीएआई के सदस्यों के लिए अवसरों की खोज करने, पाने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं। समिति पिछले कई वर्षों से, सदस्यों के लिए नए नए/विद्यमान क्षेत्रों की खोज करके/पता करके और अधिक वृत्तिक अवसरों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है जहां सदस्यों की विशेषता का बेहतर और लाभदायक रीति से उपयोग किया जा सकेगा। समिति यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रही है कि वृत्ति के सभी सदस्यों को साम्य अवसर उपलब्ध हो। इस प्रक्रिया के मात्र रूप, समिति भारत और विदेशों में विनियामक/पैनिमित प्राधिकरणों या वृत्ति की सेवाओं के उपयोग कर्ताओं से निरंतर विचार-विमर्श कर रही हैं।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान समिति की उपलब्धियां / प्रयास नीचे दिए गए हैं:—

- प्राथमिक बैंक पैनल प्ररूप को परिधि में विस्तारित किया गया है जिससे यह बहुप्रयोग्य पैनल प्ररूप बन सके। सदस्य / फर्म वेबसाइट से फार्म को डाउनलोडिंग करने के पश्चात आक लाइन कर सकते हैं। और इंटरनेट को जोड़ने के पश्चात अपने फार्म को लोड

कर सकते हैं।

- सदस्यों को व्यवहार विकास तथा वृत्तिक अवसरों संबंधी समय पर और आवश्यक जानकारी सदस्यों की प्रदान करने के लिए वृत्तिक विकास जानकारी पोर्टल विकसित किया गया है।
- बैंकों की संपरीक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक से चर्चा।
- भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के कार्यालय में सदस्यों के प्रत्यक्ष हित के अनेक मुद्दों का अनुसरण किया गया है।
- स्टॉक ब्रोकर के निरीक्षण/संपरीक्षा तथा पारस्परिक के विभिन्न विषयों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैनल के बारे में सेबी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त रूप से कार्य (आई.सी.ए.आई. और नबार्ड) की संभाव्यता पर विचार-विमर्श करने के लिए नबार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।
- पारस्परिक हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैंकिंग मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट को केवीआईसी के अधीन एनजीओ की विशेष संपरीक्षा करने पर विचार-विमर्श करने हेतु खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।
- सहकारी सोसाइटियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 44 क ख के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बारे में सीबीडीटी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।
- पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने एशियन विकास बैंक (एडीबी), इण्डो, यूएस फायर (डी) प्रोजेक्ट तथा विश्व बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।
- मूल्य वर्धितकर प्रारंभ करने के संबंध में, विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में अभ्यावेदन भेजे गए।
- उपखजाना और प्रसार विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा

के बारे में विभिन्न राज्यों के प्रधान वित्त सचिवों को अभ्यावेदन भेजे गए।

- लेखांकन और वित्त के क्षेत्र में विशेषीकृत सेवाओं के लिए एक पृथक कांडर के सृजन के बारे में सभी सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी को अभ्यावेदन दिए गए।
- पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय और लेखांकन सुधार और क्षमता निर्माण के बारे में विभिन्न राज्यों के मंत्री, पंचायती राज को अभ्यावेदन दिए गए हैं।
- संस्थान की वेबसाइट पर 2004-05 के लिए उपलब्ध बैंक शाखा लेखापरीक्षा की आवंटन स्थिति के बारे में जानकारी दी गई।

उपरोक्त के अलावा, समिति निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है:-

- सभी उपलब्ध और संभावित अवसरों की खोज और उपयोग ताकि संस्थान के सदस्यों के लिए वृत्तिक विकास और वृद्धि के नये अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
- वृत्ति प्रभावित करने वाले मामलों पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना।
- ऐसे सभी विषयों पर जो समिति के मुख्य मिशन से संबंधित हैं, पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विकसित संभाव्य क्षेत्रों के संबंध में उन्हें दिए जाने वाले मार्गदर्शन की रीति और प्ररूप अवधारित करना।
- वृत्ति के सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के साथ संसूचना प्रक्रिया में सुधार लाना जिससे कि वृत्ति के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के अनुरूप वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर प्राप्त हों।
- संस्थान सदस्यों के कौशल और योग्यता में सुधार में विनिर्दिष्ट सहायता देने के लिए उपायों और साधनों पर विचार करना।

- यह सुनिश्चित करना कि वृत्तिक विकास के विद्यमान अवसरों को न्याय संगत और वृद्धि उन्मुख स्तरों पर पूर्णतया उपयोग और अनुरक्षित किया जाए।

समिति अपने इस दायित्व के प्रति भी सचेत हैं कि वह वृत्तिक अवसरों के नए पहलुओं से संबंधित क्षेत्रों में सदस्यों को शिक्षित करें। इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्यक्रम/संगोष्ठियां आयोजित किए:-

- दिल्ली, कोलकता, अहमदाबाद, जयपुर तथा हैदराबाद में हुए परामर्श - "फंडिंग-डी-एज" संबंधी कार्यशालाओं की श्रृंखला।
- नई दिल्ली में हुए नगरपालिका निकायों में कारगर नगरपालिका वित्तीय तथा लेखांकन सुधार संबंधी संगोष्ठी।
- नई दिल्ली में हुए "सरबेन्स आक्सले अधिनियम एनओरिएंटेशन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- चैन्नई में हुए इनरिचमेंट फॉर एक्सिलेंस संबंधी भारत सम्मेलन।
- मुम्बई में हुए पारस्परिक निधियों के अध्यक्ष, निवेशक तथा सीएफओ तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट का अनिवार्य सम्मेलन।
- मुम्बई में हुए सेबी के पदाधिकारियों के लिए वित्तीय समझौता विवरण संबंधी कार्यक्रम।

5.10 पीयर रिव्यू बोर्ड

एक उपाय के रूप में, आईसीएआई ने उच्च क्वालिटी आश्वासन सामंजस्य और पारदर्शिता की मांग को पूरा करने के लिए पीयर रिव्यू संबंधी विवरण जारी किया है। विवरण में पीयर रिव्यू के संचालन के लिए एक ढांचा अधिकथित किया गया है। वृत्तिक कार्य की क्वालिटी में वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए रिव्यू किया जाता है और इसका किसी अनुशासनिक या कोई अन्य विनियामक तंत्र से कोई संबंध नहीं है। रिव्यू इस धारणा से आरंभ किया जाता है कि वृत्तिक कार्य, वृत्तिक रूप से जो वृत्तिकवाद में उन आरोपणों में वृद्धि करने से रोकता है विश्वस्तर से लेखांकन तथा संपरीक्षा वृत्तिक के फोरफ्रंट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता करते हैं। पीयर रिव्यू के उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना सम्मिलित है कि सदस्य प्रमाणन सेवाएं देते समय आईसीएआई द्वारा अधिकथित तकनीकी मानकों का पालन करते हैं; यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे सदस्य ने अपने द्वारा निष्पादित प्रमाणन सेवाओं की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रणाली (जिसमें प्रलेखन प्रणाली भी हैं) रखी है जो विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक

अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करती है और आर्थिक विनिश्चय करने के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोक्ताओं द्वारा बनाए रखे गए विश्वास को बढ़ाती है।

पीयर रिव्यू संबंधी विवरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पीयर रिव्यू बोर्ड को 2002 में स्थापित किया गया था। बोर्ड में 10 सदस्य हैं जिन्हें परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। जिसमें कम से कम छह परिषद के सदस्यों में से होते हैं बोर्ड में सदस्य के रूप में एमसीए, सी और एजी तथा उद्योग (फिक्की और सीटू) प्रतिनिधि होते हैं। इसके अतिरिक्त, विधिक, बैंकिंग तथा शिक्षा के क्षेत्र आदि से सुविख्यातव्यक्ति विशेष आमंत्रित, के रूप में अपने व्याख्यान देकर बोर्ड की सहायता करते हैं।

यथासंभव, इसलिए कि रिव्यूवर विश्वस्तर पर स्वीकार्य मानकों के रूप में रिव्यू कार्य करते हैं, बोर्ड ने पीयर रिव्यू की प्रक्रिया और पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं में पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए एक व्यापक पीयर रिव्यू मैनुअल तैयार किया है। इस संबंध में, बोर्ड के इससे महत्वपूर्ण प्रकाशन पीयर रिव्यूवर्स के लिए एक प्रशिक्षण देने वाले का यह भी मार्गदर्शन करता है कि रिव्यूवर्स का मापदण्ड है जो पैनल के पश्चात अनुभव के लिए रिव्यूवर्स के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है और इसके साथ-साथ प्रशिक्षण देने वालों का यह भी मार्ग दर्शन करता है कि रिव्यूवर्स का प्रशिक्षण कैसे संचालित किया जाए। एफ एक्चू संबंधी बुकलेट भी प्रकाशित की गई है। इस बुकलेट में, ऐसे प्रश्नों, जिनके पूछे जाने की संभावना हो, को भी प्रतिपादित करने के प्रयास किए गए हैं और उनके लिए पर्याप्त और समाधान पूर्वक उत्तर दिए गए हैं।

बोर्ड सम्पूर्ण देश में पैनलित रिव्यूवर्स को प्रशिक्षण प्रदान करता है। रिव्यू का संचालन करने में सुसंगतता और एक रूपता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे कुशल व्यक्ति जिन्हें विचार-विमर्श कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संकाय के रूप में कार्य करते हैं।

पीयर रिव्यू प्रक्रिया को आईसीएआई द्वारा दिखाया जाता है जिसका उद्देश्य तीन चरणों अर्थात् चरण 1, 2, और 3 में कर्मबद्ध रीति से सभी फर्मों को सम्मिलित करना है।

पीयर रिव्यू के चरण 1 और 2 के अधीन सम्मिलित किए जाने के लिए प्रेक्टिस यूनिटों के चयन के प्रयोजन के लिए, घोषणा पत्र की मांग की जाती है। आरबीआई, सी एण्ड एजी, सीएम आईआई आदि जैसे विनियमकों से डाटा भी एकत्रित किया गया था तथा पब्लिक सैक्टर बैंकों की शाखाओं के कानूनी संपरीक्षकों के बारे में संस्थान के अभिलेखों से तथा व्यवहार यूनिटों के निरुद्देश्य चयन के लिए विकसित विशेषकर अभिकल्पित साफ्टवेयर से भी डाटा एकत्रित किया गया था।

बोर्ड ने रिव्यूर्स और रिव्यूजी को अपने अनुभव बताने के लिए आमंत्रित किया था उनसे प्राप्त फीडबैक के अनुसार, रिव्यूर्स और रिव्यूजी दोनों ने यह अभिव्यक्त किया कि पीयर रिव्यू आपस में एक दूसरे के लिए फायदाप्रद हैं।

5.11 उद्योगों में सदस्यों के लिए समिति।

5.11.1 सामान्य अवलोकन

उद्योग में सदस्यों के लिए समिति में आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंटों के बीच निकट संबंधों को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना अंतर्निहित है जिससे कि संगठनों, सरकारी, अभिकरणों, सहकारी विभागों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के साथ व्यापक और गहन नातेदारी की अभिवृद्धि के माध्यम से व्यक्तिगत कैरियर को बढ़ाने में ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा सहायता देकर उनको उस रीति से आधार प्रदान किया जा सके जो अधिकतम नियोजन के अवसर प्रदान करने वाले लक्ष्य को इसके साथ-साथ आगे बढ़ाते समय विश्व व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और शासन को अधिकतम संभावित अविस्थिति प्रदान करे।

समिति उद्योग में पर्याप्त नियोजन अवसरों का पता लगाने में संस्थान के सदस्यों को सहायता भी प्रदान करती है। इस संबंध में, समिति संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है:-

- नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट,
- अल्प अर्हित लेखांकन वृत्तिक (ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम आर्टिकलशिप पूरा कर लिया है।
- अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट — जो वर्तमान समय में उद्योगों में नौकरी कर रहे हैं या प्रेक्टिस कर रहे हैं या जो नौकरी करना पसंद करेंगे।

उपरोक्त सभी सेवाओं को नियोजन पोर्टल www.placement.icai.org के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। आईसीएआई नियोजन पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय बेहतर प्रैक्टिस ओरिएंटेड वित्त और भारतीय उद्योग में लेखांकन संस्कृति के लिए क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से विचार-विमर्श करता है तथा वित्त और लेखांकन तथा उद्योग में अवसर प्रदान करता है।

5.11.2 नियोजन कार्यक्रम (कैम्पस साक्षात्कार)

समिति ने मई 2004 और नवम्बर 2004 में हुई सीए की अंतिम परीक्षा में अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए क्रमशः सितम्बर, अक्टूबर 2004 और फरवरी, मार्च 2005 के दौरान कैम्पस साक्षात्कार का आयोजन किया।

5.11.3 अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा सेमी अर्हित एकाउंटेंट वृत्तिक

अन्य दो प्रवर्गों की नियोजन सेवाओं को नियोजन पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। यह पोर्टल भर्ती करने वाली इकाइयों तथा रोजगार चाहने वालों के लिए आन लाइन प्लेटफार्म हैं तथा यह प्रणाली में से उनकी आशाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है।

5.11.4 सी.एफ.ओ. गिल्ड

समिति सी.एफ.ओ. के गिल्ड को बनाए रखती है। गिल्ड संस्थान के ऐसे सदस्यों के लिए हैं जो उद्योग में वरिष्ठ पदों (जी.एम. और उससे ऊपर) पर हैं।

समिति निम्नलिखित बातों पर कार्य कर रही है:-

- नए अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट के सदस्यों के अंतिम नियोजन में और सुधार करने हेतु नियोजन सेवाओं का विपणन।
- प्रमुख शहरों में नियोजन सेमिनार
- "साक्षात्कार और एफएक्यू का सामना कैसे करें" प्रकाशन का पुनरीक्षण।
- नियोजन पोर्टल को सर्वप्रिय बनाना।
- विदेशी जॉब के लिए विशेष अभियान तथा विदेशी जॉब परामर्शक से संपर्क करना।
- विदेशों में अध्ययन दौरा।
- ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन जो उद्योग से सदस्यों से सुसंगत हो।
- सर्वोत्तम (सीए)/सीएमडी/सीईओ/सीएफओ का संस्थान तथा नियमित पुरस्कार।
- सी.एम.आई.आई. समाचार पत्रों का प्रकाशन

- प्रतिष्ठित सदस्यों और जो उद्योग में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, का डाटाबेस का सृजन।
- संस्थान की नियोजन संबंधी गतिविधियों में सदस्यों की भागीदारी के लिए अर्थोपाय पर विचार करना।
- कर अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट को भर्ती करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ एमओयू तथा करार जो असंख्य अभ्यर्थियों की भर्ती करते हैं।
- उद्योग विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था।

5.12 सूचना प्रौद्योगिकी

5.12.1 1.4.2004 से 30.6.2005 के बीच आईएसए रजिस्ट्रीकरण /ईटी पास/एटी पास की प्रारिथति

यह अनुभूति की गई कि बढ़ते हुए अवसरों का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका संपरीक्षा और लेखांकन में परम्परावादी दक्षता की टेक्नॉलोजी आधारित विश्वस्त कौशल परिवर्तित कर देता है। इसलिए इसने बड़ी संख्या में सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी पश्चार्हता आईएसए पाठ्यक्रम में भाग लेकर के अद्यतन ज्ञान चाहने वाले आईसीआईआई के सदस्यों को प्रेरित किया है। आई.एस.ए. वृत्तिक प्रशिक्षण बैचों आई.एस.ए. पात्रता परीक्षण (ईटी) और निर्धारण परीक्षण (एटी) का संचालन प्रत्येक तिमाही होता है। निम्नलिखित तालिका आईएसए रजिस्ट्रीकरण/ईटी पास/एटी पास की स्थिति को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संक्षेप में दर्शाती है।

विशिष्टियां	आईएसए रजिस्ट्रीकरण	ईटी पास	एटी पास
31.3.2004	15687	8901	5157
1.4.2004 और 31.3.2005 के बीच	4542	4425	3514
31.3.2005 को	20229	13326	8671
1.4.2005 और 30.6.2005 के बीच	850	875	686
30.6.2005 को कुल संख्या	21079	14201	9357

5.12.2 सूचना प्रौद्योगिकी हारमनी न्यूजलेटर प्रौद्योगिकी पर संस्थान की आवाज

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी हारमनी न्यूजलेटर विषय-वस्तु, डिजाइन, व्यवहार और विचार विषयक उच्च स्तरय विषयों पर लेखों के लिए बहुत सराहा गया है। क्रमिक मास में आईएसए पोर्टल पर www.isaicai.org में उपलब्ध आईटी हारमनी ई पद्धति की विषय वस्तु निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

मास	विषय-वस्तु
अप्रैल, 04	आईडेंटिटी मैनेजमेन्ट
मई, 04	सरवेन्स आक्सले एण्ड रिविलिडिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट
जून, 04	कनवरजेंस
जून, 04	बिजनेस कन्टीन्यूटी प्लानिंग
अगस्त, 04	रिस्क इन एन आर्गेनाइजेशन सेट-अप
सितम्बर, 04	कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट
अक्टूबर, 04	बिजनेस इंटेलिजेंस
नवम्बर, 04	नॉलेज मैनेजमेंट
दिसम्बर, 04	आईटी/आईएस संपरीक्षा मानक
जनवरी, 05	इंटरनेट/इंटरनेट एण्ड एक्ट्रोनेट
फरवरी, 05	वेब इनेबिल्ड सर्विसेस
मार्च, 05	आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट
अप्रैल, 05	लाईफ साइकिल मैनेजमेन्ट साल्यूशन
मई, 05	सिस्टम एण्ड प्रोसेस एश्योरेंस
जून, 05	आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैंक्स

संबद्ध विषयक तथा समसामयिक विषयों के अलावा, न्यूजलेटर में सम्मिलित अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं— सरकार में नेताओं से साक्षात्कार, कारबार, प्रौद्योगिकी संस्थान।

5.12.3 आईएसए कोर्स पाठ्यक्रम और सामग्री पुनर्विलोकन समिति आईएसए वृत्तिक प्रशिक्षण बैचों का प्रबंध करने के लिए

पुनरीक्षित कोर्स संरचना और सामग्री के साथ 2005 के तीसरे क्वार्टर से आईएसए पञ्चअर्हता कोर्स के पाठ्यक्रम और सामग्री को पुनरीक्षित कर रही है।

5.12.4 ई-लर्निंग पद्धति के माध्यम से आन लाइन प्रेक्टिस परीक्षण (ओएलपीटी) और अनुसंधानात्मक आन लाइन अध्ययन सामग्री (आर.ओ.एस.एम.) की दोहरी सेवाएं

समिति ने संपूर्ण देश में फैले सदस्यों के फायदे के लिए 24/7/365 आधार पर (हर समय) आन लाइन सुविधा की व्यवस्था की है। यह सुविधा दो सेवाएं प्रदान करती है। ऑन लाइन प्रेक्टिस परीक्षण (ओएलपीटी) और अनुसंधान ऑन लाइन अध्ययन सामग्री (आरओएसएम) ओएलपीटी सुविधा सदस्यों को अपने ज्ञान के स्तर पर पहुंचकर आईएसएईटी सीएटी परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों के प्रकार और स्तर का अपावरण प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। अनुसंधानात्मक आन लाइन अध्ययन सामग्री न केवल आईएसए अभ्यर्थियों के बोध के स्तर की जांच करती है। बल्कि मुख्यधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस विषय पर एक पृष्ठीय पुनरीक्षण सामग्री प्रदान करता है। यह सेवा आईएसए पोर्टल पर www.isaicai.org से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राप्त की जा सकती है।

5.12.5 सीएएटी पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा आयोजित कम्प्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा पाठ्यक्रम कम्प्यूटर पर उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए निम्नलिखित तालिका में पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण और उसके पूरा होने की स्थिति दर्शायी गई है:-

विशिष्टियां	रजिस्ट्रीकरण	बैच	पूरे किए गए
31.3.2004 को	1,450	51	-
31.3.2005 को	2558	70	1516
1.4.05 और 30.6.2005 के बीच	187	3	31
30.6.2005 को प्रास्थित	2745	73	1547

5.12.6 श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्यों के लिए आईएसए पाठ्यक्रम

एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल के रूप में आईसीआई ने श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएसएल) के सदस्यों के फायदे के लिए एक आईएसए पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2003 में आईएसए के पाठ्यक्रम के दो बैचों के लिए आयोजन किया गया। तीसरा बैच अगस्त, 2004 चौथा 2005 में तथा पांचवा बैच अगस्त 2005 में आना है। एमओयू के भाग के रूप में आईसीआई ने परीक्षण द्वारा वृत्तिक प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम सामग्री / प्रेक्टिस परीक्षण / अंतिम निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए पाठ्यक्रम सहायता विस्तारित की है। पाठ्यक्रम को अधिक अभिस्वीकृति मिलने के परिणामस्वरूप नए बैच आ रहे हैं।

5.12.7 आई.सी.ए.एन. के सदस्यों के लिए आईएसए जागरूकता बिल्डिंग कार्यक्रम

दूसरी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल यह है कि आईसीआई ने जून 17-18 को आईसीएन के सदस्यों के फायदे के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी जागरूकता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

5.12.8 प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट लेब्रोर्ट्री (पीओसीएल) सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के केन्द्र (सीईआईटी)

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैंडस आन कार्यशालाएं आयोजित करके सदस्यों को व्यावहारिक तकनीकी एक्सपोजर प्रदान करने हेतु चैन्नई में पाइलट प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट लेब्रोर्ट्री/ सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन इनफोरमेशन टेक्नालॉजी अब प्रचालन में है। आईएस आडिट ऑफ बैंक्स तथा यूज ऑफ सीएएटी टूल्स संबंधी कार्यशाला का आयोजन सदस्यों के फायदों के लिए हर मास किया जा रहा है।

5.12.9 व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सम्मेलन /सेमिनार कार्यशालाएं।

समिति ने उच्च विषयों पर सम्मेलन तथा व्यावहारिक कार्यशालाएं आयोजित करना आरंभ किया है। वर्ष के दौरान, सम्मेलन कोलकत्ता, मुम्बई, पुणे और दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त आईएस आडिट ऑफ बैंक्स, सीएएटी औजारों के उपयोग, आडिट टूल के रूप में एक्सेल का उपयोग नेटवर्क सिम्योरिटी आडिट संबंधी व्यावहारिक कार्यशालाएं फरीदाबाद, दिल्ली और चैन्नई में आयोजित की गईं।

5.13 आरंभ किए गए लोक संपर्क क्रियाकलाप

किया गया था।

5.13.1 संस्थान के दृष्टिकोण और भारत में लेखांकन वृत्ति की शक्ति और समसामयिक मुद्दों पर संस्थान के परिप्रेष्य एवं साथ ही वृत्ति के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए रीति को अग्रसर करने के लिए एक सक्रियात्मक युक्ति अपनाई गई जेसा कि नीचे उपदर्शित है:—

- लोक संपर्क समिति संस्थान के लोग क्रियाकलापों को लगातार आगे बढ़ाने का प्रबंध करती है।
- मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और देश के अनेक दूसरे शहरों में पहल करने की जानी वाली पहल, नीतियां और कार्यक्रम तथा वृत्ति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी इलैक्ट्रानिक मीडिया सहित प्रेस सम्मेलन किए गए। इसमें वृत्ति के समक्ष आने वाले मुद्दों पर प्रसिद्ध पत्रकारों के साथ और टी.वी. चैनलों पर आमने सामने अध्यक्ष की बैठक भी सम्मिलित है।
- विशिष्ट पत्रकारों, प्रेस और इलैक्ट्रानिक मीडिया, सांसदों, सरकारी पदाधिकारीगण, दृष्टिकोण स्पष्ट करने वाले विनियामकों के साथ संकेन्द्रित विचार-विमर्श किए गए तथा वृत्ति से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संस्थान द्वारा पहल की जा रही है।
- संस्थान और सदस्यों के बीच उनके पुनर्निवेशन के लिए संसूचना संपर्क विकसित करने की दृष्टि से, संस्थान, इसके प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वृत्ति से संबंधित समसामयिक मुद्दों के लिए सार्वजनिक वाद-विवाद पर बल दिया गया।
- राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों में संरचनात्मक लेखों तथा टीवी चैनलों और प्रेस के साथ प्रभावी बैठकों के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देना।
- संपूर्ण देश में संस्थान के समाचारों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए प्रेस डाटाबेस का निर्माण किया गया।
- भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय के अधीन गठित समिति को तर्क संगत समर्थन देना।
- और अधिक प्रभावी रीति से परादर्शी कार्यों के लिए तकनीकी और वित्तीय बोलियों की तैयारी के लिए सदस्यों की सहायता हेतु दिल्ली, कोलकता और अहमदाबाद में 'कंसल्टिंग-फाईंडिंग दि एज' कार्यक्रमों का आयोजन

- संस्थान के सदस्यों के लिए "हाव टू राइट इफेक्टिव प्रेस रिलीज" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
- आईसीएआई पत्रिका को संस्थान स्तर पर महत्त्वपूर्ण विकासों के बारे में सूचित करने तथा प्रचार करने हेतु तिमाही रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।
- सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों के विकास के लिए सक्रिय पहल की गई, वृत्ति की सकारात्मक पहचान बनाई गई, सीए छात्रों के लिए कैरियर संभावनाओं और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं को प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जिसमें खालिज टाइम्स ऑफ़ दुबई भी सम्मिलित है, में विज्ञापन के माध्यम से विशिष्टता प्रदान की गई।
- संस्थान के कार्यालय में तथा इंटरनेट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के प्रत्युत्तर की क्वालिटी को सुदृढ़ बनाया गया तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया गया और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए पत्रिकाओं और छात्रों के न्यूज लेटर के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई।
- वृत्तिक और सामाजिक तौर पर संस्थान की छवि के संनिर्माण का प्रस्ताव किया गया और टीवी चैनलों पर एपिसोड्स के माध्यम से साधारण जागरूकता पैदा करने का इरादा है।
- संस्थान के प्रोफाइल और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा की जा रही सेवाओं के संबंध में पुस्तिका भी शीघ्र ही निकाली जाएगी।
- पीआर समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित करने का भी प्रस्ताव किया है।
- संस्थान के पुरालेख भी संदान किए जाते हैं।
- संस्थान के वेबसाइट को फेस-लिफ्ट (मुख्य उपचार या बाह्य रूप संस्कार) दिया गया और इसे अधिक ज्ञानवर्धक और उपयोग कर्ता मैत्री बनाया गया है। महत्त्वपूर्ण घटनाओं की वीडियो क्लिपिंग भी वेबसाइट पर उलब्ध कराई जा रही है।
- विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठकें की गईं।

- भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकें की गई।
- जैसा कि परिषद् द्वारा अनुज्ञात किया गया है, परिषद् के सदस्यों ने कुछ शर्तों के अधीन रहते, प्रेस को विवरण दिया है।
- पीआर समिति के निर्देश निबंधनों को संशोधित किया गया है जिससे कि वृत्ति और संस्थान के सामाजिक कारण / छवि के संवर्धन को सम्मिलित किया जा सके।
- संस्थान की पीआर नीति को पीआर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

5.13.2 मीडिया विषय

- संघ के गृहमंत्रालय और आईसीएआई ने 24, 25 जून 2005 को नई दिल्ली में विदेशी अभिदाय विनियम अधिनियम 1976 संबंधी संयुक्त सेमिनार का आयोजन जिसका उद्घाटन संघ के माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल ने किया तथा माननीय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल गृह राज्यमंत्री उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। विदाई भाषण संघ के वित्तमंत्री माननीय श्री पी. चिदम्बरम ने दिया। संघ के गृह सचिव श्री वी.के.दुर्गल ने भी सेमिनार को संबोधित किया।
- लोक संपर्क समिति और बीमा समिति ने 25, जून 2005 को संयुक्त रूप से "वृत्तिक सुसंगतता के वर्तमान मुद्दे" संबंधी सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्घाटन माननीय श्री के. रहमान खान, उपाध्यक्ष, राज्यसभा ने किया।
- एक अवसर पर पीआर समिति ने माननीय श्री के. रहमान खान को उपाध्यक्ष, राज्यसभा के संवैधानिक पद पर पहुंचने के कारण सम्मानित किया। श्री एम.के. गर्ग, सीएमडी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्री एम रामदास, सीएमडी, ओरियंटल एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्री बी सम्भावमूर्ति कार्यपालक निदेशक इंडियन बैंक, श्री एस.वी. नरसिम्हा, प्रबंध निदेशक, चैन्नई पेट्रोलियम, कारपोरेशन लिमिटेड, श्री जी कृष्णामूर्ति, अध्यक्ष तथा सीईओ, भारत ओवरसीस बैंक, लिमिटेड, जो वृत्ति के ब्रांड अम्बेसडर हैं तथा जिन्होंने इसे बीमा, बैंकिंग तथा पब्लिक सेक्टर कंपनियों में उच्च सोपानक हैं, को सम्मानित किया गया था।
- 14, मई 2005 को हैदराबाद में डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में उभरते हुए वृत्तिक अवसर संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन संसद सदस्य श्री सी रामचन्द्रैया ने किया था तथा सेमिनार की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री को निजेती शेसाईया ने की।
- 16 जून, 2005 को नई दिल्ली में संघ के कंपनी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन प्रक्रियात्मक पहलुओं का सरलीकरण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संघ के कंपनी कार्यमंत्री ने कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा कंपनी कार्य मंत्रालय की सचिव, श्रीमती कोमल आनंद ने विदाई भाषण दिया।
- 4 मई 2005 को नई दिल्ली में राज्य वित्तमंत्रियों की सशक्त समिति के सदस्य सचिव आईसीएआई के श्री रमेश चन्द्र द्वारा तैयार राज्य स्तर वैट के लिए मॉडल संपरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया।
- वैट संबंधी राज्यमंत्रियों की सशक्त समिति के अध्यक्ष माननीय डा. असीम कुमार दास गुप्ता ने 15 अप्रैल, 2005 को आईसीएआई द्वारा तैयार राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पण राष्ट्र को समर्पित किया।
- 3 फरवरी, 2005 को राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में आईसीएआई विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।
- 1 जुलाई, 2005 को चार्टर्ड एकाउन्टेंट दिवस मनाया गया। जिसका उद्घाटन माननीय विधि और न्यायमंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज ने किया था। राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री के.रहमान खान, संसद सदस्य और भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभू तथा संसद सदस्य माननीय श्री सी रामचन्द्रैया ने समारोह की शोभा बढ़ाई।
- 4 फरवरी, 2005 को आईसीएआई का 55वां वार्षिक समारोह का आयोजन हुआ जिसका उद्घाटन संघ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री कमलनाथ ने किया था।
- नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में "न्यू चैलेंजेंज न्यू सोल्यूशन इन आईटीएण्ड डब्ल्यूटीओ द्वारा" संबंधी सम्मेलन में संघ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री कमलनाथ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन पर एक नया पश्च अर्हता पाठ्यक्रम आरंभ किया गया।

- 8 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में कारपोरेट विधि, प्रकटन अपेक्षा तथा अनुसूची 6 के चेंजिंग फेंस पर आईसीएआई और फिक्की की संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सभा की गई।
- संस्था ने वर्ष 2003-04 के लिए "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार दिए जाने के लिए एक समारोह आयोजित किया। हिज एक्सलेंसी उपराज्यपाल (सेवानिवृत्त) एस.के. सिन्हा, और कंपनी मामलों के रूप मंत्री माननीय श्री प्रेम चन्द गुप्ता ने विजयी घोषित किए गए संगठनों के प्रतिनिधियों को पुरस्कार दिए।
- संस्थान ने भारत में सुनामी पीड़ितों के पुर्नवास के लिए प्रधानमंत्री राहत निधि में अंशदान करने के लिए 42.50 लाख रुपये एकत्रित किए। संस्थान के अध्यक्ष श्री कमलेश एस विक्रमसे ने रकम के चेक को कंपनी कार्य मामलों के मंत्री माननीय श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता को दिया। कंपनी कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती कोमल आनंद तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- 24 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अवसर संबंधी बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग फोकसिंग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए पी.आर. सपोर्ट प्रदान करना।
- 8 दिसम्बर, 2004 को 19वां सार्क चार्टर दिवस के अवसर पर, संस्थान ने "कम्प्यूटेशन सिक्लिस् : कटिंग एज फार सीए प्रोफेशन पर वाद-विवाद का आयोजन किया था। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सार्क श्री वी. अशोक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- आईसीएएन के अध्यक्ष श्री पुष्पालाल श्रेष्ठा की अध्यक्षता में नेपाल के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के एक प्रतिनिधि दल ने भारत का दौरा किया जिससे आईसीएआई के साथ दो दिन लगातार विचार-विमर्श किया गया और दो संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यवाई योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।
- 4 जून 2005 को स्टेट ऑडिट इंस्टिट्यूट ऑफ अमन के प्रतिनिधि दल ने नई दिल्ली का दौरा किया।
- आस्ट्रेलिया के हेड एपीजी सचिवालय श्री रिक मैक डोनल की अध्यक्षता में 21 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में संस्थान में मनी लांडरिंग पर एशिया पेसफिक समूह के पारस्परिक मूल्यांकन दल ने दौरा किया।
- 17 से 18 मार्च को दुबई में आईसीएआई के दुबई चैप्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा—इचैलेंजेज एण्ड फोकस 2005 संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

5.14 व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति संकल्पनावाद, सूत्रीकरण, बातचीत कार्यान्वयन, व्यापार से संबंधित प्रतिरोध विधि जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार भी सम्मिलित हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, जिसमें साधारणतया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से दोनों विश्व व्यापार संगठन प्रणाली भी सम्मिलित हैं, से संबंधित सभी विषयों में सुविज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लिए उसके लक्ष्य को प्राप्त करने और आईसीएआई की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित और बढ़ाने के लिए गठित की गई थी जिससे कि इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, चिन्ता और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, समिति चुनौतियों का सामना करने तथा नई विश्व व्यापार व्यवस्था में उनकी विशेषज्ञता उदार बनाने के फायदों को प्राप्त

5.13.3 अंतर्राष्ट्रीय

- 16-18 फरवरी, 2005 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट (आईएफएसी) के अध्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड और आईएफएसी के मुख्य कार्यपालक श्री आयनवाल ने भारत का दौरा किया।
- नई दिल्ली में 1 से 4 नवम्बर, 2004 तक आईएफएसी पब्लिक सैक्टर समिति की बैठक की मेजबानी संस्थान ने की। बैठक के अलावा, —इनहैंसिंग अकाउंटेंटिलटी एंड गुड गवर्नेंस इन दि पब्लिक सैक्टर संबंधी एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया था। जिसमें लगभग 15 देशों से 45 विदेशी प्रतिनिधि थे।
- केरल में 24-25 सितम्बर, 2004 को इमर्जिंग ग्लोबल अपरच्युनिटिज पर आईसीएआई और आईसीएसएल का संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ।

करने के लिए संस्थान के सदस्यों तकनीकी रूप से लैस करने की दृष्टि से बदलते हुए विश्व परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए तथा भारत के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए निरंतर प्रयास करता है।

5.14.1 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम

यह वर्ष बहुत पहले से प्रतिक्षेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम को आरंभ करने के साथ समिति के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में साबित हुआ है। इसके उद्देश्य निम्नलिखितवत हैं:-

- आईसीएआई के सदस्यों की सेवाओं के लक्ष्य में विस्तार करना।
- सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और करारों के जटिल क्षेत्रों में विशेषीकरण का लाभ लेने में समर्थ बनाना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के उभरते हुए क्षेत्रों में प्रीमियम सेवाओं का प्रस्ताव करने के लिए सदस्यों की क्षमता निर्माण को समर्थ बनाना।
- क्षेत्र में विकसित समर्पित प्रेक्टिस के लिए तैयार क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाना।

नए विश्व व्यापार क्रम में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों तथा करारों को समझने तथा लागू करने में सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए विशेषज्ञता का आधार सृजित करने की दृष्टि से, 5 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग संघ मंत्री माननीय श्री कमलनाथ द्वारा एक पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एक विशेषीकृत पाठ्यक्रम जिसे नए विश्व व्यापार वातावरण के अनुरूप से बनाकर संस्थान के सदस्यों के लिए अभिकल्पित किया गया, होने के नाते पाठ्यक्रम को संपूर्ण देश में फैले सदस्यों से प्रोत्साहित प्रयुत्तर प्राप्त हुए। पाठ्यक्रम के आरंभ होने पर प्रथम बैच के लिए कुल 139 सदस्यों का रजिस्ट्रीकृत किया गया था। 30.7.2005 तक कुल 150 सदस्यों का पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण के लिए लिया गया।

पाठ्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य निम्नलिखित की पूर्ति किए जाने के लिए थे:-

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों तथा विश्व व्यापार संगठन विधियों के लिए विवरणिका जारी करना, तेजी से बदलते

हुए परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की वृत्तिक योग्यता को सुदृढ़ करते हुए, इसके महत्त्व को दर्शित करना;

- जटिल मुद्दों पर सदस्यों की सहायता करने के लिए देश में और इससे बाहर, विषय के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके पाठ्यक्रम के सभी पेपरों के लिए व्यापक अध्ययन सामग्री जारी करना;
- सुझाई गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसी पाठ्यक्रम सामग्रियों की सूची की सिफारिश जो पाठक को अतिरिक्त जानकारी देते हैं तथा विशिष्ट मुद्दे / विषय का ब्यौरा देते हैं;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और करारों, जो विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान के अंतर्गत प्रचालित होते हैं, की व्यावहारिक पहलुओं तथा पेचदगियों के बारे में समझने में अभ्यर्थियों को समर्थ बनाने के लिए वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम संचालित करना।

5.14.2 पाठ्यक्रम के अधीन वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम के प्रथम चरण का सफलतापूर्वक पूरा होना।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि तथा विश्व व्यापार संगठन में अर्होत्तर पाठ्यक्रम के लिए वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम का पहला चरण का सफलतापूर्वक आयोजन 1 से 14 जुलाई, 2005 तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली के साथ-साथ मुम्बई, चैन्नई, कोलकता और कानपुर में किया गया था। कार्यक्रम इस अर्थ में विलक्षण था कि पहली बार आईसीएआई के 14 दिन के लंबे कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से दिल्ली के साथ मुम्बई, चैन्नई-कोलकता और कानपुर के विनिर्दिष्ट केन्द्रों में बैठे अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। कार्यक्रम चर्चा करने वाला था जिसके द्वारा ऐसे अवस्थानों से कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्य कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा आपस में विचार-विमर्श करने में समर्थ थे। प्रतिष्ठित प्राध्यापक वर्ग तथा वाणिज्य मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन के लिए भारत के स्थायी मिशन, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के प्राध्यापक वर्ग, व्यापार तथा उद्योग से लोग, विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्र में वृत्तिक और अन्य अनुसंधान आधारित संगठनों ने अपने विचार प्रकट किए तथा पीसीपी के दौरान अपने व्याख्यान दिए और भागीदारी द्वारा अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

5.14.3 डब्ल्यू टी ओ अन्वेषक डब्ल्यूटीओ विषयों पर अद्यतन तकनीकी जानकारी।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, अगस्त, 2004, दिसम्बर, 2004 और अप्रैल, 2005 प्रत्येक में "डब्ल्यूटीओ अन्वेषक, डब्ल्यूटीओ विषयों पर अद्यतन तकनीकी जानकारी" के तीन अंक निकाले गए थे। जागरूकता अभियान सामग्री के रूप में प्रकाशन सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों के फायदों के लिए डब्ल्यूटीओ संबंधी उपयोगी अद्यतन तकनीकी जानकारी लगातार दे रहा है। इन मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग निम्नलिखित हैं:—

- डब्ल्यूटीओ का जुलाई फ्रेमवर्क करार: कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं।
- व्यापार नीति पुनर्विलोकन: तंत्र तथा नवीनतम रिव्यू पर एक नजर।
- टैक्सटाइल और क्लेशिंग: 2005 से भविष्य
- भारतीय विदेश व्यापार नीति 2004-09
- सेवाओं में व्यापार संबंधी साधारण करार: मूल तल, लेखांकन, सेवाओं में बातचीत।
- आगे बढ़ना: प्रक्रिया से उत्पाद पेटेंट प्रणाली तक।
- चायना डब्ल्यूटीओ अनुपालन
- प्रतिस्पर्धा विधि और नीति — एक समझदारी।
- डब्ल्यूटीओ समाचार।

5.14.4 सेमिनार/सम्मेलन / जागरूकता कार्यक्रम

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति ने हैदराबाद में 14 मई, 2005 को डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में उभरते हुए वृत्तिक अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जिसकी मेजवानी एसआईआरसी के हैदराबाद शाखा ने की थी। सेमिनार का उद्घाटन संसद सदस्य माननीय श्री सी रामचन्द्रैया तथा वृत्तिक सदस्यों ने किया तथा आंध्रप्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री रोसायिया कोनजेती ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, डा. मोहन कनाड़ा, आईएसएस ने भी भाग लिया। 'प्रतिस्पर्धा विधि और नीति के विशेष संदर्भ के साथ डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में उभरते हुए वृत्तिक अवसर' विषय पर प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य, प्रशासन श्री विनाद के दल ने संबोधन किया। तकनीकी सत्र के दौरान डा. एस चक्रवर्ती (आईएसएस सेवानिवृत्त)

एमआरटीपी आयोग के भूतपूर्व सदस्य और भूतपूर्व विशेष मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर गोपालन आईएसएस तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री आर.के. गुप्ता, आईआरएस ने प्रतिस्पर्धा विधि और नीति — लेखांकन वृत्तिकों के लिए अवसर, सेवा का निर्यात — अभिस्वीकृति अवसर और क्रास बार्डर संव्यवहार — लेखांकन वृत्तिकों के लिए मुद्दे और उभरते हुए अवसर संबंधी तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में हैदराबाद वाणिज्य कर आयुक्त, सीबी भास्कर, आईएसएस द्वारा वैट व्यवस्था में लेखांकन वृत्तिकों की उभरती हुई भूमिका पर विशेष संबोधन को सम्मिलित किया गया। सेमिनार जिसमें सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे, को व्यापक मीडिया प्रचार मिला।

- 4-6 नवम्बर, 2004 को 'आईटी और डब्ल्यूटीओ युग में नई चुनौतियाँ, नए समाधान संबंधी सम्मेलन का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी और आईसीएआई की एन आईआरसी संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से नई दिल्ली में व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति ने किया। सम्मेलन के विशेष सत्र के दौरान, संघ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री कमलनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ में एक अर्होत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर गोपालन ने सेवा में व्यापार के उदारीकरण की वास्तविकताएं संबंधी तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की तथा डब्ल्यूटीओ व्यवस्था में उभरते हुए वृत्तिक अवसर संबंधी तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिव श्री टी.के. विश्वनाथन ने की थी। सम्मेलन में वाणिज्य मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय लघु उद्योग आदि के अनेक पदाधिकारियों, सदस्यों, मीडिया और अन्य लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में पहचानी गई संभावनाओं स्वयं आत्म विश्लेषण तथा उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए हमारी वृत्तिक सक्षमता को समझने की आवश्यकता जैसे मुद्दों को उठाया गया था।

- "डब्ल्यूटीओ व्यवस्था तथा लेखांकन सैक्टर की अत्यावश्यकता — चुनौतियाँ तथा अवसर" संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 25 सितम्बर, 2004 को आईसीएआई के एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा, हैदराबाद में, 4 अक्टूबर 2004 को आईसीएआई की एनआईआरसी की जालंधर शाखा, जालंधर तथा 17 जून, 2005 को आईसीएआई की ई आईआरसी, कोलकाता में किया गया था। इस प्रयोजन के लिए,

“डब्ल्यूटीओ में बेसिक तथा डब्ल्यूटीओ में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का प्रभाव तथा अवसर संबंधी व्यापक पृष्ठभूमि वाली सामग्री” भी तैयार की गई थी।

5.14.5 ज्ञान साझेदारी

समिति ने ज्ञान साझेदारी पृष्ठ विकसित किया है जिसे आईसीएआई की वेबसाइट पर लिंक ‘केएम’ के अंतर्गत दर्शित किया गया है और यह निरंतर पृष्ठ डब्ल्यूटीओ की बुनियादी समझ संबंधी उपयोगी और सुसंगत जानकारी प्रदान करता है। यह पृष्ठ विश्व व्यापार के परिप्रेक्ष्य में तेजी से होने वाले नवीनतम विकास के बारे सदस्यों को परिचित करता है।

5.14.6 आईसीएआई तथा आईआईएफटी के बीच समझौता ज्ञापन

आईसीएआई और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के बीच डब्ल्यूटीओ के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा डब्ल्यूटीओ में अर्हतापूर्ण पाठ्यक्रम के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- संसाधन व्यक्ति के रूप में फैकल्टी के बीच साझेदारी;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि तथा विश्व व्यापार संगठन में अर्हतापूर्ण पाठ्यक्रम के लिए व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को समर्थन;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों तथा विश्व व्यापार संगठन में अर्हतापूर्ण पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत आईसीए आई सदस्यों को आईआईएफटी के पुस्तकालय और अन्य अवसरचना की भागीदारी;
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ के क्षेत्र के ज्ञान के आधार को विकसित करने से संबंधित तकनीकी और अन्य दस्तावेजों का आदान-प्रदान;
- संयुक्त प्रकाशनों के परिणाम स्वरूप डब्ल्यूटीओ के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान तथा अध्ययन करना;
- पारस्परिक लागत भागीदारी आधार पर अनुध्यात हित के विषय से संबंधित संयुक्त सेमिनारों, कार्यशालाओं का आयोजन; और

- तकनीकी जानकारी तथा ज्ञान और विशेषज्ञता के अंतरण को सुकर करने की विशेषज्ञता का आदान प्रदान।

5.14.7 गेट्स के अधीन आरंभिक प्रस्तावों का निर्धारण

समिति वर्तमान गेट्स के अंतर्गत आरंभिक प्रस्तावों का निर्धारण कर रही है और ऐसे सेवाओं के क्षेत्रों में विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा सेक्टर विनिर्दिष्ट/ समान सीमाएं अंकित की गई हैं जिनमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लेखांकन, संपरीक्षा, बुक कीपिंग, कराधान, कम्प्यूटर संबंधित सेवाएं जिसमें साफ्टवेयर, डाटा प्रसंस्करण और डाटा बेस सेवाएं सम्मिलित हैं, प्रबंध परामर्शी विधिक तथा उनसे तुलनात्मक फायदों को प्राप्त करने के लिए सुझाई गई संभावित युक्ति हेतु अनुसंधान अध्ययन करने वाली वित्तीय सेवाओं जैसी सेवाओं में सहायता कर सकते हैं।

5.15 बीमा संबंधी समिति

समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए अप्रैल, 2003 में बीमा और जोखिम प्रबंध में एक अर्हतापूर्ण पाठ्यक्रम (डीआईआरएम) आरंभ किया है। विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ जीवन और साधारण बीमा के सिद्धांत और व्यवहार, बीमा लेखांकन और प्रबंध, विनियामक ढांचा, आरिस्त और दायित्व प्रबंध, शोधन क्षमता मार्जिन, अनेक साधारण और जीवन बीमा उत्पादों तकनीकी पहलू जोखिम प्रबंध उपाय, बीमा कारबार के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी औजारों का उपयोग तथा उत्पाद विनिर्मिति तथा सहायक क्षेत्रों पर नियंत्रण और युक्तियों विस्तारण सम्मिलित हैं। यह पाठ्यक्रम इस दृष्टिकोण से अनुमोदित किया गया है। जिससे कि सदस्यों को बीमा उद्योग के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त हो सके।

- समिति ने 6 नवम्बर, 2004 को हैदराबाद में बीमा संबंधी राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया। आईआरडीए के अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे।
- 25 जून, 2005 को बीमा संबंधी समिति तथा पीआर समिति ने संयुक्त रूप से वृत्तिक सुसंगतता के वर्तमान मुद्दों पर एक अखिल भारती सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री रहमान खान ने किया था। सम्मेलन में बीमा, बैंकिंग, कराधान, सेवा कर फ्रिज फायदाकर बैंकिंग नकद संव्यवहार कर, रियल इस्टेट और आईटी एड बीपीओ के लिए दस्तावेजों के प्रारूपण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। सुविख्यात वक्ताओं ने विभिन्न सत्रों ने

संबोधित किया। सम्मेलन में 800 लोगों ने भाग लिया था।

- समिति ने उद्योग और आईसीएआई से संबंधित मुद्दों पर आईआरडीए के साथ निकट संपर्क बनाए रखा।
- उद्योग विनिर्दिष्ट विशेषीकरण पाठ्यक्रम होने के कारण, पाठ्यक्रम के रजिस्ट्रीकरण में वस्तुतः जबरदस्त, प्रतिक्रियाएं हुईं। पाठ्यक्रम के लिए 30 जून, 2005 तक 2566 सदस्यों का नामांकन हुआ। अभ्यर्थियों का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्षेत्र	31 मार्च 2005 को	30 जून 2005 को
पश्चिमी	443	463
दक्षिणी	974	983
मध्य	454	469
पूर्वी	279	286
उत्तरी	360	365
योग	2510	2566

- दूसरी तकनीकी परीक्षा 5 और 9 नवम्बर, 2004 के बीच आयोजित की गई थी जिसमें 266 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दूसरी तकनीकी परीक्षा में 73 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। तीसरी तकनीकी परीक्षा 6 और 10 मई, 2005 के बीच आयोजित की गई थी।
- तकनीकी परीक्षा में सकल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के लिए ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम मई और नवम्बर, 2004 को विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गये थे। इसमें क्रमशः 45 और 95 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
- संस्थान की वेबसाइट, www.icaai.org पर प्रारंभ ज्ञान गेटल को जारी रखा गया है। इसमें समाचार भाग समसामयिक भागफल, पाठ्यक्रम जानकारी/उद्घोषणाएं और प्रेस कक्ष दिए गए हैं। यह बीमा सेक्टर से सहबद्ध प्रेक्टिस तथा सेवा में सदस्यों, और उन सदस्यों के लिए लाभदायक है जो आईआरएम पाठ्यक्रम कर रहे हों।
- बीमा कंपनियों के निरवेश कार्यक्रम के निरीक्षण तकनीकी गाइड के पाठ को जारी कर दिया गया है।

- पाठ्यक्रम सामग्री को पुनर्निरीक्षित किया गया है।

6. अंतर्राष्ट्रीय पहल

वर्ष के दौरान, समिति ने परीक्षा से संस्थान के सदस्यों को छूट दिए जाने और विदेशी निकायों की अर्हता के भाग रूप प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेशी लेखांकन निकायों द्वारा संस्थान की अर्हता का मूल्यांकन किया लम्बी प्रक्रिया होने के कारण इसमें अर्हता, प्रशिक्षण, अनवरत वृत्तिक शिक्षा तथा अनुशासनिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन सम्मिलित है और गेट्स के अधीन बातचीत की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें आंतरिक अतिसंवेदनशीलता है, जिससे प्रक्रिया धीमी रहती है, अभी भी संस्थान प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

नामनिर्देशन के रूप में संस्थान एक प्रमुख भूमिका अदा करता है यह अपनी विभिन्न वृत्त्यकारी समितियों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन के शासी निकाय बोर्ड, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी), कंफेडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक अकाउंटेंट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) का उपयोग करता है। इस समय संस्थान का प्रतिनिधि एसएएफए का उपाध्यक्ष है। शासी बोर्ड के अतिरिक्त संस्थान निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है।

आईएफएसी की समितियां:

- शिक्षा समिति;
- लघु तथा मध्य व्यवसायकर्ता स्थायी टास्क फोर्स;
- विकासशील राष्ट्र स्थायी टास्क फोर्स;
- अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड;
- व्यावसाय समिति में वृत्तिक अकाउंटेंट्स

सीएपीए की अनुकूल समितियां

एसएएफए:

- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी पर उत्कृष्टता केन्द्र
- मानक तथा क्वालिटी नियंत्रण पर उत्कृष्टता केन्द्र
- संपरीक्षाओं की नीतिविषयक तथा स्वतंत्रता पर उत्कृष्टता केन्द्र

- बेहतर प्रस्तुति लेखा पुरस्कार तथा बेहतर निगमित शासन पुरस्कार पर उत्कृष्ट केन्द्र
- एसएएफए की पुनर्संरचना के लिए वे-फारवर्ड पर सिफारिश करने के लिए कार्यकारी समूह;
- दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रोदभवन लेखांकन संबंधी कार्यकारी समूह,
- दक्षिण एशिया क्षेत्र में बेहतर कारपोरेट शासन प्रेक्टिसेस संबंधी कार्यकारी समूह
- फर्म के नेटवर्किंग संबंधी कार्यकारी समूह
- सार्क देशों में प्रमुख उत्पादों की कास्ट इंडिसेस का अध्ययन संबंधी टास्क फोर्स
- सलाहकार के रूप में (दिसम्बर, 2004 तक)
- स्थायी सचिव के रूप में;

संस्थान ने 27-28 अगस्त, 2004 को साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) के सार्क क्षेत्र में एकीकृत वित्तीय बाजार पर 20वीं जयंती सम्मेलन की मेजबानी की। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, पाकिस्तान, प्रतिभूति और विनियम आयोग, श्रीलंका प्रतिभूति और विनियम आयोग तथा नेपाल प्रतिभूति बोर्ड जैसे विनियामकों ने विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

- संस्थान 26-27 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में हुई एसएएफ असम्बेली, सलाहकारी निकाय जिसमें भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे, सार्क क्षेत्र में प्रमुख उत्पादों की लागत इंडेक्स के अध्ययन पर टास्क फोर्स तथा सदस्य निकायों की अनुसंधान संबंधी सदस्य निकायों के प्रधानों की बैठक की मेजबानी की।

1 नवम्बर 2004 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आईएफएसी) की सार्वजनिक सेक्टर समिति के साथ एन्हासिंग अकाउंटेंटबिलिटी एण्ड गुड गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर पर एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया।

- संस्थान ने 2-4 नवम्बर, 2004 को नई दिल्ली में आईएफएसी के सार्वजनिक सेक्टर समिति की बैठक की मेजबानी भी की।
- संस्थान ने चीन में पूंजी बाजार, विनियम, बैंकिंग और

बीमा उद्योग, स्टॉक बाजार प्रणाली, विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति आदि का अध्ययन करने और चीन के प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करने के लिए वहां का अध्ययन दौरा आयोजित किया। इस दौरे का आयोजन 23 नवंबर, 2004 से 3 दिसम्बर, 2004 तक किया गया।

- 25-26 नवम्बर, 2004 को मसकट, ओमान में ओमान सलतनत को राज्य संपरीक्षा संस्था के तत्वावधान में रिडिफाइनिंग द अकाउंटिंग प्रोफेशन विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया।
- 25-26 दिसंबर, 2004 को नागपुर, भारत में आयोजित 17वें अखिल भारतीय आईसीए इंडिया स्टूडेंट सम्मेलन में बंगलादेश, नेपाल और श्रीलंका से चार्टर्ड अकाउंटेंसी सदस्य निकायों के छब्बीस छात्रों ने भाग लिया था।
- दक्षिण एशिया के अन्य देशों में वृत्तिक वातावरण के प्रति अनुकूलन की दृष्टि से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्रों को समर्थ बनाने के लिए जनवरी, 2005 के दौरान पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएपी) के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 9-10 जनवरी 2005 को अबू धाबी में संस्थान ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृत्ति की भूमिका पर एक सम्मेलन आयोजित किया।
- 14-15 जनवरी, 2005 को लाहौर के पाकिस्तान के चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान के साथ "एकाउंटिंग प्रोफेशन: न्यू होराइज़न" विषय पर एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- 30 जनवरी, 2005 को इण्डोनेशिया स्थित संस्थान के चैप्टर ने वृत्तिक विकास और शिक्षण क्रियाकलाप आयोजित करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन किया।
- 30-31 जनवरी, 2005 को काठमाण्डू, नेपाल में, नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ "प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स: लुकिंग बियॉड फ्रंटियर" विषय पर संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया।

संस्थान के निमंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार परिसंघ (आईएफएसी) के अध्यक्ष श्री ग्राहम बार्ड और आईएफएसी के मुख्य कार्यमालक श्री इयान बाल 16-18 फरवरी, 2005 को भारत आए। उनके आगमन के समय ही सरकार, विनियामकों, सीएफओ, वृत्ति के सदस्यों और मीडिया के साथ बहुउद्देशीय परिचर्चा हुई जिससे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक भागीदारी

को समझने और सार्वभौमिक रूप से होने वाले विकास एवं आईएफएसी द्वारा उठाए गए कदमों को भारत सरकार और विनियमकों द्वारा अपनाए जाने में सहायता मिले। उनके तीन दिवसीय आगमन पर उन्होंने माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों, माननीय कंपनी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के महा नियंत्रक और लेखा परीक्षक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पदाधिकारियों से भेंट की। आईएफएसी के अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि आईएफएसी लेखांकन वृत्तियों के स्वतंत्र रूप से आने जाने के पक्ष में हैं और लेखांकन वृत्ति में सर्वोत्तम प्रेक्टिस स्थापित करने के लिए विश्व बैंक जैसे अग्रणी विश्व निकायों और अन्य विनियामकों के साथ भी कार्य कर रहा है। आईएफएसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत में लेखांकन वृत्ति की अधिक भूमिका की वकालत की उनके आगमन के समय ही 18 फरवरी, 2005 को मुम्बई में "चैंजिंग पैराडिगम इन अकाउंटिंग प्रोफेशन" पर एक सम्मेलन भी आयोजित हुआ।

सदस्य अधिकारिता में ओर आतंकवाद को वित्तपोषित करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के क्रियान्वयन और निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय निकाय एशिया /पेसिफिक ग्रुप (एपीजी) के मूल्यांकों का एक उच्च स्तरीय दल ने 21 मार्च, 2005 को आईसीएआई से संपर्क स्तरीय दल ने 21 मार्च, 2005 को आईसीएआई से संपर्क किया था।

- दुबई स्थित संस्थान के चैप्टर द्वारा 17-18 मार्च, 2005 को 'ई चैलेजेज एण्ड फोकस 2005 पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- संस्थान के दुबई स्थित चैप्टर ने वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों में और उनकी विवक्षाओं एवं वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास पर 29, मई, 2005 को एक तकनीकी सम्मेलन आयोजन किया था।
- संस्थान ने 18, जुलाई 2004 को काठमाण्डू में नेपाल के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन और संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों, मार्गदर्शक टिप्पण, नेपाली संस्थान के सदस्यों के लिए नीति पूरक संहिता सतत् वृत्तिका शिक्षा तंत्र का निर्माण, अध्ययन सामग्री की डिजाईनिंग और विकास और आईसीएएन छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली के स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी समर्थन की व्यवस्था, दो निकायों के मध्य अनुसंधान क्रियाकलापों तथा संयुक्त सम्मेलनों के संवर्धक और समर्थन के लिए उपाय सुझाने पर अधिक ध्यान दिया गया।

- नेपाल के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान के अध्यक्ष तथा कार्यपालक निदेशक पर सम्मिलित एक प्रतिनिधि मण्डल संस्थान द्वारा नेपाल के आईसीए को सहायता की बाबत औपचारिकताओं पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए 6-7 दिसम्बर, 2004 को संस्थान में आया था।
- नेपाल के आईसीए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक परिषद् सदस्य 2-5 मई, 2005 को संस्थान में आए और संस्थान द्वारा पीयर रिवीव, आईएसए पाठ्यक्रम के संचालन, पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण तथा सतत् वृत्तिक शिक्षा के क्षेत्रों में नेपाल के आईसीए को सहायता प्रदान करने की बाबत व्यापक विचार-विमर्श किया।
- संस्थान ने अन्य बातों के साथ-साथ नेपाल के आईसीए के प्रति पीयर रिवीव ढांचा और आईसीए नेपाल सदस्यता के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा ने अर्होत्तोर पाठ्यक्रम के प्रति आनी बचनबद्धता प्रकट की तथा 17-18 जून, 2005 को काठमाण्डू में पीयर रिवीव प्रणाली एवं सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर एक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया।
- पारस्परिक सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र धारित करने वाले संस्थान के सदस्यों को (i) वाणिज्यक विधि; (ii) प्रत्यक्ष कर और (iii) अप्रत्यक्ष कर में नेपाल आईसीए की परीक्षा पारित करने पर उसकी सदस्यता लेने के लिए अनुज्ञात किया गया और वे केवल ऐसी फर्म के रूप में नेपाल में व्यवसाय कर सकते हैं, जहां विदेशी नागरिकों का अंश 51 प्रतिशत से अधिक न हो।
- श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान के साथ भी श्रीलंका के संस्थान के सदस्यों के लिए सूचना और प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) पर पाठ्यक्रम के संचालन को समर्थन देने के लिए 18, जुलाई, 2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वृत्तिक प्रशिक्षण के संचालन के लिए संस्थान के पदाधिकारियों/संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था, पृष्ठभूमि सामग्री का उपबंध, अभ्यर्थियों के लिए अनुसंधान आनलाइन अध्ययन सामग्री (आरओएसएम) एवं आनलाइन व्यावहारिक परीक्षा की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के संचालन और प्रशासन के लिए निर्धारण परीक्षणों के संचालन की व्यवस्था के उपबंध किए गए थे।
- संस्थान द्वारा नवंबर, 2004 में आयोजित चीन के अध्ययन दौरे में चीन के सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट

संस्थान के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए दोनों निकायों के सदस्यों की शंकाओं का समर्पित समाधान करने के लिए, तकनीकी दस्तावेजीकरण के विकास में समर्थन देने और परीक्षा, पियर रिवीव, वित्तीय रिपोर्ट पुनर्विलोकन, सतत वृत्तिक शिक्षा अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम आदि में आदान-प्रदान करने और समर्थन देने के लिए दोनों में से प्रत्येक संस्थान में तकनीकी डेस्क स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई। उपरोक्त विनिश्चयों के संबंध में दोनों संस्थानों के मध्य चर्चा ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- सिंगापुर के सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट संस्थान के साथ भारत के तत्वावधान में एमआरए अकाउंटेंसी सेक्टर में सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) करने के लिए बातचीत की जा रही है।
- समिति ने ऐसे देशों में भी लेखांकन वृत्ति का समर्थन करने की समभाव्यताओं का पता लगाया, जहां वृत्ति का कोई सांविधानिक स्थापन नहीं है।

लेखांकन वृत्ति का संस्थानिकरण और क्षमता भवन के लिए यूई को तकनीकी सहयोग विषयक संस्थान के प्रस्ताव के प्रबंध में एक प्रस्ताव पत्र यूई में भारत के महा कौशल कार्यालय में और यूई सरकार के अर्थव्यवस्था तथा योजना मंत्री को प्रस्तुत किया गया है।

- महामहिम श्रीनासिर एच अलरवाही, उपाध्यक्ष एसएआई की अध्यक्षता में स्टेट आडिट इंस्टीट्यूट, ओमान (एसएआई) से एक प्रतिनिधिमंडल का 4 जुलाई, 2005 को ओमान में लेखांकन संस्थानीकरण जिसमें इसके अपने लेखांकन निकाय की स्थापना है, में आईसीएआई की भूमिका पर विचार करने के लिए संस्थान में आगमन हुआ। संस्थान और एसएआई के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में आईसीएआई के साथ एसएआई के सहयोग और मसकट, ओमान में संस्थान के एक शाखा कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था है।
- संस्थान ने 15 अक्टूबर, 2004 को बेसेल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और संपरीक्षा मानक के क्रियान्वयन पर गोलमेज में 10-11 फरवरी, 2005 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड और राष्ट्रीय मान स्थापक बैठक में 23 फरवरी, 2005 को कोलंबो में साफाक्षेत्र में मानक स्थापक बैठक में और एसएमई पर लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विशेषज्ञों के अंतर-सरकारी कार्य समूह की

बैठक में प्रतिनिधित्व किया।

मई, 2005 में संस्थान ने विदेशों में रहने वाले सदस्यों के लिए आश्रित एक इलेक्ट्रानिक तिमाही विज्ञप्ति आईसीएआई इंटरनेशनल प्रारंभ की है।

- समिति ने विदेशों में रहने वाले संस्थान के सदस्यों के परिप्रेक्ष्य में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों के एक सैट का संकलन किया है। इसे संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्ष के दौरान संस्थान ने नाइजीरिया और पोर्ट मोर्सबी (पपुवा न्यू गुआना) में दो नए चैप्टर खोले हैं। जिससे विश्व भर में संस्थान के चैप्टरों की संख्या 15 हो गई है।

- संस्थान भारतीय वृत्ति के अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों के साथ परस्पर मान्यता व्यवस्थाओं के संवर्धन के अपने निरंतर प्रयासों के साथ-साथ देश की समस्याओं पर भी समान रूप से ध्यान देता है, संस्थान की संसूचनाओं ने मुख्य रूप से इस बात को उजागर किया है कि सरकार की लेखांकन सैक्टर में प्रस्थापना का मार्गदर्शन राष्ट्रीय हित को सामने रखकर हो और उसे प्रारंभिक रूप से लेखांकन सेवाओं को की गई प्रस्थापना को कम न करके वृत्ति की चिंताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। संस्थान ने कारगर वचनबद्धता /प्रस्थापनाओं की ईप्सा करने की आवश्यकता और बड़े व्यापारी भागीदारों से वृत्तिक और गैर वृत्तिक बाधाओं को हटाने की ईप्सा की है ताकि भारतीय लेखांकन वृत्तियों को इन देशों तक कारगर पहुंच प्राप्त हो सके।
- संस्थान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेता रहा है ताकि लेखांकन सैक्टर में चल रही बातचीत पर अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कर सके।
- ईयू इंडिया स्माल प्रोजेक्ट्स फेसिलिटी प्रोग्राम फार द इयर, 2004 के अधीन यूरोपियन कमिशन को भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में प्रतिनिधि मण्डल ने निम्नलिखित शीर्षक की परियोजना भारत को प्रदान की है। फाईनेंसिएल एण्ड अकाउंटिंग रिफार्मस: कैपेसिटी बिल्डिंग एण्ड रिलेटेड स्ट्रेटजीज़।
- समिति की सिफारिशों पर आधारित संस्थान की परिषद ने दक्षिण एशिया लेखाकार परिषद (साफा) द्वारा या साफा के तत्वावधान में इसके चार्टर्ड अकाउंटेंसी सदस्य निकायों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए संस्थान के सदस्यों को सीपीई प्रत्यय

अनुज्ञात किया जाए।

- संस्थान 1-2 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में 'अकाउंटिंग प्रोफेशन: एडिंग वेल्थू टू न्यू होरीजन्स ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ' विषय पर एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है।

- संस्थान 1 से 3 सितंबर 2005 को नई दिल्ली में साफा सभा इसके उत्कृष्टता केन्द्रों और कार्य समूहों की बैठकों की मेजबानी करेगा।

- वर्ष 2005 के दूसरे भाग के दौरान आईएफएसी के विकासशील राष्ट्र स्थाई टास्क फोर्स की बैठकों की मेजबानी करेगा।

- संस्थान को वर्ष 2006 के लिए इंटरनेशनल इन्वैशन नेटवर्क (आईआईएन) सम्मेलन और इसकी समन्वयन समिति की बैठकों की जनवरी 2006 में मेजबानी करने का सैद्धांतिक अनुमोदन आईआईएन से प्राप्त हो चुका है। आईआईएन, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में लगभग 20 देशों में लेखांकन संस्थानों का संगठन है जिसमें विश्व भर के एक मिलियन से अधिक लेखाकार प्रतिनिधित्व करते हैं।

7. अन्य क्रियाकलाप

7.1 मानव संसाधन विकास

7.1.1 मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआई ने अपने सदस्यों, छात्रों और अन्य सम्बद्ध जनसाधारण को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ताकि ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो और व्यवहार संबंधी परिवर्तन आए:

- व्यक्तिगत सशक्तिकरण, व्यवहार और कार्यपालक प्रभावकारिता, चुस्त प्रबंध, समय प्रबंध और संचार जैसे क्षेत्रों में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला।
- योग थेरापी पर पश्चातवर्ती श्रृंखला का राउंड।
- मझौले, ज्येष्ठ और उच्च स्तर के कार्य पालकों के लिए प्रबंधकारी प्रभावकारिता/कार्यपालक विकास, कार्यक्रम की विशेषरूप से तैयार की गई श्रृंखला।
- अस्थाई समितियों के सचिव की आशा रखने वालों के

लिए ज्ञान बांटने के लिए आवधिक/सतत् सत्र, अनुभव और चिन्ता/पूर्विकता के क्षेत्रों की पहचान।

- नए प्रवेश पाने वालों के लिए जागरूकता और परस्पर क्रिया सत्र।
- साप्ताहिक कार्यशाला लेखांकन मानक और सहयोजित विषय।
- अधिकारियों के लिए आवधिक परस्पर क्रिया अनुकूलन पाठ्यक्रम।
- कर्मचारिवृन्द के लिए विभिन्न स्तरों पर आवधिक परस्पर क्रिया सत्र

- एमआईएस और इसकी प्रभावकारिता पर सम्मेलन

- वेट पर कार्यशाला।

- पुस्तकालय सेवाओं पर कार्यशाला

- कम्प्यूटर प्रशिक्षण की पश्चातवर्ती श्रृंखला।

इसके अलावा शिकायत निवारण, समय से काउंसलिंग, वर्धित सुविधा प्रबंध आदि के लिए मानव संसाधन पहल निम्नानुसार हैं:-

- शिकायत की ईप्सा तथा कष्ट कम करने की प्रक्रिया कारवाई के साथ मास प्रारंभ करें।
- विभागीय सोमवार बैठकें
- अतिरिक्त /केन्द्रित कर्मचारी के ध्यान के अपेक्षा करने वाले क्षेत्रों में आवधिक कर्मचारी काउंसलिंग।
- निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए उनके उन्नत प्रदर्शन द्वारा तथा अपेक्षित स्तर तक परिदान स्तर को लाकर मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए सतत् समर्थन।

इस प्रकार नियमित मानव संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 2750 घण्टों से भी अधिक समय का है, मुख्यालय और प्रादेशिक कार्यालय स्तरों पर आयोजित किए गए।

7.1.2 मानव संसाधन — कल्याणकारी उपाय।

आईसीएआई ने सदैव इस बात को मान्यता दी है कि मानव संसाधन इसकी पूर्व की तमाम सफलताओं की सबसे महत्वपूर्ण, आरिष्ठ है इसका यह भी दृढ़ विश्वास है कि यह आरिष्ठ आने

वाले समय की सभी कठिनाइयों का समाधान है और यह आईसीएआई को एक "मार्गदर्शक तारा" बनाएगी। वर्ष के दौरान भी इसने अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक कल्याणकारी उपाय करना जारी रखा।

7.2 सदस्यों और छात्रों की सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

7.2.1 वर्चुअल इंस्टीट्यूट

परिषद को 'वर्चुअल इंस्टीट्यूट' को सार्वभौमिक बनाने की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है अखिल भारतीय आधार पर सदस्यों और छात्रों के केन्द्रीयकरण और एकीकरण का प्रथम कार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ क्रियाशील समस्याएँ हैं किन्तु मंजिल सामने है और इन समस्याओं को शीघ्र ही हल कर लिया जायेगा।

वर्चुअल इंस्टीट्यूट के पास विवेकी संरचना और उपयोजन के प्राथमिक परिधान केन्द्र (पीडीसी) के रूप में आंकड़ा केन्द्र है। थकाऊ अध्ययन के पश्चात चैनल की पीडीसी की अवस्थिति के रूप में और नई दिल्ली की डिजासस्टर रिकवरी (डीआर) स्थल के रूप में पहचान की गई। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर चैनल और नई दिल्ली ने एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क बनाया। सभी क्षेत्रीय कार्यालय उच्च बैंडविड्स लीज्ड लाइन के माध्यम से चैनल के साथ जुड़े हैं। शाखाएं डायलप वीपीएन के माध्यम से पीडीसी से जुड़ी हैं क्योंकि उनका उपयोग आंतरिक है और एक या दो व्यक्तियों तक सीमित है। दिल्ली और चैनल के बीच एक 2 एमबीपीएस पाइप न केवल दो अवस्थितियों के मध्य प्रतिदिन यातायात को समर्थन देता है बल्कि नई दिल्ली में डीआर आंकड़ा आधार के आन लाइन समक्रमण का भी ध्यान रखता है।

आंकड़ा केन्द्र, सन कलस्टर, सिलिक्स एप्लीकेशन सर्वर फार्म और वेब सर्वर फार्म पर चलने वाले डियल एप्लीकेशन कलस्टर (आरएसी) के साथ ओरकिल 9i आंकड़ा आधार सर्वर सहित एक हाई एण्ड स्थापन है। डीआर स्थल स्केल्ड डाऊन सैटअप की मेजबानी करता है। पीडीसी पर जोखिम की स्थिति में आंकड़े सुरक्षित कर लिए जाते हैं और गंभीर प्रचालन डीआर स्थल से जोड़कर पुनर्जीवित कर लिए जाते हैं।

वर्चुअल इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, दो वर्षों के अनथक परिश्रम के पश्चात संपूर्ण संरचना के शीर्ष पर है। उपयोजन पर डब्ल्यू ए एन वातावरण के भीतर स्टिरिक्स थिन कम्प्यूटिंग क्लायंट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट उपयोग कर्ता (सदस्य और छात्र) ब्राउसर पर वेब सर्वर के माध्यम उपयोजन पर पहुंच सकते हैं।

इस परियोजना में प्राप्त की गई अभी तक वृद्धि से सभी पांच क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रचलन एक केन्द्रीकृत तंत्र के रूप में बंध गया है। इन सभी से आईसीएआई के क्रियाशील कृत्य, सीमलेस प्रवाह और सूचना उपलब्धता के साथ एक सामान्य इंटरनेट में आ गए हैं। संस्थान के साथ परस्पर क्रिया करने में छात्रों और सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए आईसीएआई ई-सेवा के नाम की सेवाएं सदस्यों और छात्रों को आईसीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। यह सुविधा छात्रों और सदस्यों को संदाय गेट वे के प्रयोग से फीस का भुगतान करने में समर्थ बनाती है।

7.2.2. संचार आधार

संस्थान ने अपना संचार आधार रिलायंस नेटवर्क को स्थानांतरित कर दिया है। संस्थान रिलायंस मोबाइल सेवा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क द्वारा डाटालाइन और इंटरनेट सेवाओं का इस वर्ष के प्रारंभ से उपयोग कर रहा है।

7.2.3 आईसीएआई की उद्यम ईमेल सर्वर

वैयप्ति और विश्व पता पुस्तकों, निगमित निर्देशिका, वेब आधारित कलेंडरिंग और अनुसूचीकरण, डाकनीति और असीमित उपभोक्ताओं के लिए वेब आधारित प्रशासन जैसी मुख्य विशेषताओं वाले रोबस्ट एंटी स्पम/एंटी वाइरस नियंत्रण के साथ संस्थान के उद्यम ईमेल सर्वर को अद्यतन किया गया है।

7.2.4 ऑनलाइन बहुउद्देशीय सूचीकरण फार्म

संस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वृत्तिक विकास समिति को एक ऑनलाइन बहुउद्देशीय सूचीकरण फार्म की घोषणा करने में समर्थ बनाया। सामान्य बैंक सूचीकरण फार्म के विस्तार को बढ़ाया गया और उसे बहुउद्देशीय सूचीकरण फार्म बनाया गया जिससे कि आईसीएआई को बहुउद्देशीय सूचीकरण फार्म के उत्तर के माध्यम से सृजित आंकड़ा आधार से पैन्लों के लिए विभिन्न उद्यमों के अनुरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सुविधा हो।

7.2.5 सदस्यों की सूची तक ऑनलाइन पहुंच

1, अप्रैल, 2005 को यथा विद्यमान सदस्यों की सूची तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा आईसीएआई वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा सदस्यता संख्या या नाम आधारित खोज में समर्थ करती है। इस सुविधा का उपयोग करने के बाद जनसाधारण यह पता लगा सकेगा कि क्या स्वयं को चार्टर्ड अकाउंटेड घोषित करने वाला व्यक्ति आईसीएआई का सदस्य है या नहीं।

7.2.6 ऑनलाइन प्रकाशन बिक्री

वर्ष के दौरान संस्थान के प्रकाशनों की ऑन लाइन बिक्री प्रारंभ करने का विनिश्चय किया गया था। तदनुसार एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई जो उपयोगकर्ताओं को प्रकाशन का चयन करने में समर्थ बनाती है ताकि उसकी कीमत भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कूरियर प्रभागों पर देने में समर्थ करती है। तत्पश्चात् प्रकाशन कूरियर द्वारा उपयोगकर्ताओं को उस पते पर भेज दिए जाते हैं जो ऑन लाइन अनुरोध के समय प्रकाशन क्रम करने के लिए आईसीएआई साईट पर उपदर्शित किया गया था।

उपरोक्त के अलावा, सदस्यों और छात्रों को उनके शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक किलियरेंस सिस्टम (ईसीएस) का उपयोग करके ऑन लाइन करने की सुविधा प्रारंभ की गई।

7.2.7 ईरेगुलेशन

आंकिक प्रमाण पत्र जारी करने वाला आईसीएआई एक उपप्रमाणन प्राधिकारी है। उप-प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में आंकिक प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता प्राप्त करने वाला आईसीएआई प्रथम संस्थान है। ई-रेगुलेशन के भाग रूप में, संस्थान ने प्रस्तुत किए गए ऑन लाइन फार्म/आंकड़ों के लिए आंकिक हस्ताक्षर की सुविधा प्रारंभ की है और ग्राहक मशीन (अर्थात् सदस्य) कर्मचारी और जारी किए गए आंकिक हस्ताक्षर का उपयोग करने वाले सुरक्षित एचटीटीपी कनक्शन उपयोक्त आईसीएआई उप प्रमाणन प्राधिकारी के वेब सर्वर के मध्य सूचना के लिए एक सुरक्षित चैनल स्थापित किया है। प्रारंभ में यह सुविधा ईमेल पर आंकिक हस्ताक्षरों का उपयोग करके प्रारंभ की गई थी। एक ऐसी प्रणाली प्रारंभ की जा रही है जिसमें सदस्य और छात्र आईसीएआई के साथ सभी विनियामक फार्मों पर ऑन लाइन हस्ताक्षरों के लिए आंकिक हस्ताक्षरों का उपयोग करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा और अधिक सुरक्षा एवं पहुंच नियंत्रण की दृष्टि से आईसीएआई, सदस्यों और छात्रों को ऑनलाइन फार्म फाइल करने में समर्थ बनाने के लिए पहुंच नियंत्रण यंत्र आधारित आंकिक प्रमाण पत्र समाकलित करती है। वर्तमान में, आईसीएआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र सदस्यों को आयकर विभाग के साथ ई इंटरमीडियटरी के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाते हैं।

7.2.8 आईसीएआई पोर्टल

वर्ष के दौरान आईसीएआई वेबसाइट को पुनर्सर्जित करने और परस्पर क्रियात्मक पोर्टल बनाने का विनिश्चय किया गया था इस समय इस दिशा में कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही आईसीएआई वेबसाइट को परस्पर क्रियात्मक पोर्टल बना दिया

जायेगा। आईसीएआई वेबसाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता के परिसर से स्वयं आईसीएआई के परिसर में आ गई है। लेखक/ की बर्ड (शब्द कुंजी) आधारित खोज पुस्तकालय पुस्तकों के शीर्षक ऑन लाइन देखने की सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई है।

7.2.9 इंटरनेट

आईसीएआई इंटरनेट सुविधा को कारगर उपयोग के लिए शुरू कर दिया गया है। कार्यालय की सभी आंतरिक संसूचनाएं, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासन विभाग से संबंधित मुद्दों के बारे में उपयोगकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर प्रारंभ किया गया ताकि उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों / प्रार्थना पत्रों की स्थिति का पता लगा सकें। वेतन पर्ची, आयकर विवरण और व्यक्तिगत व्यौरे देखने और मुद्रित करने की एक प्रणाली भी इंटरनेट पर क्रियान्वित कर दी गई है।

7.3 संपरीक्षा समिति

आईसीएआई की परिषद् ने इसको वित्तीय सूचना की बाबत रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन पद्धति का अवलोकन करने की दृष्टि से संपरीक्षा समिति गठित की थी। वार्षिक वित्तीय विवरण और रिपोर्टों के परिषद् को प्रस्तुत किए जाने के पूर्व, अवलोकन के समय निम्नलिखित केन्द्र बिन्दु होते हैं:-

- लेखांकन नीतियों और समाधान को बनाए रखना।
- लेखांकन मानकों और लागू विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता आंकना
- आंकड़ा सुरक्षा और अखंडता आदि की क्षमता
- वित्तीय और जोखिम प्रबंध नीतियों का मूल्यांकन

वर्ष के दौरान समिति ने, अपने निर्देश के निबंधनों की परिधि के भीतर कार्य करते हुए, नियमित अंतरालों से आईसीएआई के आंतरिक और कानूनी दोनों संपरीक्षकों से विस्तृत चर्चा की। समिति ने आंकड़ा सुरक्षा, अखंडता आदि सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के साथ-साथ संपरीक्षकों की राय एवं सुझावों पर विचार-विमर्श किए एवं आईसीएआई लेखाओं को संपूर्ण रूप से पुनरीक्षित किया। इसने प्रादेशिक कार्यालयों में लेखांकन सिद्धांतों एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपयों की सिफारिश की और आईसीएआई द्वारा अधिकथित नीतियों को बनाए रखा।

समिति ने यह महसूस किया कि केन्द्रीय और प्रादेशिक संपरीक्षा

समितियों की बैठकें नियमित अंतरालों पर अर्थात् दो मास में कम से कम एक बार कराई जानी आवश्यक है ताकि लेखाओं की स्थिति और संपरीक्षा प्रेक्षण का पुनर्विलोकन किया जा सके। तदनुसार, प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों ने भी अपने अपने प्रादेशिक कार्यालयों में स्थिति का अवलोकन करने के लिए एवं क्रियात्मक दक्षता में वृद्धि करने के लिए और अधिक प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण की बाबत उपाय करने के सुझाव देने के लिए आवाधिक अंतरालों पर बैठकें की। प्रादेशिक समितियों की टीका टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय संपरीक्षा समिति ने एक नीतिगत विनिश्चय के लिए तथा दक्षता में और अधिक सुधार लाने के लिए अपने सुझावों की सिफारिश कार्य समिति को की जिन्हें अंततः पश्चात्तर्वर्ती द्वारा स्वीकार किया गया।

समिति ने आंतरिक संपरीक्षकों के लिए कार्य-विस्तार का भी पुनर्विलोकन किया और इसे वित्तीय एवं जोखिम प्रबंध के साथ नियंत्रण पहलुओं के सभी बड़े क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अधिक व्यापक बनाया। समिति ने आंतरिक और कानूनी संपरीक्षकों से सूचना के मुक्त प्रवाह के साथ कारगर संसूचना और संपरीक्षा प्रेक्षणों के समय से अनुपालन एवं परिणामतः वार्षिक लेखाओं के शीघ्र निपटारे के लिए आईसीएआई के आंतरिक और कानूनी सभी संपरीक्षकों के आंकड़ा आधार सृजित करने की भी पहल की है।

7.4 वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड

वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड की स्थापना जुलाई, 2002 में देश में प्रचलित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे को और सशक्त बनाने एवं वृत्ति के सदस्यों द्वारा प्रदान की जा रही अनुप्रमाणन सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाने की दृष्टि से की गई थी। बोर्ड, उद्यमों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन अवधारित करने की दृष्टि से करता है।

रिपोर्टधीन वर्ष बोर्ड के कारगर कार्यकरण का प्रथम वर्ष था। वर्ष के दौरान बोर्ड के यादृच्छिक आधार पर चयनित वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 20 कंपनियों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया था। बोर्ड में प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार इन विवरणों का प्राथमिक समीक्षा बोर्ड द्वारा रखे गए पैनल में से चयनित तकनीकी समीक्षकों द्वारा किया गया था। तकनीकी समीक्षक द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट पर इस प्रयोजन के लिए गठित वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा समूह ने विचार किया था। तब बोर्ड ने समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार किया। इन 20 कंपनियों की समीक्षा अब पूरी हो चुकी है। इन 20 मामलों में से बोर्ड ने छः मामले

उनकी जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के उपबंधों के अधीन जांच किए जाने के लिए सचिव आईसीएआई को भेजे हैं। बोर्ड ने पांच मामले उद्यमों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए उद्यमों के सुसंगत विनियामक निकायों को भी भेजे हैं। (इन पांच मामलों में चार मामले वे हैं जो संस्थान के सचिव को निर्दिष्ट किए गए हैं)।

अपर उल्लिखित 20 कंपनियों की समीक्षा करने के पश्चात् बोर्ड ने वर्ष 2003-04 के लिए यादृच्छिक आधार पर चयनित 125 कंपनियों के साधारण प्रयोजन के वित्तीय विवरणों की समीक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया है। इस समीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड ने इसके द्वारा रखे जा रहे समीक्षकों के पैनल में 80 तकनीकी समीक्षक रखे हैं और देश के विभिन्न भागों में छः वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा समूह गठित किए हैं। इन वित्तीय विवरणों की समीक्षा पहले ही प्रारंभ हो चुकी है।

7.5 शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति

7.5.1 लेखांकन शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव का लक्ष्य ऐसे सक्षम वृत्तिक लेखाकार पैदा करना है जो अपने जीवन काल में वृत्ति को तथा समाज को, जिसमें वे रहते हैं, सकारात्मक योगदान देने में समर्थ हों। वृत्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वृत्तिक लेखाकार बनने वाले व्यक्ति सक्षमता का एक युक्तियुक्त स्तर प्राप्त करें और फिर उसे बनाए रखें। वे साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति सक्षमता विकसित और बनाए रख सकते हैं, शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव हैं और फिर सतत वृत्तिक विकास।

7.5.2 आईसीएआई ने छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण को सशक्त बनाने में निरंतर प्रयत्नशील रहा है क्योंकि उसके विचार में ये वृत्ति का आधार हैं। नीतिगत रूप में, आईसीएआई शिक्षा और प्रशिक्षण की आवधिक समीक्षा करता रहता है। वर्तमान में शिक्षा और प्रशिक्षण की स्कीम जो अक्टूबर 2001 से प्रवृत्त है, मुख्यता समीक्षा समिति (1998) की सिफारिशों पर आधारित है। सूचना क्रांति, आर्थिक सुधारों और सार्वभौमिकरण के साथ अंतराष्ट्रीय विकास उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से संस्थान की परिषद ने निम्नलिखित निर्देश शर्तों के साथ मई, 2003 में उच्च शक्ति प्राप्त शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति गठित की:-

- परिवर्तन वातावरण और वृत्ति की मांग के संदर्भ में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुसंगतता और पर्याप्तता अवधारित और सुनिश्चित करने के लिए संस्थान की सदस्यता हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण की विद्यमान प्रणाली की समीक्षा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपायों पर विचार करना और उन्हें अपनाना कि प्रणाली अंतराष्ट्रीय लेखाकार परिसर की शिक्षा समिति जैसे अंतराष्ट्रीय निकायों द्वारा

विकसित अर्हता पूर्व अर्हतात्तर के निर्देश से अंतराष्ट्रीय शिक्षा मानकों में अंतर्विष्ट विशेषताओं और अन्य विवरणों को पूरा करती है।

- छात्रों के लिए वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रम की अंतर्वस्तु में समुचित परिवर्तनों पर विचार करने और अपनाने के लिए विद्यमान पाठ्य विवरण की समीक्षा।
- बढ़ती अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण-प्रक्रिया की स्वीकृति और उपयोजन और पारस्परिक मान्यता करारों पर विचार करा और उन्हें अपनाना।
- सदस्यों (जिसके अंतर्गत सदस्यता पश्चात परीक्षा भी है) के लिए सतत वृत्तिक शिक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार करना।
- उपरोक्त मुद्दों से उत्पन्न ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति अवधारित करे।

7.5.3 समिति ने प्रश्नावलियों के डिजाइन और विश्लेषण, प्रथक अध्ययन समूह बनाना, जनसाधारण की राय आमंत्रित करना आदि सहित शिक्षा और प्रशिक्षण की कोई स्कीम बनाने के पूर्व इसकी शक्तियों और कमजोरियों के संदर्भ में और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं से संबंधित सक्षमता प्रोफाइल के अवधारण में वर्तमान शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रणाली के मूल्यांकन का एक व्यापक रास्ता अपनाया।

7.5.4 संस्थान की परिषद् ने जुलाई, 2005 में आयोजित अपने 252 वें अधिवेशन में शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया। की गई सिफारिशों के अनुसार आईसीएआई की सदस्यता के लिए अर्हतापूर्व शिक्षा और प्रशिक्षण की प्रस्तावित संपूर्ण स्कीम निम्नानुसार है:-

- कक्षा 10 (या इसके समतुल्य) परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या इसके बाद सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) के लिए अध्ययन बोर्ड में नामांकन।
- 10+2 (या इसके समतुल्य) परीक्षा में बैठने के पश्चात या बाद में सामान्य प्रवीणता परीक्षा में बैठना परन्तु यह तब जबकि सीपीटी के नामांकन और सीपीटी में सम्मिलित होने के बीच कम से कम तीन मास का अंतर हो; और दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करना।
- वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) और साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण करने के लिए सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु सीपीटी और 10+2 (या इसके समतुल्य)

उत्तीर्ण करने के पश्चात अध्ययन बोर्ड में नामांकन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण।

- वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम और फाइन पाठ्यक्रम करते समय साढ़े तीन वर्ष की अवधि के लिए एकीकृत सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना।
- कम से कम 100 घंटे (या जैसाकि परिषद द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए जिसके अंतर्गत इसकी रूपात्मकताएं हैं) का अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण करना, जो सीपीटी परीक्षा में बैठने के तुरंत पश्चात या चार्टर्ड एकाउन्टेड पाठ्यक्रम में सम्मिलित वृत्तिक विषयों के सुसंगत व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान (इसका विनिश्चय अध्ययन बोर्ड परिषद के परामर्श से समय-समय पर करेगा) प्रारंभ हो सकता है और यह वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 18 मास पश्चात वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

- वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किन्तु संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकन के पूर्व कम से कम 100 घंटे का या जैसा कि अवधि या रूपात्मकता के संबंध में परिषद द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए। साधारण प्रबंध और संसूचना, कौशल पाठ्यक्रम करना।

- व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतिम छः मास में या उसके पश्चात आयोजित संस्थान द्वारा संचालित फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करना, परन्तु यह तब जबकि वृत्तिक सक्षमता परीक्षा और फाइनल परीक्षा के बीच कम से कम एक परीक्षा का अंतर हो यदि ऐसी फाइनल परीक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान ली जाती है।

7.5.5 व्यावहारिक प्रशिक्षण की विद्यमान तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाकर साढ़े तीन वर्ष करना प्रस्तावित है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतराष्ट्रीय मानकों के समन्वय में प्रभावी तीन वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण (छुट्टी अवधि निकाल कर प्रदान) किया जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और साधारण प्रबंध संसूचना कौशल पाठ्यक्रम पर जोर देने का आशय समुच्चय वृत्तिक पैदा करना है। नई स्कीम प्रारंभ किए जाने पर चार्टर्ड एकाउन्टेड बनने के लिए अपेक्षित कुल समयावधि वर्तमान में पांच वर्ष तीन मास के स्थान पर लगभग चार वर्ष होगी।

7.5.6 संसूचना और सूचना प्रौद्योगिक के दौर में, परिषद ने सैद्धांतिक शिक्षा देने में ई-लर्निंग सुविधा के गहन उपयोग की

सिफारिश की है। विषयों की प्रस्तावित पुनर्संरचना द्वारा भी लेखांकन, जिसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर और वित्तीय प्रबंध सहित प्रबंध लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान हैं, जैसे प्रमुख क्षेत्रों के अलावा कारबार नीतिशास्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया है। निर्धारण रीति में बड़े परिवर्तन किए जाने की संभावना है क्योंकि सीपीटी स्तर पर बहुचयनित प्रकार के प्रश्नों पर बल दिया जाएगा जबकि फाइनल परीक्षा में अधिक बल केस स्टडी रीति पर होगा।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी तीनों परीक्षाओं, अर्थात् सामान्य दक्षता परीक्षण (सीपीटी), वृत्तिक सक्षमता परीक्षा (पीसीई) और अंतिम परीक्षा में बैठने पर कोई निर्वधन नहीं लगाया जायेगा।

7.5.7 संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अंतिम संपूर्ण स्कीम की पद्धतियाँ को अनुकूल बनाया जा रहा है और परिणाम स्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 में प्रस्तावित संशोधनों को एमसीए को भेजा जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए, नई स्कीम 2006 से प्रवृत्त होगी।

7.6 आंतरिक संपरीक्षा समिति

7.6.1 मिशन

आंतरिक संपरीक्षण संबंधी समिति को संवर्धक, समाज में इससे संबंध आंतरिक संपरीक्षा और अन्य पहलुओं के संबंध में ज्ञान के स्रोत तथा प्रबंधक के रूप में आईसीएआई के आधिपत्य का संवर्धन करने के लिए 5 फरवरी, 2005 को आईसीएआई की अस्थायी समिति के रूप में गठित किया गया था जिससे कि इसके सदस्य उद्योग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं अधिक कारगर तथा दक्षता से देने में समर्थ हों पश्चातवर्ती को अपने नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को सुव्यस्थित और सशक्त करके अपनी शासन प्रक्रिया को सशक्त तथा सुव्यवस्थित करने में सहायता दे सकें।

7.6.2 उद्देश्य

समिति का उद्देश्य भारत में विद्यमान आंतरिक संपरीक्षा व्यवहार का पुनर्विलोकन तथा आंतरिक संपरीक्षा (एसआईए) संबंधी विकास मानकों को विकसित करना, मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करना तथा एसएस से उद्भूत मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करना है जिससे कि इनको संस्थान के परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जा सके।

7.6.3 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक तथा मार्गदर्शन की प्रस्तावना।

वर्ष के दौरान, समिति ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणों की प्रस्तावना को अंतिम रूप दे दिया है। प्रस्तावना का आशय महत्वपूर्ण मुद्दों और मानक के रूप में सहायता कराना है जैसे— आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति या कार्यक्षेत्र तथा कृत्य, 'आंतरिक संपरीक्षा पद की परिभाषा, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों को बनाने की प्रक्रिया, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों तथा मार्गदर्शक टिप्पणों का लागू होना, इन मानकों तथा मार्गदर्शक टिप्पणों के अनुसरण की विक्षाएं, इन मानकों तथा मार्गदर्शक टिप्पणों के संबंध में प्रकटन, मानकों को प्रभावी बनाने की तारीख आदि।

7.6.4 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति आईसीएआई के निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि – सामग्री के रूप में तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।

- कोडई कनाल में अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा संबंधी तीन दिवसीय आवसीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी (अनवरत वृत्तिक शिक्षा समिति के साथ संयुक्त रूप से)
- मुम्बई में अंतरिक संपरीक्षा संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएआई के पश्चिम भारतीय क्षेत्रीय परिषद के साथ संयुक्त रूप से)।

7.6.5 ज्ञान पृष्ठ

वर्ष के दौरान, समिति ने अपने ज्ञान पृष्ठ को इधर-उधर की सामग्री जुटाकर व्यापक बनाया है। इसमें वर्तमान रूप से निर्देश-निबंधन समिति का संविधान, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, आंतरिक संपरीक्षा और एफक्यूएस संबंधी मानक और मार्गदर्शक टिप्पण की प्रस्तावना आदि जैसी जानकारी सम्मिलित की गई है।

7.6.6 वर्तमान परियोजना

वर्ष के दौरान, समिति ने आंतरिक संपरीक्षा, संबंधी निम्नलिखित प्रस्तावित मानकों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है:-

- आंतरिक संपरीक्षा के मूल उद्देश्य तथा शासी सिद्धांत।
- समग्र संपरीक्षा की योजना
- प्रलेखन
- आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण।

7.6.7 अन्य क्रियाकलाप

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित परियोजनाओं का भी अनुमोदन किया:—

- आंतरिक नियंत्रण अर्थात्, सूचीबद्ध करार का खंड 49, का प्रारूप निर्धारण
- बैंकिंग उद्योग में कोषागार के आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रारूप मार्गदर्शक टिप्पण।
- आंतरिक संपरीक्षा तथा निगमित शासन
- ◆ हार्ड नियंत्रण के प्रति साफ्ट नियंत्रण का महत्त्व।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 55वां वार्षिक समारोह 4 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में हुआ था। वाणिज्य और उद्योग संघ मंत्री माननीय श्री कमलनाथ मुख्य अतिथि थे। समारोह में आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट क्षेत्रीय परिषद और शाखाओं को शील्ड तथा प्रशंसा पत्र दिए गए। समारोह में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति पर प्रशंसा की बौछार लगा दी।

8.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस की याद में 1 जलाई, 2005 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। संघ के विधि और न्याय मंत्री, माननीय श्री एचआर भारद्वाज मुख्य अतिथि थे, माननीय श्री के.रहमान खान, एफसीए, उपाध्यक्ष राजसभा, माननीय श्री सुरेश प्रभु, एफसीए, संसद सदस्य और माननीय श्री सी. रामचन्द्रैया, एफएसीए, संसद सदस्य सम्माननीय अतिथि थे। उनके द्वारा विशेष अभिभाषण दिए गए। इसके अतिरिक्त, अनेक स्थानों पर शाखाओं में भी स्थानीय रूप से भव्य रूप से समारोह आयोजित किए गए।

इस अवसर की याद में आईसीएआई के मुख्यालय, प्रादेशिक कार्यालय और उनकी शाखाओं के भवनों का नाम आईसीएआई भवन रखा गया।

8.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

8.3.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम में संशोधन

जैसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में अवगत किया गया था कि संस्थान ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधन संबंधी कार्यकारी समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ 3 अगस्त, 2002 को प्रस्तुत कर दिया है। इसी बीच केन्द्रीय सरकार ने 3 दिसम्बर 2003 को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2003 को तैयार किया और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सभा में पेश किया था जिसे बाद में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। आईसीएआई की उक्त विधेयक पर प्रतिक्रिया पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। यह आशा की जाती है कि संशोधित अधिनियम किसी भी समय प्रवृत्त हो जायेगा।

8.3.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम 1988 में संशोधन

(1) वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विनियम 25 ख (2) और 28 ख (3) वृत्तिक शिक्षा के लिए प्रवेश मानदण्ड परीक्षा -I और वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा -II) और पीई-II परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात पदभार ग्रहण करने वाले आर्टिकल्ड क्लर्क के संदेय मानदेय की दर में वृद्धि करने के लिए विनियम 48 (1) में प्रारूप संशोधन को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। उक्त प्रारूप संशोधनों को अपनी-अपनी उन तारीखों जिनको उक्त प्रकाशन जनता को उपलब्ध कराए गए थे से 45 दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर छात्रों द्वारा सामना की जारी कठिनाईयों को दूर करने के लिए कार्यवाई प्रारंभ की जाएगी।

8.4 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय सदस्यों, छात्रों तथा संस्थान के विभिन्न निदेशालयों की फैंकल्टियों, सचिवों की विभिन्न समितियों, को पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और संदर्भ सुविधा प्रदान करता है तथा मुख्यालयों, विभिन्न विश्वविद्यालयों से अध्येतावृत्तिकों और पीई-1 पाठ्यक्रम के छात्रों को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है। पुस्तकालय सदस्यों को विभिन्न वृत्तिक जर्नलों तथा समाचार पत्रों से संकलित सामग्रियों की सूची तथा संदर्भ शीर्षक "एकाउंटेंट्स ब्रोसर" के अंतर्गत संस्थान के जर्नल में प्रत्येक मास प्रकाशित सामग्री की फोटो प्रति भी प्रदान करती है और इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान करती है डेलनेट के माध्यम से नेटवर्किंग भारत तथा विदेश में पुस्तकालयों को नेटवर्क प्रचालन में है तथा पुस्तकालय सामग्री का कम्प्यूटरीकरण किया

जा रहा है जिसमें पुस्तकें, जर्नल, आर्टिकलस, सदस्यों का अभिलेख पुस्तकालय साफ्टवेयर पर उपलब्ध है। 11000 से अधिक आर्टिकल का भण्डारण आधार, जिसके अंतर्गत आईसीएआई की पत्रिका "चार्टर्ड अकाउंटेंट" के आर्टिकल भी पुस्तकालय साफ्टवेयर में उपलब्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय ने 8000 से अधिक कंपनियों के प्रोवैस लेन वर्जन, कारपोरेट डाटावेश अर्जित किए हैं। विधि विनिश्चयों के लिए ग्रांड ज्यूरिक्स साफ्टवेयर, आईटीआर आन लाइन उत्पाद सीमा शुल्क तथा सेवा कर और अन्य सहबद्ध विधियों के इलेक्ट्रानिक पुस्तकालय हेतु एक्सस-ए साफ्टवेयर केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के विभिन्न विषयों पर सीडी के साथ भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय www.icaai.org में आने वाली वेब सेवाओं संस्थान की वेबसाइट में अकाउंटेंट्स ग्रोसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से आर्टिकल, विबलो ग्राफिक ब्यूरो - सम्मेलन / सेमिनार, पुस्तकालय में उपलब्ध सीडी, दि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडेक्स (आईसीएआई की पत्रिका) आईसीएआई के पीई-1, पीई-2 तथा अंतिम वर्ष के लिए सिफारिश की गई पुस्तकों की सूची, छात्रों/सदस्यों के पुस्तकालय प्रतिभूति निक्षेप नियम, पुस्तकालय समाचार और दृष्टिकोण, पुस्तकालय द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं/समाचार पत्रों की सूची; पुस्तकालय में उपलब्ध फोटोग्राफ, पुस्तकों के वर्तमान अंक, एसएएफए पुस्तकों की सूची, सुझाई गई पुस्तकें/पत्रिकाएं आदि सेवाओं को उपलब्ध करता है।

उपरोक्त के अलावा, पुस्तकालय, सुविधाएं संपूर्ण देश की प्रादेशिक कार्यालयों तथा शाखाओं में भी उपलब्ध है। कम्प्यूटीकरण करने के पश्चात विभिन्न प्रादेशिक पुस्तकालयों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए प्रयास जारी हैं। पुस्तकालय केन्द्रीय और प्रादेशिक पुस्तकालयों में सदस्यों और फैंकल्टियों के निर्देश के लिए आईएएसवी, आईएफएसी, एआईसीपीए, आईसीआईएंड डब्ल्यू, एएसवी और अन्य अंतराष्ट्रीय वृत्तिक निकायों से महत्त्वपूर्ण प्रकाशन डाउनलोड कर रहा है या प्राप्त कर रहा है।

8.5 संपादकीय बोर्ड

8.5.1 आईसीएआई के "दि चार्टर्ड एकाउंटेंट" पत्रिका इसके लिए ब्रांड अम्बेडर है। इसके अतिरिक्त, पत्रिका सदस्यों, छात्रों तथा बाहरी स्रोतों के लिए आईसीएआई की प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शित करती है अंतराष्ट्रीय मानक के लिए आईसीएआई की ब्रांड अम्बेसडर "दि चार्टर्ड अकाउंटेंट" पत्रिका निरंतर उत्साह से आगे बढ़ रही है। संस्थान के संपादकीय बोर्ड ने इस वर्ष विशिष्ट साहसिक कार्य किया है।

इसकी गुणवत्ता अंतर्वस्तु, तापिकल कवरेज, अंतराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण और अनेक लोगों तक पहुंच तथा समय पर आने के कारण, बोर्ड के सभी काउंटों पर लिपि तैयार की है।

वृत्तिक मानक के उच्चतर स्तर को ध्यान में रखते हुए, पत्रिका ने इस वर्ष न केवल सदस्यों के लिए अपितु सहबद्ध वृत्तिकों, संस्थानों तथा भारत और विदेश में इकोनोमिक विश्व के लिए भी जानकारी तथा वृत्तिक ज्ञान के और अधिक मूल्यवान दूल को विकसित किया है। इसकी व्यापक पहुंच और पठन आधार की दृष्टि से आज इस पत्रिका का कुल सर्कुलेशन 165,000 से अधिक हो गया है।

8.5.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संपादक बोर्ड की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार थी:-

(1) फीचर और आर्टिकल

- जुलाई, 2004 से जून 2005 की अवधि के दौरान विगत तत्स्थानी वर्ष के दौरान मुद्रित 1400 पृष्ठों की तुलना में 1760 पृष्ठों को मुद्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, गत पिछले वर्ष के दौरान, प्रकाशित 86 आर्टिकल की तुलना में 2002 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित किए गए थे। प्रकाशित आर्टिकल सदस्यों के लिए लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान तथा विधि वाले सभी सुसंगत विषयगत मुद्दों पर थे।
- अनेक नए फीचर तथा सैकसन जिसमें 'वृत्तिक होरिजन', 'टेक 4 यू' 'कैरियर वाच', 'लेखांकन और संपरीक्षा मानक', 'इंसाइड आईसीएआई', 'साक्षात्कार' और 'रीडर क्वैरीज' (बेहतर उत्तर सहित) आदि आरंभ किए गए हैं।
- अधिक सुसंगत तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से, बोर्ड ने मूल दिवस संबंधी मुद्दों को प्रकाशित करने का विनिश्चय किया है। पत्रिका में निम्नलिखित विषयवस्तु को सम्मिलित किया गया था:-

बजट 2004-05 - जुलाई 2004

कारपोरेट विधि - सितम्बर, 2004

कर सुधार और वित्त अक्टूबर, 2004

जोखिम प्रबंध - नवम्बर, 2004

वैकल्पिक दिवाद समाधान - दिसम्बर, 2004

संपरीक्षा क्वालिटी प्रबंध - जनवरी 2005

बैंकिंग और वित्त - फरवरी, 2005

संघीय बजट 2005–2006 मार्च, 2005

बैंक संपरीक्षा – अप्रैल, 2005

कारपोरेट गर्वनेंस – मई, 2005

मूल्यवर्धित कर – जून 2005

(2) अंशदाता

- भारत और विदेश के लेखांकन व्यापार, वाणिज्य बीमा तथा वित्त आदि के क्षेत्रों से प्रमुख व्यक्ति, विशेषज्ञ तथा प्रध्यापक वर्ग ने पत्रिका में अपना अंशदान किया है।
- विभिन्न वृत्तिक क्षेत्रों से विशेषज्ञ लेखकों के एक मानक पैनल को पत्रिका में प्रकाशन की क्वालिटी तथा विषय वस्तु की अंतर्वस्तु के लिए रखा गया है। इस संबंध में लेखकों के लिए एक व्यापक मार्ग दर्शक सिद्धांत भी तैयार किए गए हैं।
- आर्टिकलों के रिव्यूवरा के लिए मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। जबकि दो समीक्षकों द्वारा समीक्षा किए गए आर्टिकलों को प्राप्त करने के प्रस्ताव को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार किया गया है कि पत्रिका में त्रुटियां नहीं हैं।

(3) ले आउट, डिजाइन तथा मुद्रण

- पत्रिका के बेसिक ले आउट, डिजाइन, और आकार तथा हर भाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन को जुलाई, 2005 के विशेष अंक में करने की अनुमति दे दी गई है।
- 'एकाउंटेंसी प्रोफेसन इन ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव' विषय वस्तु पर जुलाई, 2005 पत्रिका का विशेष अंक लाने के लिए नए मुद्रण, प्रकाशन, प्रेषण तथा परिदान संबंधी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मान के नए आकार के अनुसार लाने की योजना है।
- संपूर्ण पत्रिका के 4 कलर फारमेट में प्रकाशित कने, बेहतर पेपर क्वालिटी, व्यापक प्रचार करने तथा विज्ञापन लाने तथा नए मुद्रण तथा प्रकाशन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक मास की पहली तारीख को पत्रिका का परिदान सुनिश्चित करने का विनिश्चय लिया गया है।
- अक्टूबर, 2004 अंक में पत्रिका की डिजाइन और

मस्तूल शिखर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी गई है। पत्रिका के पीछे नाम/ अंक संख्या / पत्रिका की कीमत देने वाला -स्पइन प्रिंटिंग माड्यूल सितम्बर, 2004 के अंक से प्रारंभ किया गया है। फरवरी 2005 के अंक से पत्रिका के कवर पृष्ठ को विश्वस्तर का बनाकर उसकी पुनः डिजाइन की गई है।

(4) अन्य पहल:

- विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों की संपूर्ण सूची को आईसीएआई की वेबसाइट पर डाला गया है तथा मार्च 2005 के अंक से पत्रिका में परिपत्र के प्रकाशन के अतिरिक्त उसे निरंतर मासिकवार अद्यतन किया जा रहा है।
- संसद के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सचिवों, मुख्य मंत्रियों तथा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के नामों को सम्मिलित किए जाने से पत्रिका का आधार व्यापक हुआ है।

9. सदस्य

9.1 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा 8778 सदस्यों को दर्ज किया गया। जिससे 1 अप्रैल, 2005 को उसके कुल सदस्यों की संख्या 1,23,546 हो गई।

पूर्व वर्ष में 3459 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 3246 सहयोजित सदस्य फैंलों के रूप में प्रविष्ट किए गए।

1.4.2005 को सदस्यों की संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	फैंलो	सहयोजित	स्तम्भों का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	45,586	21,283	66,869
अंशकालिक व्यवसाय में	3,521	7,768	11,289
जो व्यवसाय में नहीं हैं	6,387	39,001	45,388

9.2 चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स हितकारी निधि

दिसम्बर 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेन्ट हितकारी निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो आईसीएआई के सदस्य हैं या रहे हैं, उनके आश्रितों को उनके पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 31 मार्च, 2004 को 54,904 से बढ़कर 31 मार्च 2005 को 63,071 हो गई है। निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं:-

	31.3.2004 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.3.2005 को समाप्त वर्ष के दौरान
दी गई कुल वित्तीय सहायता	39,41,223	44,26,777
प्रशासनिक खर्च	4,77,879	5,40,441
निधि अधिशेष	13,91,599	13,81,087
निधि का अतिशेष	1,59,67,275	1,73,48,362
कोरपस का अतिशेष	4,10,49,000	4,94,54,000

10. छात्र

10.1 छात्रों की संख्या

1 अप्रैल, 2004 और 31 मार्च 2005 के दौरान पीई 1, पीई-2 और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए निमांकित छात्रों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:-

पाठ्यक्रम	2003-04	2004-05
पीई-1	38188	39000
पीई-2	30395	33063
आर्टिकल सहित पीई-2	3837	1127
फाइनल	11390	11061

अध्ययन बोर्ड के रजिस्टर में प्रविष्ट 31 मार्च, 2005 को छात्रों की कुल संख्या (उन छात्रों को छोड़कर जो वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1 के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं), 31 मार्च, 2004 को छात्रों की कुल संख्या 307462 की तुलना में 328550 थी।

10.2 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम I) के छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने के लिए 43 संस्थानों को तथा (पाठ्यक्रम-II) के लिए 30 संस्थाओं को (जिसमें 2 शाखाएं हैं) प्रत्यायन प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान फाइनल पाठ्यक्रम के लिए संस्थाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए 7 संस्थाओं का (एक शाखा सहित) प्रत्यायन जारी रहा। पीई-I और पीई-II पाठ्यक्रमों के लिए 10-10 संस्थाओं के नाम वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए वार्षिक चन्दा न देने के लिए निकाल दिए गए 31 मार्च, 2005 को वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम I) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 178 और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 95 है। नवम्बर 2004 में होने वाली परीक्षा के छात्रों के फायदे के लिए 36 संस्थाओं ने वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-I) की कक्षाएं और मई, 2005 की परीक्षाओं के लिए 57 संस्थानों ने कक्षाएं आयोजित की। 25 संस्थानों ने वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) की कक्षाएं नवंबर, 2004 की परीक्षाओं के लिए और 20 संस्थानों ने मई, 2005 की परीक्षाओं के लिए आयोजित कीं।

10.3 अध्ययन सामग्री की समीक्षा

समीक्षा की निरंतर प्रक्रिया के भागरूप में अध्ययन सामग्री की समीक्षा अनेक विषय-विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और उनकी टिप्पणियों एवं सुझावों को, जहां कहीं समुचित समझा जाता है, सम्यक संपादन और सत्यापन के पश्चात अध्ययन मॉड्यूल के अगले मुद्रण में सम्मिलित किया जाता है।

10.4 छात्रों की काउंसेलिंग

पाठ्यविवरणों की अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु प्रादेशिक मुख्यालयों में काउंसेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं।

10.5 250 घंटे का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 250 घण्टे के कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:

पश्चिमी क्षेत्र	4422
दक्षिणी क्षेत्र	3282
पूर्वी क्षेत्र	1691
मध्य क्षेत्र	2503
उत्तरी क्षेत्र	2305

छात्रों को, उनके निवास स्थान के समीप प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए अध्ययन बोर्ड ने प्रत्यायन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया है और नगर स्तर पर कार्य करने वाली 61 और संस्थाओं को (जिसके अंतर्गत 2 प्रादेशिक परिषदें और 7 शाखाएं हैं)। पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रत्यायन प्रदान किया है।

10.6 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर पाठ्यक्रम

साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान भाग लेने वाले 8000 व्यक्तियों के फायदे के लिए देश भर के 42 केन्द्रों पर पाठ्यक्रम के 175 बैच संचालित किए गए।

10.7 संगोष्ठियां और सम्मेलन

वर्ष के दौरान, बोर्ड, ने एक दिवसीय संगोष्ठियां, वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं और प्रादेशिक / राज्य स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन को बढ़ावा देने की नीति जारी रखी। 5 प्रादेशिक परिषदों और 25 शाखाओं द्वारा शाखा / प्रादेशिक स्तर पर वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। फाइनल वक्तृता / क्विज प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2005 में जोधपुर में हुआ।

- दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद चैन्नई पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद कोलकाता, पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद की बड़ौदा शाखा और दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की एर्नाकुलम शाखा ने क्रमशः 27/8.11.2004, 1.8.2004, 18/19.6.2004, 4/5.8.2004 और 5.12.2004 को प्रादेशिक/उपप्रादेशिक सम्मेलन

आयोजित किए। उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद की हिसार शाखा ने 20/21.8.2004 को राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया।

- जयपुर शाखा ने 17 और 18 जनवरी 2005 को चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया।
- अध्ययन बोर्ड द्वारा नागपुर में 17वां अखिल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया।
- 2 प्रादेशिक परिषदों और विभिन्न प्रादेशिक परिषदों की 23 शाखाओं ने एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किए। दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद और प्रादेशिक परिषदों की 8 शाखाओं ने अन्य शैक्षिक समारोहों का आयोजन किया।
- दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय और दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की त्रिचूर शाखा ने क्रमशः 18-19.12.2004 और 18.6.2004 को संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए।

10.8 छात्रवृत्तियां

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान 96 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं (24 गुणता छात्रवृत्तियां 4 गुणता एवं आश्रयता आधृत छात्रवृत्तियां, 68 आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां) इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न विन्यासों से प्राप्त आय में से 37 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

10.9 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलेटर)

मासिक सीए छात्र संवादपत्र — 'द चार्टर्ड एकाउंटेंट स्टूडेंट' जिसमें उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत उद्घोषणाएं हैं, छात्रों के लिए लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुईं। यह प्रकाशन सदस्यों में भी लोकप्रिय रहा।

सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार (2000 रुपये) सुश्री लक्ष्मी जयराम, कोच्चि को एसआईसीएसएस की एर्नाकुलम शाखा के संवादपत्र में प्रकाशित 'पियर रिवीव' पर उनके लेख के लिए दिया गया था।

10.10 रविवार परीक्षा पत्र स्कीम में खुली पुस्तक प्रणाली का प्रारंभ

कारबार और निगमित विधियों, कंपनी विधियों और सचिवालय प्रेक्टिस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए रविवार परीक्षा पत्र स्कीम में खुली पुस्तक प्रणाली प्रारंभ की गई है।

10.11 वास्तविक कक्षाओं का संचालन

प्रथम उद्घाटन कक्षा का संचालन 1 फरवरी, 2005 को किया गया। श्री आर भूपथी एक प्रख्यात संकाय और आईसीएआई के भूतपूर्व अध्यक्ष ने 'कारबार से आय पर कराधान में मुद्दे, पर एक व्याख्यान दिया।

10.12 वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2) के लिए पायलट आधार पर पात्रता परीक्षण के लिए ऑन लाइन परीक्षा

वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम -2) के सूचना प्रौद्योगिकी, आयकर और वित्तीय प्रबंध विषयों के लिए पात्रता परीक्षण हेतु 5 ऑन लाइन परीक्षाएं (20 बैंचों में) एक्सटर्नल वेंडर के सहयोग से संचालित की गई।

10.13 ऑनलाइन आपिनियन पोल

बोर्ड ने छात्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर राय लेने के लिए ऑन लाइन वेबपोल की एक श्रृंखला प्रारंभ की है।

10.14 छात्र अदला-बदली कार्यक्रम

छात्र अदला बदली कार्यक्रम के तत्वावधान में, एसएएफए सदस्य निकायों के 26 छात्र (आईसीएपी-7 आईसीएबी-4 आईसीएएन- 11 आई सीएएस एल-4) भारत आए और नागपुर में आयोजित 17वें अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट छात्र सम्मेलन में भाग लिया। आईसीएआई के 9 छात्र भी आईसीएपीके निमंत्रण पर जनवरी 2005 में लाहौर गए।

10.15 ई लर्निंग मॉड्यूल का विकास

उपलब्ध होने वाली प्रौद्योगिकी की नई किस्मों के कारण शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं वेब आधारित सिखाई सीडी रोम प्रशिक्षण और परस्पर क्रियात्मक कम्प्यूटर प्रेरणा, शिक्षा का भविष्य बदल रहे हैं। ई शिक्षा, अपने अनेक रूपों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रणाली का अभिन्न अंग बन रहा है। प्राथमिक स्तर पर आईसीएआई एक विनिर्दिष्ट से सृजित ई-मेल id guidance@icai.org के माध्यम से छात्रों से विचार-विमर्श कर रहा है। इसे फैकल्टी के एक परामर्शी समूह द्वारा मानिटर किया जाता है और छात्रों को आनलाइन सहायता प्रदान करता है। ऐसे छात्र, जिनके पास अपनी तैयारी के दौरान उत्पन्न विद्या संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस

स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने चार्टर्ड लेखाकर्म के वृत्तिक पाठ्यक्रम और वृत्तिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के छात्रों को मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने पर बदल देना जारी रखा है।

इसने चार अस्थाई समितियों अर्थात् संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड, वाणिज्य शिक्षा और कैरियर काउंसिलिंग समिति, वित्तीय बाजार और निवेशक सुरक्षा समिति तथा घनीय विधि समिति के कार्यकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा यह 'पीयर रिवीव' बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

बोर्ड, ऑन लाइन चैटिंग सृजित करने, पात्रता परीक्षण और पीई-2 तथा फाइनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की ऑनलाइन परिधि को विस्तृत करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

10.16 स्वयं विकास पुस्तिका श्रृंखला

वर्ष के दौरान संपरीक्षा दस्तावेजीकरण पर स्वयं विकास पुस्तिका निकाली गई।

10.17 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहकर्मी की भावना विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से लगाने की दृष्टि से आईसीएआई हमेशा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं खोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघों की 34 शाखाएं पहले ही स्थापित हो चुकी हैं।

10.18 एस.वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान, 300 रुपये प्रति छात्र प्रतिमास के मूल्य की 57 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी गई। निधि की सदस्यता 31 मार्च, 2004 को 346 के मुकाबले 31 मार्च, 2005 को 349 थी। निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2004 को 6,86,834 रुपये के मुकाबले 31 मार्च, 2005 को 9,02,384 रुपये थी।

10.19 सीए पाठ्यक्रम को पीएचडी कार्यक्रम के लिए मान्यता।

विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर सम्पर्क करने के बाद वाणिज्य शिक्षा और कैरियर काउंसिल समिति पी.एचडी/फैलो कार्यक्रम

के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अलावा 76 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रही है।

11. प्रादेशिक परिषद और उनकी शाखाएं

11.1 संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं।

11.1.1 प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 104 है।

11.1.2 फिलहाल भारत के बाहर संस्थान के 15 चैप्टर हैं।

11.1.3 फिलहाल पूरे भारत में 24 संदर्भ पुस्तकालय हैं।

11.2 शाखाओं के लिए भवन

वर्ष के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रुचि दिखाते रहे हैं कुल मिलाकर 47 शाखाओं के अपने भवन हैं।

11.3 चल शील्ड

संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद को हर वर्ष चल शील्ड देता है पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड प्रदान की जाती है। पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्रसंघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्रसंघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड वर्ष 1999 से चलाई गई है। 2004 के लिये यह शील्ड 4 फरवरी, 2005 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी:-

- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद: पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद।
- प्रादेशिक परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा: पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद की नागपुर शाखा।
- सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ — पश्चिम भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ
- छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा:

पश्चिमी क्षेत्र: डब्ल्यूआईसीएएसए की बड़ौदा शाखा।

दक्षिण क्षेत्र — एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा।

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से क्रमशः अत्यंत प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिए गए थे:-

- पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद की बड़ौदा शाखा
- दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की हुबली शाखा
- दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की सलेम शाखा।

11.4 नव विकेन्द्रीकृत कार्यालय

प्रादेशिक स्तर पर कार्य/क्रियाकलाप की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखकर और तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्त्व को मानते हुए जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सके हैं, आईसीएआई ने मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा दक्षिणी क्षेत्र में बैंगलूर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में मध्य क्षेत्र में जयपुर में, 5 और विकेन्द्रीकृत कार्यालय खोल चुकी है।

प्रादेशिक स्तर पर कार्य/क्रियाकलापों की वृद्धि पर विचार करते हुए सूरत, नागपुर और बड़ौदा (पश्चिमी क्षेत्र) एर्नाकुलम और कोयम्बूटर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य प्रदेश) और चण्डीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में सात और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

12 वित्त और लेखा

31 मार्च 2005 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है।

13. प्रशंसा

13.1 परिषद व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी हैं जिन्होंने संस्थान की समितियों पर सहयोजित सदस्य के रूप में कार्य किया है और उनका भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद के शैक्षिक तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परिक्षाओं के संचालन में वर्ष 2004-2005 के दौरान परिषद की सहायता की।

13.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2003-2004 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

13.3 परिषद् उन गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी शोभा बढ़ाई। परिषद् राज्य स्तर पर अनेक कृत्यकारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है। जिन्होंने आईसीएआई के अंगो द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई।

13.4 परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रुचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2004-2005 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय है।

सदस्यों के अंकड़े 1.4.1997 से

सारणी-1

वर्ष (को यथाअवमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1.4.1997	सहयुक्त	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	अध्येता	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	योग	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	सहयुक्त	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	अध्येता	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	योग	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	सहयुक्त	23194	14466	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1.4.2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546

सदस्यों के आंकड़े 1.4.1950 से

सारणी 2

	1.4.1950 को	1.4.1951 को	1.4.1961 को	1.4.1971 को	1.4.1981 को	
अध्येता	569	672	1590	3326	8642	
सहयुक्त	1120	1285	4059	7901	16796	
योग	1689	1957	5649	11227	25438	
	1.4.1991 को	1.4.01 को	1.4.02 को	1.4.03 को	1.4.04 को	1.04.05 को
अध्येता	22136	44789	47064	49637	52707	55494
सहयुक्त	36862	51603	54666	60619	63384	68052
योग	58998	96392	101730	110256	116091	123546

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रगति चार्ट 31.3.1996 से

	वर्ष 1995-96 के दौरान	वर्ष 1996-97 के दौरान	वर्ष 1997-98 के दौरान	वर्ष 1998-99 के दौरान
फाउंडेशन/पीई पाठ्यक्रम-1	29015	28209	37052	43809
इंटरमीडिएट/पीई पाठ्यक्रम-2	19288	21354	24652	28253
फाइनल	8675	9275	9394	12227
योग	56978	58838	71098	84289

	वर्ष 1999-2000 के दौरान	वर्ष 2000-01 के दौरान	वर्ष 2001-02 के दौरान	वर्ष 2002-03 के दौरान	वर्ष 2003-04 के दौरान	वर्ष 2004-05 के दौरान
फाउंडेशन/पीई (पाठ्यक्रम-I)	44180	35999	34215*	35524	38188	3900
इंटरमीडियट/पीई (पाठ्यक्रम-II)	27508	23405	29403**	33283	34232	34190
फाइनल	10787	9026	11524	11102	11390	11061
योग	82475	68430	75142	79909	83810	84251

1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) के 5006 छात्र भी शामिल हैं।

1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) के 11848 छात्र भी शामिल हैं।

उन्नीसवीं परिषद् की रचना (2005-06)

अध्यक्ष

श्री कमलेश एस. विक्रमसे
एफसीए

उपाध्यक्ष

श्री टी. एन. मनोहरन
एफसीए

अवधि

5 फरवरी, 2005 से आगे

सचिव

डा. अशोक हल्दिया

उन्नीसवीं परिषद् के सदस्य (2005-06)

निर्वाचित सदस्य :

श्री अभिजीत बंदोपाध्याय
श्री अमरजीत घोषड़ा
श्री अनुज गोयल
श्री चरनजोत सिंह नन्दा
श्री जी. रामास्वामी
श्री एच. एन. मोतीवाला
श्री हरिन्दरजीत सिंह
श्री जे. पी. गोखले
श्री जयदीप नरेन्द्र शाह
श्री के. पी. खंडेलवाल
श्री कमलेश एस. विक्रमसे
श्री मनोज फेडनिस
श्री पंकज इंदरचन्द जैन
श्री आर. एस. अडूकिया
श्री एस. गोपालाकृष्णन
श्री एस. संधानाकृष्णन
श्री एस. सी. वासुदेव
श्री शान्ति लाल दागा
श्री सुनील गोयल
श्री सुनील तलाटी
श्री टी. एन. मनोहरन

कोलकता
नई दिल्ली
गाजियाबाद
नई दिल्ली
कोयम्बटूर
मुम्बई
नई दिल्ली
मुम्बई
नागपुर
कोलकता
मुम्बई
इन्दौर
मुम्बई
मुम्बई
हैदराबाद
चैन्नई
नई दिल्ली
हैदराबाद
जयपुर
अहमदाबाद
चैन्नई

श्री उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
श्री वी मुरली	चैन्नेई
श्री वेद जैन	नई दिल्ली
मनोनित सदस्य	
सुश्री बुलबुल सेन (18.01.2005 से)	नई दिल्ली
श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
श्री के. सी. पाराशर	जोधपुर
श्री पवन कुमार शर्मा	गुवाहाटी
श्री सिद्धार्थ कुमार बिरला	नई दिल्ली
श्री टी. जी. श्रीनिवासन (18.11.2004 से)	नई दिल्ली
संपरीक्षक	
श्री शशि कुमार, एफसीए	नई दिल्ली
श्री मनु चड्ढा, एफसीए	नई दिल्ली

संपरीक्षकों की रिपोर्ट

- हमने 31 मार्च, 2005 को यथा-विद्यमान भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के संलग्न तुलनपत्र और साथ ही उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इसके साथ उपाबद्ध आय और व्यय और नकदी प्रवाह विवरण, जिसमें अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के कार्यालयों, कम्प्यूटर केन्द्रों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखा शामिल हैं, संपरीक्षा की और उनकी रिपोर्टों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय सम्यक्तः विचार किया गया। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंध मण्डल का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी संपरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
- हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत संपरीक्षा मानकों के अनुसार संपरीक्षा की। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम अपनी संपरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाएं और उसका पालन करें कि क्या वित्तीय विवरण अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। परीक्षण के आधार पर, संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में समर्थकारी रकम और प्रकटन साक्ष्य की जांच शामिल होती है। संपरीक्षा में, उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांत और प्रबंध मण्डल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन एवं समुच्चय वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि, हमारी राय के लिए हमारे द्वारा की गई संपरीक्षा एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।
- हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:-
 - हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
 - तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया, लेखा बहियों के अनुरूप है;
 - हमारी राय में लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे गए हैं;
 - हमारी राय में, तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण में सुसंगत लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
 - हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबद्ध अनुसूचियों सहित और लेखांकन के भागरूप में लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणों के साथ पठित विवरण सही और उचित मत व्यक्त करते हैं।

- (i) 31 मार्च, 2005 को यथा-विद्यमान कामकाज के तुलनपत्र के मामले में; और
- (ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यय के मुकाबले आय के आधिक्य में आय-व्यय लेखा के मामले में;
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह

ह/०

सीए शशि कुमार

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सदस्यता संख्या 86492

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 9 जुलाई, 2005

ह/०

सीए मनु चड्ढा

चार्टर्ड एकाउंटेंट

सदस्यता संख्या 80996

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान
31 मार्च, 2005 को यथा-विद्यमान तुलन-पत्र

	अनुसूची	रकम 31.3.2005	रकम (लाख रुपये में) 31.3.2004
निधियों के स्रोत			
पूँजीगत आरक्षितियां	I	4224.69	3800.12
साधारण आरक्षितियां	II	3002.01	2354.40
अन्य आरक्षितियां	III	99.11	87.68
उद्दिष्ट निधियां	IV	5835.19	5090.84
	योग	13161.00	11333.04
निधियों का उपयोग:			
<u>स्थिर आस्तियां</u>	V		
सकल ब्लॉक		5661.71	4237.54
न्यून: अवस्थुण		2408.74	1866.69
शुद्ध ब्लॉक		3252.97	2370.85
पूँजी अग्रिम सहित पूँजी प्रगति कार्य में निवेश:		2820.65	841.75
उद्दिष्ट निधि निवेश	VI	5835.19	5090.84
अन्य निवेश		2133.74	3644.40
		7968.93	8735.24
<u>वर्तमान आस्तियां, उधार और अग्रिम</u>			
निवेश से प्राप्य ब्याज		717.58	797.91
सूचियां	VII	287.25	270.87
प्राप्य लेखे	VIII	98.48	147.77
नकद और बैंक अतिशेष		620.78	605.22
उधार और अग्रिम	IX	1130.56	590.09
	उप-योग	2854.65	2411.86
<u>न्यून : वर्तमान दायित्व और प्रावधान</u>			
अग्रिम प्राप्त शुल्क/आय	X	2832.90	2034.61
व्यय के लेनदार		437.90	539.99
उपदान निधि के लिए प्रावधान		155.20	158.99
अन्य दायित्व		310.20	293.07
	उप-योग	3736.20	3026.66
शुद्ध वर्तमान आस्तियां		(881.55)	(614.80)
	योग	13161.00	11333.04
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वक्तव्य	XIV		
टिप्पणियां जो लेखाओं का अंग हैं	XV		
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं			

ह०/-
सीए दीपक दीक्षित
संयुक्त सचिव

ह०/-
सीए अशोक हल्दिया
सचिव
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ह०/-
सीए शशि कुमार
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 86492

ह०/-
सीए टी.एन मनोहरन
उपाध्यक्ष

ह०/-
सीए कमलेश एस विक्रम
अध्यक्ष

ह०/-
सीए मनु चड्ढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 9 जुलाई, 2005

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान
31 मार्च, 2005 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र

	अनुसूची	रकम 31.3.2005	(लाख रुपये में) रकम 31.3.2004
आय			
शुल्क	XI	7008.08	6355.99
प्रकाशन		374.02	444.60
संगोष्ठियां		1153.74	813.18
निवेशों पर ब्याज		313.67	420.15
अन्य आय	XII	385.23	365.51
पूर्व अवधि आय		34.97	16.00
	योग	9269.71	8415.43
व्यय			
वेतन और भत्ते		1812.89	1800.26
मुद्रण और लेखा सामग्री		1239.71	1036.12
संगोष्ठी व्यय		998.93	709.59
डाक, तार और दूरभाष		468.58	408.23
किराया दरें और कर		356.38	250.15
यात्रा और वाहन अंतर्देशीय		532.36	475.66
अंतर्राष्ट्रीय संबन्ध:			
यात्रा	97.93	57.76	
विदेशी वृत्तिक निकायों का सदस्यता शुल्क	54.09	54.08	
अन्य व्यय	12.31	164.33	8.21
मरम्मत और रखरखाव		202.34	206.65
प्रकाशन		149.92	129.88
अन्य प्रचालन व्यय	XIII	1493.94	1354.64
निर्वाचन व्यय			118.64
राष्ट्रीय निगमित शासन प्रतिष्ठान में अंशदान			100.00
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश की बिक्री में हानि			25.35
अवक्षयण और अपाकरण		549.79	301.66
पूर्व अवधि व्यय		44.68	33.71
	योग	8013.85	7070.59
	शुद्ध अतिशेष	1255.86	1344.84
निधियों / आरक्षितियों में विनियोजन			
शिक्षा निधि [नीति स. III (ख)]		538.69	527.71
कर्मचारी हितकारी निधि [नीति स. III (ग)]		10.00	9.65
साधारण आरक्षित		707.17	807.48
		1255.86	1344.84
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वक्तव्य	XIV		
टिप्पणियां जो लेखाओं का अंग हैं	XV		

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियों तुलन-पत्र का अभिन्न भाग है

ह०/-
सीए दीपक दीक्षित
संयुक्त सचिव

ह०/-
सीए अशोक हल्दिया
सचिव

ह०/-
सीए टी.एन मनोहरन
उपाध्यक्ष

ह०/-
सीए कमलेश एस विक्रम
अध्यक्ष

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह०/-
सीए शशि कुमार
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 86492

ह०/-
सीए मनु चड्ढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 9 जुलाई, 2005

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान
31, मार्च, 2005, को समाप्त नकदी प्रवाह विवरण

	2004-05	(लाख रुपये में)	2003-04
क. क्रियाशील कार्यकलापों में नकदी प्रवाह			
शुद्ध अधिशेष	1255.86		1344.84
समायोजन:			
अवस्थान और क्रमिक अपाकरण	549.79	301.66	
आस्थगित राजस्व व्यय	0.00	1.65	
निवेशों की बिक्री पर हानि	0.00	25.35	
निवेशों पर ब्याज	(313.67)	(420.15)	
	236.12		(91.49)
क्रियाशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व क्रियाशील लाभ	1491.98		1253.35
सूचियों में वृद्धि	(16.38)	(52.11)	
निवेशों में प्रोद्भूत ब्याज में कमी	80.33	200.86	
प्राप्य रकमों में कमी	49.29	(52.67)	
ऋणों और अग्रिमों में कमी	(540.47)	(33.68)	
अग्रिम रूप से प्राप्त शुल्क / आय में वृद्धि	798.29	5.09	
व्यय के लिए लेनदारों में कमी	(102.09)	(34.07)	
उपदान निधि के प्रावधान में कमी	(3.79)	(20.69)	
अन्य दायित्वों में कमी/वृद्धि	17.13	(13.79)	
	282.31		(1.06)
क्रियाशील कार्यकलापों से शुद्ध नकदी	1774.29		1252.29
ख. निवेशकारी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
स्थिर आस्तियों का अर्जन	(1431.91)	(982.19)	
प्रगति में पूंजीगत कार्य	(1978.90)	(135.54)	
निवेशों का अर्जन	766.31	(792.91)	
निवेशों पर ब्याज	313.67	420.15	
उद्दिष्ट निधि निवेशों से आय	302.26	271.47	
पूंजीगत प्राप्तियाँ	269.84	454.60	
निवेशों की बिक्री पर हानि	0.00	(25.35)	
निवेशकारी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी	(1758.73)		(789.77)
नकदी /नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / कमी	15.56		462.52
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	605.22		142.70
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	620.78		605.22

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वक्तव्य XIV
टिप्पणियाँ जो लेखाओं का अंग हैं XV
ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियाँ नकदी प्रवाह,
विवरण का अभिन्न भाग हैं

ह०/-
सीए दीपक दीक्षित
संयुक्त सचिव
हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
ह०/-
सीए शशि कुमार
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 86492

ह०/-
सीए टी.एन मनोहरन
उपाध्यक्ष

ह०/-
सीए कमलेश एस विक्रम
अध्यक्ष

ह०/-
सीए मनु चड्ढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता संख्या 80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 9 जुलाई, 2005

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची - I

पूँजीगत आरक्षितिया

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
(क) साधारण:		
आरम्भिक अतिशेष	1106.10	1097.50
जमा:		
सदस्यता शुल्क [नीति सं. III (क)]	24.05	20.67
— भवनों के लिए सदान	52.59	28.58
अंतरण		
साधारण आरक्षितियों से अंतरित	16.10	7.91
अन्य आरक्षितियों से अंतरित	0.77	—
उद्दिष्ट निधियों से अंतरित—अन्य	3.81	3.21
न्यून:		
ई.आई.आर.सी./चण्डीगढ़ की भूमि के मद्दे समायोजन	—	(51.77)
योग (क)	<u>1203.42</u>	<u>1106.10</u>

(ख) शिक्षा:

आरम्भिक अतिशेष	2694.02	1934.00
जमा: कम्प्यूटरीकरण निधि से अंतरित	—	401.83
[नीति सं. III (घ) (i)]	<u>327.25</u>	<u>358.19</u>
जमा: शिक्षा निधि से अंतरित	योग (ख)	<u>2694.02</u>
(नीति सं. III (घ) (iii))	<u>3021.27</u>	
सकल योग (क+ख)	<u>4224.69</u>	<u>3800.12</u>

अनुसूची - II

साधारण आरक्षितियां

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
आरम्भिक अतिशेष	2354.40	1609.96
जमा:		
आय:व्यय लेखा से विनियोजन	707.17	807.48
	707.17	807.48
न्यून अंतरण:		
उद्दिष्ट निधियों में अंतरण—अनुसंधान	1.25	1.97
उद्दिष्ट निधियों में अंतरण—पदक	0.06	3.09
उद्दिष्ट निधि में अंतरण—अन्य	28.53	44.25
अन्य आरक्षितियों में अंतरण	13.62	5.82
पूँजीगत आरक्षितियों में अंतरण—साधारण	16.10	(63.04)
योग	<u>(59.56)</u>	<u>(63.04)</u>
	<u>3002.01</u>	<u>2354.40</u>

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची - III

साधारण आरक्षितियां*

	रकम	रकम	(लाख रुपये में)
	31.3.2005	31.3.2004	रकम
आरम्भिक अतिशेष	87.68	77.14	
जमा अंतरण			
साधारण आरक्षितियों से अंतरण	13.62	13.62	5.82
न्यून अंतरण:			
पूजीगत आरक्षितियों में अंतरण	0.77		
-उद्दिष्ट निधियों - अन्य में अंतरण	—	(0.77)	0.05
वर्ष के दौरान शुद्ध जमा ह्रास		(1.42)	4.77
योग	99.11	87.68	

* अन्य आरक्षितियां वे आरक्षितियां हैं जैसे पुस्तकालय आरक्षितियां और कोचिंग कक्षा आरक्षितियां जैसा कि प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं की बहियों में अंकित हैं।

अनुसूची - IV

उद्दिष्ट निधियां

	रकम	रकम	(लाख रुपये में)
	31.3.2005	31.3.2004	रकम
अनुसंधान निधियां			
आरम्भिक अतिशेष	453.15	398.71	
साधारण आरक्षितियों से अंतरण	1.25	1.97	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	17.85	20.70	
वर्ष के दौरान आय	51.71	70.81	54.64
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(0.30)	(0.20)
उप-योग (क)	523.66	453.15	
लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन और भवन निधि			
आरम्भिक अतिशेष	257.77	238.57	
वर्ष के दौरान आय	19.90	19.20	
उप-योग (ख)	277.67	257.77	
कम्प्यूटरीकरण निधि			
आरम्भिक अतिशेष	—	371.89	
आय-व्यय लेखा से विनियोजन	—	—	
वर्ष के दौरान आय	—	29.94	29.94
न्यून: पूजीगत आरक्षितियों में अंतरण - शिक्षा नीति सं. III (घ) (i)			(401.83)
उप-योग (ग)	—	—	
शिक्षा निधि			
आरम्भिक अतिशेष	2663.85	2308.50	
आय-व्यय लेखों से विनियोजन [नीति सं. III (ख)]	538.69	527.71	
वर्ष के दौरान आय	205.65	744.34	713.54
न्यून: पूजीगत आरक्षितियों में अंतरण - शिक्षा नीति सं. III (घ) (iii)]	(327.25)	185.83	(358.19)
उप-योग (घ)	3080.94	2663.85	

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची - IV
उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपये में)

		रकम 31.3.2005		रकम 31.3.2004
पदक और पुरस्कार निधियां				
आरंभिक अतिशेष		79.18		57.48
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान		9.54	17.59	
वर्ष के दौरान आय		5.57	4.55	
साधारण आरक्षिति से अंतरण		0.06	3.09	25.23
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान	2.60		3.50	
समायोजन	0.90	(3.50)	0.03	(3.53)
उप-योग (ड)		90.85		79.18
विद्यार्थी छात्रवृत्ति निधियां				
आरंभिक अतिशेष		26.97		25.34
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान		—	0.91	
वर्ष के दौरान आय	2.08	2.08	2.07	2.98
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(0.87)		(1.35)
उप-योग (च)		28.18		26.97
पेंशन निधि				
आरंभिक अतिशेष		920.03		613.85
वर्ष के दौरान वृद्धियां	92.99		301.22	
वर्ष के दौरान आय	71.03	164.02	49.41	350.63
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(50.73)		(44.45)
उप-योग (छ)		1033.32		920.03
छुट्टी नकदीकरण निधि				
आरंभिक अतिशेष		356.31		278.12
वर्ष के दौरान वृद्धियां	66.20		89.62	
वर्ष के दौरान आय	27.51	93.71	22.39	112.01
न्यून: वर्ष के दौरान भुगतान		(38.53)		(33.82)
उप-योग (ज)		411.49		356.31
कर्मचारी हितकारी निधि				
आरंभिक अतिशेष		59.59		46.86
आय-व्यय लेख से विनियोजन (नीति सं. III (ग))	10.00		9.65	
वर्ष के दौरान आय	4.60	14.60	3.77	13.42
वर्ष के दौरान भुगतान		(0.51)		(0.69)
उपयोग (झ)		73.68		59.59
अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)				
आरंभिक अतिशेष		273.99		203.73
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	8.04		22.31	
वर्ष के दौरान आय	17.48		11.32	
अन्य आरक्षितियों से अंतरण			0.05	
साधारण आरक्षिति से अंतरण	28.53	54.05	44.25	77.93
न्यून: पूर्णगीत आरक्षितियों में अंतरण—साधारण	3.81		3.21	
समायोजन	0.12		0.22	
वर्ष के दौरान भुगतान	8.71	(12.64)	4.24	(7.67)
उप-योग (ञ)		315.40		273.99
सकल योग		5835.19		5090.84

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची V स्थिर आस्तियां	(रकम लाख रुपये में)									
	सकल ब्लॉक		अपाकरण ब्लॉक		शुद्ध ब्लॉक					
आस्तियां	वर्ष के दौरान बढ़ियां	समयोजन/अंतरण/विक्रय	31.3.2005 को लागत	1.4.2004 तक	अवसायन और वर्ष के दौरान	अंतरण/विक्रय	31.3.2005 तक	31.3.2005 को	31.3.2004 को	ह्रास के बाद
रु. प्रत आस्तियां										
1. भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली	214.70	(141.17)	100.43	0.00	-	-	0.00	100.43	214.70	
2. भूमि पट्टाधृत (टिप्पण सं.2.3.)	299.14	144.85	459.99	24.49	5.19	3.84	33.52	426.47	274.65	
3. भवन	1027.20	661.39	1852.15	357.72	65.82	8.57	432.11	1420.04	669.48	
4. विद्युत संस्थान और फिटिंग	198.65	0.23	245.13	85.85	13.06	(1.16)	97.75	147.38	112.80	
5. कंप्यूटर	965.02	-	1058.96	589.32	247.52	(0.77)	836.07	222.89	375.70	
6. वातावरणकूलन	202.76	(0.43)	293.16	81.52	25.62	(0.26)	106.88	186.28	121.24	
7. फर्नीचर और फिक्सचर	502.02	(2.96)	619.38	201.79	35.83	(4.09)	233.53	385.85	300.23	
8. लिफ्ट	80.63	-	101.65	22.31	7.57	-	29.88	71.77	58.32	
9. कार्यालय उपकरण	312.17	(9.52)	332.78	169.71	22.93	(6.21)	186.43	146.35	142.46	
10. वाहन	31.30	(0.23)	31.34	13.37	3.60	(0.05)	16.92	14.42	17.93	
11. पुस्तकालय की पुस्तकें	278.94	(7.61)	307.60	278.94	36.27	(7.61)	307.60	0.00	0.00	
ख. अप्रत आस्तियां	125.01	119.63	259.14	41.67	86.38	-	128.05	131.09	83.34	
साफ्टवेयर										
योग	4237.54	764.18	5661.71	1866.69	549.79	(7.74)	2408.74	3252.97	2370.85	
गत वर्ष के अंकड़े	3207.09	1032.50	4237.54	1565.51	301.66	(0.48)	1866.69	2370.85	1641.58	

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची - VI

निवेश

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)		
(I) यूनिट 2002/1964 योजना	—	0.61
(II) भारत सरकार 8 प्रतिशत (कराधेय) बाण्ड - 2003	2400.00	1100.00
(III) अनुसूचित बैंको में निश्चितकालीन निक्षेप	3909.12	5112.04
ख. चालू निवेश		
अनुसूचित बैंकों निश्चितकालीन निक्षेप	1659.81	2522.59
कुल निवेश	<u>7968.93</u>	<u>8735.24</u>
आबंटन:-		
उद्दिष्ट निधि निवेशों को आबंटित	5835.19	5090.84
अन्य निवेशों को आबंटित	2133.74	3644.40
योग	<u>7968.93</u>	<u>8735.24</u>

अनुसूची - VII

सूचियां

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		
अध्ययन सामग्री और प्रकाशनों के लिये कागज	176.88	166.39
(जिसमें मुद्रकों के पास कागज का भण्डार	90.64	83.88
- 81.63 लाख रु. पूर्व वर्ष 78.94 लाख रुपये शामिल हैं)		
लेखन सामग्री और अन्य मदें	19.73	20.60
योग	<u>287.25</u>	<u>270.87</u>

अनुसूची VIII

प्राप्य लेखे

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
अन्य प्राप्य	104.68	155.37
न्यून: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(6.20)	(7.60)
योग	<u>98.48</u>	<u>147.77</u>

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची IX

उधार और अग्रिम (प्राप्य-योग्य)

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.03.2004
कर्मचारियों को अग्रिम	228.16	233.18
कर्मचारियों के उधार से वसूलनीय ब्याज	86.18	77.39
प्रतिभूति निक्षेप	31.92	18.95
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान	784.30	260.57
योग	1130.56	590.09

अनुसूची - X

अग्रिम प्राप्त शुल्क / आया

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
परीक्षा शुल्क	1306.74	843.38
पत्रिका अभिदान	4.12	0.53
सदस्यता शुल्क / छात्र शुल्क	369.90	358.79
टयूशन शुल्क	951.07	590.62
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	101.54	125.49
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	16.89	58.44
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यूटीओ पाठ्यक्रम	3.40	-
संगोष्ठी शुल्क और अन्य संग्रहण	79.24	57.36
योग	2832.90	2034.61

अनुसूची - XI

शुल्क

(लाख रुपये में)

	रकम	रकम
	31.3.2005	31.3.2004
सुदूर शिक्षा शुल्क	2154.77	2110.83
परीक्षा शुल्क	2227.58	1672.52
सदस्यता शुल्क	1359.13	1310.79
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम शुल्क	490.80	647.77
सामान्य प्रबंध कौशल पाठ्यक्रम शुल्क	418.77	335.16
कोचिंग कक्षा आय (प्रादेशिक परिषद और शाखाएं)	237.11	192.08
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	75.59	58.89
छात्र पंजीकरण शुल्क	9.87	10.97
सी.ए.ए.टी. पाठ्यक्रम शुल्क	20.32	8.26
प्रवेश शुल्क	8.78	6.89
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टीओ पाठ्यक्रम	3.40	-
छात्र संघ शुल्क	1.96	1.83
योग	7008.08	6355.99

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान

अनुसूची - XII

अन्य आय

	रकम	(लाख रुपये में)
	31.3.2005	31.3.2004
छात्र सूचना पत्र	10.29	8.83
पत्रिका से आय—अभिधान सूचना पत्र	104.48	75.81
(प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	33.18	23.31
कम्प्यूटर केन्द्र	44.62	36.61
अनुशासन संबंधी मामले दाखिल करने का शुल्क	0.22	0.35
कैम्पस साक्षात्कार	72.53	51.70
विशेषज्ञ सलाहाकर समिति शुल्क	9.80	5.45
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज	15.47	15.21
अब अपेक्षित नहीं उपबंध प्रतिलिखित	6.21	35.88
अन्य	88.43	112.36
योग	385.23	365.51

अनुसूची - XIII

साधारण और प्रशासनिक व्यय

	रकम	(लाख रुपये में)
	31.3.2005	31.3.2004
परीक्षकों, परामर्शदाताओं और अन्य को शुल्क एवं व्यय	798.39	743.76
सामान्य प्रबंध कौशल पाठ्यक्रम	264.00	217.73
कोचिंग कक्षा व्यय (प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं)	133.14	110.46
विज्ञापन	43.49	63.42
कार्यालय बैठक व्यय	52.64	38.08
कम्प्यूटर केन्द्र	20.69	15.64
योग्यता छात्रवृत्ति	1.46	2.20
संपरीक्षा शुल्क		
—प्रधान कार्यालय	2.48	2.43
—अन्य कार्यालय	5.96	5.19
आस्थायिक राजस्व व्यय	—	1.65
अन्य व्यय	171.69	154.08
योग	1493.94	1354.64

अनुसूची XIV

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विवरण:

I. लेखांकन कन्वेंशन

लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं और जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोदभवन आधार पर हैं।

II. राजस्व मान्यता

- (क) सहयोजित सदस्यों से प्रवेश शुल्क का एक तिहाई भाग आय मानी जाती है।
- (ख) वार्षिक सदस्यता शुल्क, व्यवसाह प्रमाण पत्र के लिये शुल्क, टयूशन शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और पत्रिका के लिए अभिदाय प्रथम वर्ष में प्रतिनिधित्व किए जाने की सीमा तक तुल्य संकल्पना के आधार पर आय माने जाते हैं, अतिशेष प्राप्तियां आगामी वर्ष/ वर्षों में अग्रणीत की जाकर सुसंगत वर्ष में तुल्य संकल्पना के आधार पर आय माने जाते हैं।
- (ग) निवेशों से आय
- (i) यूनिटों में किए गये निवेशों पर लाभांश को प्राप्त करने के हकदारी के आधार पर आय माना जाता है।
- (ii) बैंकों में ब्याज धारित प्रतिभूतियों और निश्चितकालीन निक्षेपों पर ब्याज से आय को प्रोद्भूत के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- (iii) निवेशों से होने वाली आय को संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेषों पर भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों में आवंटित किया जाता है।

III पूंजीगत आरक्षिति और उद्दिष्ट निधि में आवंटन / अंतरण

- (क) अध्येता सदस्यों से प्रवेश शुल्क और सहयोजित सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे पूंजीगत आरक्षिति - साधारण में लिया जाता है।
- (ख) भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिय वर्ष के दौरान प्राप्त दान अपने-अपने आरक्षिति लेखा में प्रत्यक्षतः चले जाते हैं।
- (ग) सुदूर शिक्षा शुल्क का 25 प्रतिशत जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है।
- (घ) वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क (सहयोजित और अध्येता तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र शुल्क) का 0.75 प्रतिशत कर्मचारी हितकारी निधि में आवंटित किया जाता है।
- (ङ) निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों में से पूंजीगत आरक्षिति - शिक्षा में अंतरण
- | | |
|---|---|
| (i) कम्प्यूटरीकरण अनुसंधान प्रतिष्ठान निधि में से | विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना के संबंध में कम्प्यूटरों और साधित्रों की क्रय लागत का 100 प्रतिशत। |
| (ii) लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान में निधि में से | स्थिर आस्ति और लेखांकन अनुसंधान निधि फाउंडेशन से संबंधित अन्य भवनों की लागत का 100 प्रतिशत। |
| (iii) शिक्षा निधि में से | अन्य स्थिर आस्तियों की अतिरिक्त लागत (कटौती के पश्चात शुद्ध) का 50 प्रतिशत। |

IV. स्थिर आस्तियां / अवक्षयण

- (क) पट्टाधृत भूमि को छोड़कर स्थिर आस्तियां मूल लागत में से अवक्षयण घटाने पर वर्णित की जाती हैं।
- (ख) पट्टाधृत भूमि, पट्टा अधिकार अर्जित करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर वर्णित की जाती है। इस प्रकार प्रीमियम का पट्टा अवधि के दौरान क्रमिक अपाकरण किया जाता है।
- (ग) वृद्धियों पर अवक्षयण का मासिक आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।
- (घ) अवक्षयण अवलिखित मूल्य पद्धति से संस्थान की कार्य समिति/परिषद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर लगाया जाता है जो अपनी-अपनी आस्तियों के उपयोगी जीवन पर आधारित होती है:—

भवन	5 प्रतिशत
वातानुकूलक और कार्यालय उपकरण	15 प्रतिशत
लिफ्ट, विद्युतीय अधिष्ठान, फर्नीचर और फिक्सचर	10 प्रतिशत
वाहन	20 प्रतिशत
कम्प्यूटर	60 प्रतिशत

- (ङ) अमूर्त आस्तियों (साफ्टवेयर) की तीन वर्षों में समान रूप से क्रमिक अपाकरण किया जाता है।

V. निवेश

- (क) एक वर्ष से अधिक की अवधि तक के लिए धारित या धारित किए जाने के आशयित निवेशों को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है और निवेशों का मूल्य लागत पर अवधारित किया जाता है। अस्थायी से भिन्न मूल्यों में कमी का उपबंध है।
- (ख) चालू निवेश उचित मूल्य या कमतर लागत पर निकाला जाता है।

VI. सूचियां

कागज, लेखन सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की सूचियों का मूल्यांकन कमतर लागत पर या शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है। लागत एफ.आई.एफ.ओ. तरीके से अवधारित की जाती है।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- क. विदेशी मुद्रा में नामित संव्यवहार साधारणतया संव्यवहार के समय प्रचलित विनियम दर पर अभिलिखित किए जाते हैं।
- ख. विदेशी कार्यालयों की आय और व्यय औसत दर पर स्थानांतरित किए जाते हैं। इसकी धनीय आस्तियां और दायित्व वर्ष के अंत की दरों पर स्थानांतरित किए जाते हैं। गैर-धनीय मदों का स्थानांतरण संव्यवहार की तारीख की दरों पर किया जाता है।
- ग. समझौता या संव्यवहार पर विनिमय अंतर के कारण कोई आय या व्यय की लाभ या हानि के लेखा में माना जाता है।

VIII. सेवांत /सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं

- क. उपदान के मद्दे वर्ष का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और इसके लिए जीवन बीमा को किया गया अंशदान आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है।
- ख. पेंशन और छुट्टी नकदीकरण मद्दे वर्ष का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और इस प्रकार अवधारित रकम आय और व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा इसके लिए पृथक उद्दिष्ट निधियां रखी जाती हैं।

अनुसूचि XV**लेखाओं के भागरूप टिप्पणियां****1. आकस्मिक दायित्व**

- 1.1. तीन शाखाओं की बाबत सम्पत्ति /भवन कर संबंधी विवादग्रस्त रकम मद्दे 24.68 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष में 19.50 लाख रुपये);
- 1.2. विभिन्न पक्षकारों से दावों की बाबत 17.75 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में 17.75 लाख रुपये) संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

2. टिप्पणियां

- 2.1. पूंजीगत प्रतिबद्धता की प्राक्कलित रकम (अग्रिमों के पश्चात शुद्ध) – 66.54 लाख रुपये है (पूर्व वर्ष में 227.80 लाख रुपये)
- 2.2. पट्टाधृत भूमि में मुकदमे के अधीन हुबली स्थित भूमि से संबंधित 2.51 लाख रुपये (पूर्व में 2.51 लाख रुपये) शामिल हैं इस भूमि का कब्जा अभी संस्थान को दिया जाना शेष है।
- 2.3. संस्थान, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वृत्ति विनियमित करता है और भारत में प्रधान रूप से एक कारोबार खण्ड चलाता है।
- 2.4. आईसीए आई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान को ऋण और अग्रिमों में 589.93 लाख रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम (पिछले वर्ष 24.69 लाख रुपये) शामिल है।
- 2.5. अवधि पूर्व आय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

	2004-05	2003-04
	(लाख रुपये में)	(लाख रुपये में)
परीक्षा शुल्क	46.66	—
संगोष्ठी आय	(17.63)	—
अन्य	5.94	16.00
योग	<u>34.97</u>	<u>16.00</u>

अवधि पूर्व खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

अवक्षयण / अपाकरण	12.53	—
आईएसए व्यय	—	11.97
संगोष्ठी व्यय	4.20	—
अन्य	27.95	21.74
योग	44.68	33.71

- 2.6 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) (iv) के अधीन अन्य छूट को ध्यान में रखते हुए आयकर /आस्थगित कर आस्ति /दायित्व के लिए उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया।
- 2.7 एस-3 का अनुपालन किया गया और नकदी प्रवाह विवरण अवधारित करने के लिए अप्रत्यक्ष रीति उपयोग की गई।
- 2.8 प्रकाशन और संगोष्ठियों की गतिविधियों पर केवल प्रत्यक्ष होने वाले व्यय, व्यय के इन शीर्षों पर क्रमशः प्रभारित किए गए हैं और इन गतिविधियों पर होने वाले अप्रत्यक्ष व्यय के क्रिया शील शीर्ष पर प्रभारित किए गए हैं।
- 2.9 जहां कहीं चालू वर्ष की प्रस्तुति से गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना आवश्यक समझी गई वहां इन आंकड़ों को पुनः समूहित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

[विज्ञापन III/IV/104/2005-असाधा.]

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2005

(Chartered Accountants)

No.1-CA(5)/56/2005 — In pursuance of Sub-section(5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949 a copy of the Report and the Audited Accounts of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2005 is hereby published for general information.

56th ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has immense pleasure in presenting its 56th Annual Report for the year ended 31st March, 2005. The ICAI, which was set up by an Act of Parliament on 1st July, 1949, entered into its 56th year of existence during the year. The Council, at the outset, commends the members and students for the position which the Chartered Accountancy profession occupies and the role it plays today in the growth and development of Indian economy. The changing world trade order is likely to unfold plethora of choices and opportunities for the accounting profession which is a core driver to sustenance of financial discipline.

Globalization has altered the pattern of economies world over. No economy can afford to remain insular today. Service sector which is the largest and most rapidly expanding sector in most economies has been dominating the economic activities of countries at every stage of development. Globally, the trend is clear: as national economies develop and incomes rise, the commercial service sector accounts for a ever larger share of GDP. In India also, the service sector has already accounted for over 52% of GDP in 2004-2005 and export of services also witnessed one of the fastest rates of growth in the world. Given the India's vast pool of talented professionals in a wide range of services, India enjoys tremendous potential in export of services.

ICAI believes that given an enabling framework, the profession in India will rise to

the occasion and has the propensity to blossom into an internationally competitive profession. Proactive measures at the macro and micro levels are already on and are slated to be further intensified to gear up to meet the imperatives of a truly globalised accounting profession. The role of Chartered Accountancy profession in this new milieu, as a natural corollary, becomes multi-pronged. ICAI sees progressive liberalisation of accountancy services on reciprocal basis, as an opportunity for the profession in India rather than as a threat.

With that perspective, the Report highlights the important activities of the Council and its various Committees for the year 2004-2005, and, in brief, upto end of June, 2005. The Report also covers important events and statistical profile relating to members and students for the year.

The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The Report also covers the seminars and conferences organised, training programmes conducted, relevant statistics relating to members and students and also the accounts of the ICAI for the year 2004-2005. The important activities and major initiatives of the ICAI upto end of June, 2005 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

The Nineteenth Council was constituted on 5th February, 2004 for a period of three years. In terms of the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council should be composed of 30 members — 24 elected

members and 6 members to be nominated by the Central Government. The composition of the Council for the year 2005-2006 commencing from 5th February, 2005 is shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted on 5th February, 2005 three Standing, and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. Subsequently, a Committee on Accounting Standards for Local Bodies, Autonomous Bodies and Not-for-profit organizations was also constituted. During the year ended 31st March, 2005, 164 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 132 meetings held during the year ended 31st March, 2004.

3. AUDITORS

Shri Shashi Kumar, FCA and Shri Manu Chadha, FCA were the Joint Auditors of the ICAI for the financial year 2004-2005. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters and overseas offices and those connected with employees, maintenance of accounts etc.

Some of the important recommendations made by the Committee to the Council are on matters relating to:

- Capacity Building Measures of CA Firms in respect of Network amongst the firms registered with ICAI, Merger & Demerger of firms.
- Granting of permission to the chartered accountants in practice to act as Insurance Agents/Advisors/Brokers (Based on recommendation of Committee on Insurance).
- Taking on record the particulars of merged/merging firms of chartered accountants including that of date(s) of joining partner(s) of merging firm(s).
- Allowing the students to undertake articulated training upto a maximum period of three months with members of other SAFA member bodies, who are eligible to train students in their respective country and treating such training as equivalent to the training required to be served by the students for becoming members under the respective statute.
- Grant of waiver to physically handicapped students for undergoing the Course on General Management and Communication Skills (Based on the recommendation of Board of Studies).
- Relaxation of condition for appearance in the Final Examination for the first time (Based on the recommendation of Board of Studies).
- Relaxation – general/specific of condition(s) for registration/re-registration of candidates of PE II examination (Based on the recommendation of Board of Studies).

Some of the important tasks accomplished/initiatives undertaken by the Committee during the period under Report are on matters relating to :

- Grant of exemption from payment of tuition and registration fees to the children of

military and para-military forces killed in action.

- Revision of various grants payable to Regional Councils & Branches and Review of Guidelines for release of library and reading room grants.
- Opening of a Chapter of the Institute at Nigeria.
- Setting up of branches at Vasai and Thane in Western Region.
- Setting up of decentralised offices at Chandigarh, Indore, Surat, Vadodara and Ernakulam.
- Setting up of a reference library at Pimpri in Western Region.
- Setting up of a reference library at Gorakhpur in Central Region.
- Naming of all buildings of the Institute as 'ICAI Bhawan'.
- Establishment of Continuing Professional Education (CPE) Cell at the Regional Councils for better co-ordination and execution of increasing activities between Central Council Committees, Regional CPE Committee and Branches.
- Development of Information Technology Security Policy and Audit for ICAI.
- Institutionalization of Annual awards for best CMD/CEO/CFO for members of ICAI in industry.
- Induction Ceremony to be organised at Regional Council level, twice in a year, to welcome the fresh entrants to the profession.
- Revised guidelines on functioning of Chapters.
- Release of grant to Branches for undertaking students related educational activities.

4.2 Examination Committee

The Chartered Accountants Final, Professional Education - II and Professional Education - I

Examinations were held in November, 2004 in 143, 157 and 136 centres respectively in 94 cities all over the country in addition to those at Dubai and Kathmandu and in May, 2005 in 150,163 and 151 centres respectively spread over 94 cities in addition to those at Dubai and Kathmandu.

The total number of candidates who appeared in the Final, Professional Education - II and Professional Education - I Examinations held in November 2004 were 29427,51057 and 14695 respectively and in May 2005 were 30027, 49326 and 26508 respectively.

Besides the aforesaid students' examinations, during the period, Assessment Tests of the Post Qualification Course on Information Systems Audit were also held in the months of June, September, and December 2004 and March and June 2005. Further, examinations of Management Accountancy Course (Part I) were held in May and November 2004 and May 2005 apart from the Corporate Management Course (Part I) and Tax Management Course (Part I) examinations, which were also conducted along with the students' examinations in May 2005. The Post Qualification Course examination in Insurance and Risk Management was also successfully held in November 2004 and May 2005.

New examination centres were set up in Amravati, Jamnagar, Sangli and Thane with effect from November 2004 examinations and in Guntur, Pimpri-Chinchwad and Sri Ganganagar with effect from May 2005 examinations.

During the period under Report, for the convenience of the candidates, the following facilities were continued to be provided :-

- Examination application forms in the OMR format and the admit cards containing the candidate's scanned photograph and specimen signature were issued to the candidates. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.

- Examination application forms were made available, besides at all the Regional offices of the Institute and branches of the Regional Councils, at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. The facility of downloading the admit card from the website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form was extended.
- Results were made available on the Institute's IVR system. The results as well as the marks were also made available on the National Informatics Centre's Website. Information pertaining to merit list was also made available on the Website simultaneously with declaration of results
- Results as well as marks were made available simultaneously at different locations in the metropolis of Delhi and Mumbai
- Facility of down loading of the results as well as marks by the Regional offices of the ICAI and branches of Regional Councils was made available simultaneously with the declaration of results
- Facility of on-line printing of the statement of marks by the candidates themselves from the Website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by the candidates in the OMR/ICR application form was made available.
- Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was continued and candidates registering for the same were provided with their results by e-mail immediately after declaration of respective results.
- Admit card through e-mail query was extended to the students for November 2004 and May 2005 examinations.
- Results of November 2004 examinations were made available on SMS mode.

- Students of Professional Education Examination –I were offered the facility of online filling of examination application effective from the November 2004 examination.

Consultancy continued to be provided to few of the foreign institutions in the examination systems and procedures. The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) successfully conducted its Foundation, Intermediate and Final examinations in June 2004 and December 2004 with the continued technical expertise and support of the ICAI. The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka successfully conducted its Information Systems Audit (ISA) Assessment Tests in March and June 2005 with the technical expertise and support of the ICAI.

4.3 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the ICAI. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year 1st April, 2004 to 31st March, 2005, this Committee held sittings on 13 occasions for a period spanning 20 days and at venues covering the various regions of the country. During the year, the Committee concluded its enquiry in 100 cases, which included cases, referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards

The Council of the ICAI, recognising the need to harmonise the diverse accounting policies and practices in use in India, constituted the Accounting Standards Board (ASB) in the year 1977. The Board, since its inception, has been striving for bringing about an overall qualitative improvement in financial reporting in the country by developing Accounting Standards

(AS) and promoting the use of those standards. Towards this end, the Board has formulated 29 Accounting Standards till date which have been issued under the authority of the Council of the ICAI. Work on some other Indian Accounting Standards corresponding to International Financial Reporting Standards (IFRSs) is under progress to bridge the gap between IFRSs and Indian Accounting Standards. Further, the objective of the Board is not only to bridge the gap between Indian Accounting Standards and International Financial Reporting Standards by issuance of new accounting standards but also to ensure that the existing Indian accounting practices are in line with the changes in international thinking on various accounting issues. Keeping in line with this, the Board has issued revised Accounting Standards from time to time. The standards, which have been revised in the recent years, are (AS) 7, Construction Contracts, AS 11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates and AS 15, Employee Benefits. Besides this, certain other existing Accounting Standards are also under revision.

The Board has also been constantly striving for effective implementation of new/revised Accounting Standards. With the issuance of new accounting standards and the revision of existing ones, certain issues of interpretation and application of the accounting principles enunciated in the standards have arisen. To resolve these problems and to ensure effective implementation of accounting standards, the Board has taken a number of proactive steps by formulating Accounting Standards Interpretations (ASIs) on matters related to accounting standards. An ASI has the same status as that of the relevant accounting standard. So far, twenty-eight Accounting Standards Interpretations on various intricate interpretational issues arising in the implementation of new accounting standards have been issued. Besides this, it has also issued a number of Announcements clarifying certain provisions of Standards. During the year, the Board continued its endeavours towards issuing new/revised accounting standards and providing interpretations, wherever required. A brief overview of the work

done by the Accounting Standards Board during the period under Report is as follows:

5.1.1 Revised Accounting Standard Released

Accounting Standard (AS) 15 (revised 2005), Employee Benefits, has been issued.

5.1.2 Proposed new/revised Accounting Standards Interpretations expected to be issued soon

The Board has finalised the Drafts of three Accounting Standards Interpretations (ASIs) on various accounting matters arising from the Accounting Standards, for consideration of the Council. These new/revised interpretations are likely to be issued soon and it would ensure that the relevant accounting principles are interpreted in the same manner with a view to uniform application thereof by all concerned. Besides this, interpretations on some other matters are also under preparation.

5.1.3 Applicability of Accounting Standards to Small and Medium Sized Enterprises

Keeping in view the concerns being expressed by various sections of the society, regarding the applicability of accounting standards to Small and Medium sized Enterprises (SMEs), the Board, during the last year, had decided to provide relaxations from disclosure requirements to SMEs. The Council of the Institute has given directional clearance to the matter relating to providing exemptions/relaxations, where appropriate, to SMEs from the recognition and measurement principles contained in Accounting Standards. The Board has constituted a study group to examine all accounting standards for identifying areas where exemptions/relaxations may be provided from recognition and/or measurement principles to SMEs.

5.1.4 Limited revisions to Accounting Standards

The Board also made limited revisions to certain accounting standards wherever it is felt that the revised position is more appropriate in view of the changed thinking in respect of the matters

involved and feedback received from various interest groups. Limited revision has been made to Accounting Standard (AS) 26, Intangible Assets.

5.1.5 Issuance of Announcements

With a view to address the matters of clarificatory nature raised by the members and others, the Board issued Announcements on accounting matters arising from various accounting standards. Besides this, Announcements on certain accounting matters are under preparation and will be issued shortly.

5.1.6 Responding to International Developments

The Board took various initiatives to keep pace with the developments that are taking place internationally in the area of accounting. These initiatives include sending comments on various exposure drafts issued by the International Accounting Standards Board (IASB), taking up projects on new International Financial Reporting Standards (IFRSs) issued by the IASB, examination of revisions made to various International Accounting Standards (IASs) by the IASB for considering the same in the revisions of the corresponding Indian Accounting Standards.

5.1.7 Interaction with National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS)

The Board considered various suggestions made by the NACAS and addressed these suggestions in an appropriate manner.

5.1.8 Interaction with Regulatory Bodies

The Board sent its views on various accounting matters referred to it by regulators such as Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), etc. from time to time. One of the important developments was that the RBI, vide its circular, required the banks to comply with the revised Accounting Standard (AS) 11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

5.1.9 Projects in Progress

A substantial progress has been made on various projects, particularly, on accounting for financial instruments, tangible fixed assets and presentation of financial statements.

5.1.10 Compendium of Accounting Standards

An updated edition of Compendium of Accounting Standards as on July 1, 2005, is under preparation and is likely to be released shortly alongwith a Compact Disk (CD).

5.1.11 New projects taken up by the Board

The Board has undertaken a new project for preparation of Accounting Standard on Investment Property, corresponding to IAS 40, Investment Property.

5.2. Auditing and Assurance Standards Board.

The credibility of any profession rests on the confidence reposed by the entire society. The prerequisite for any profession to stand up to the expectations of the society is that the profession should be able to proactively respond to as well as keep itself abreast with the latest developments in the environment in which it operates. In order to live up to the expectations of the society, the ICAI has always taken timely and effective steps to understand and react to the dynamic, technical, legislative, economic environment around it – domestic as well as international. The ICAI established, among other Committees and Board, the Auditing and Assurance Standards Board (AASB). The AASB was constituted as a technical organ of the ICAI in September 1982 in the form of a Non-Standing Committee.

5.2.1 Mission and Objectives

The primary mission of the AASB is to review the existing auditing practices in India and develop Auditing and Assurance Standards. The AASs represent a codification of the best practices in the area of auditing. The AASB also undertakes preparation of Guidance Notes on

issues relating to auditing, whether generic in nature or industry specific. The AASB recently also undertook the task of issuing Clarifications on issues arising from the Auditing & Assurance Standards. As on date, the AASB has three Statements, thirty-four Auditing and Assurance Standards and forty Guidance Notes, including four industry specific Guidance Notes, to its credit.

5.2.2 *Issues on Companies (Auditor's Report) Order, 2003*

The ICAI, had in 2003, issued the Statement on the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 to help members properly understand and discharge their duties under the Companies (Auditor's Report) Order 2003 (CARO, 2003). However, for understanding the ground realities and resolve the difficulties and intricacies involved in practical implementation and compliance with the requirements of the Order, the AASB took the initiative of reaching out to the members of the Institute to gather their feedback and opinion on the CARO, 2003. Members were required to send their views/opinion on such issues arising from CARO, 2003, which in their opinion needed further elucidation in addition to what was provided in the Statement on CARO, 2003.

The publication, Issues on the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 is a clause by clause compilation of the feedback so received from the members on CARO, 2003 and the considered responses of the AASB on those issues in the form of a ready reference handbook.

5.2.3 *Auditing and Assurance Standards*

The AASB during the year also came out with two Auditing and Assurance Standards, viz,

- Auditing and Assurance Standard (AAS) 33, Engagements To Review Financial Statements
- Auditing and Assurance Standard (AAS) 34, Audit Evidence – Additional Consideration for Specific Items.

5.2.4 *Guidance Notes*

- Guidance Note on Audit of Banks (Revised)

The AASB, in March 2005, issued a thoroughly revised edition of the Guidance Note on Audit of Banks. This edition is an update to the earlier edition issued in 2001 and its supplement issued in 2003. The previous edition of the Guidance Note was revised on account of number of developments impacting the functioning of the Banking industry and consequently the auditors of banks, such as, issuance of new/revised circulars of the RBI with respect to prudential guidelines relating to income recognition, asset classification, provisioning and investment valuation, restrictions on loans and capital adequacy.

The revised Guidance Note also contains specific guidance on issues relating to service tax in banking sector and Basel II recommendations. It also touches upon the aspect of application of various Accounting Standards, issued after the 2003 Supplement, to the banks as well as the implications of the report of N D Gupta Committee on Compliance with Accounting Standards by Banks. The RBI's circulars relating to "Know Your Customer" (KYC) guidelines have also been dealt with in the Guidance Note.

- Revised Guidance Note on Sec 227 (3)(e) and (f) (pursuant to Disqualification of Directors Rules)

The AASB had in 2001 issued the Guidance Note on Section 227 (3) (e) and (f) of the Companies Act, 1956. The objective of the Guidance Note was to assist the members in discharging their professional responsibilities in respect of clauses (e) and (f) of Sub section (3) of Section 227 of the Companies Act, 1956.

The AASB, during the year, came out with a Revised Guidance Note on Section 227 (3) (e) and (f) of the Companies Act, 1956 to assist the members in properly understanding the implications of the Companies (Disqualification of Directors under section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956) Rules, 2003 issued by

then Department of Company Affairs on their duties and responsibilities as auditors. Besides, the revised Guidance Note also gives an insight into other relevant Rules, which though do not find any mention in the abovementioned Rules, have a significant bearing on the efficient discharge of the duties of the auditors in that regard.

5.2.5 Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective

The AASB under its aegis came out with a publication titled *A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective* to educate and impart training to the members of the Institute and to enable them to eradicate money laundering from the economy. This book provides an insight into the various critical aspects of money laundering to help them better understand the concept and channelise their expertise in the right direction.

The Study discusses the important international initiatives in fighting money laundering including the forty recommendations of the Financial Action Task Force of OECD, Customer Due Diligence Guidelines of the Basel Committee of the Bank for International Settlements, etc. While discussing the Indian Initiatives, the Study discusses certain significant provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, as well as important requirements of the Know Your Customer Guidelines of the RBI for the commercial banks as well as the Non Banking Finance Companies. It also deals with duties and responsibilities of external auditors with respect to money laundering.

5.2.6 Handbook of Auditing Pronouncements

The AASB also brought out a revised Handbook of Auditing Pronouncements, which contains the text of the Statements on Auditing, Auditing and Assurance Standards and generic Guidance Notes on auditing, in force as on February 1, 2005. The Handbook also contains a Compact Disc containing the text of all the aforesaid as on that date.

5.2.7 Report of the Dr. J. J. Irani Committee on Company Law

The Government of India constituted an Expert Committee on Company Law on December 2, 2004 under the Chairmanship of Dr. J.J. Irani to make recommendations on various emerging issues arising from the revision of the Companies Act, 1956 and protecting the interests of the stakeholders and investors including small investors. The AASB contributed by way of analysing the Concept Paper on Company Law issued by the Ministry of Company Affairs (MCA) in so far as they related to audit and auditors of companies and also prepared a detailed analysis of comparative position in USA, UK, Australia and Canada. The comments and analysis made by the AASB secretariat formed part of the presentation made by the ICAI before the Irani Committee. Many of the recommendations/comments of the ICAI have found place in the report of the Dr. J. J. Irani Committee on Company Law, issued on May 30, 2005.

5.2.8 Other Activities

- Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)

The AASB had, last year, constituted a Joint Committee with the IRDA to function as a common platform to consider important issues and share views on audit and other relevant issues in respect of the insurance industry. The representatives of the AASB have had meetings with the representatives of the IRDA and a joint study group has been constituted to prepare a draft of the Long Form Audit Report (LFAR) pertaining to insurance companies, on the lines of the one applicable to banks. The study group has developed a draft LFAR for insurance companies.

5.2.9 Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, the AASB has also undertaken a number of ambitious projects such as bringing out/revising existing Auditing & Assurance Standards corresponding to the International

Standards on Auditing issued by the International Federation of Accountants (IFAC), formulating Guidance Notes on various emerging issues in the area of auditing etc. The AASB has also commenced the process for revision of a number of Guidance Notes issued in the past and formulation of Guidance Notes on certain new topics of relevance identified by it for the purpose.

5.3 Research

The Research Committee brings out various publications in the form of guidance notes, research studies, technical guides on accounting and auditing in specific industries, etc., with a view to provide guidance to the members of the Institute in discharge of their professional duties and to enhance the value of the services rendered. It also undertakes approved research projects on current and continuous basis and also prepares representations on various matters of accounting that affect the profession and fall within the scope of research. During the year, the Committee formulated four Guidance Notes viz., Guidance Note on Accounting for State-level Value Added Tax, Guidance Note on Accounting for Employee Share-based Payments, Guidance Note on Accounting for Fringe Benefits Tax and Guidance Note on Accounting by Schools which have been issued under the authority of the Council of the Institute.

The Guidance Note on Accounting for State-level Value Added Tax has been brought out with a view to recommend sound accounting principles for VAT. The issuance of the Guidance Note simultaneously with the introduction of VAT scheme in certain states has enabled the dealers to develop appropriate accounting systems on a timely basis thereby ensuring uniform accounting of VAT throughout the country. The Guidance Note on Accounting for Employee Share-based Payments deals with various aspects of accounting for Employees Stock Option Plans, Employee Stock Purchase Plans and other similar plans involving payments to the employees which are based on the share prices of an enterprise in a

comprehensive manner. The Guidance Note recognises that there are two methods of accounting for employee share-based payments, viz., the fair value method and the intrinsic value method and permits the enterprise to use either of the two methods for accounting for such payments.

The Finance Act, 2005, has introduced Chapter XII-H in Income-tax Act, 1961, on Income-tax on Fringe Benefits. With the introduction of Fringe Benefits Tax, the profession of Chartered Accountants is changed with the responsibility of ensuring proper accounting for the fringe benefits tax for the purpose of preparation of financial statements. To fulfill that need, the Guidance Note on Accounting for Fringe Benefits Tax has been brought out which deals with accounting for fringe benefits tax, particularly with regard to the recognition and presentation of the fringe benefits tax in the financial statements. Another important matter which received topmost priority of the Committee, during the year, is accounting by schools. With the objective of bringing about uniformity and making improvements in the accounting systems being followed by the schools, the Guidance Note on Accounting by Schools has been brought out. The objective of this Guidance Note is to harmonise the diverse accounting practices being followed in schools including Fund Based Accounting and recommending uniform formats of income and expenditure account and balance sheet.

In keeping with the objective of providing industry-specific guidance, a Technical Guide on Accounting and Auditing in Housing Finance Companies has been brought out by the Committee. The Technical Guide discusses main functions of Housing Finance Companies (HFCs), major risks faced by HFCs, statutes applicable to HFCs along with the other relevant regulatory aspects of HFCs. It also discusses various accounting and audit aspects that may be useful in the audit of a housing finance company.

During the year, the Committee also carried out a Study on the useful life of oil and gas pipelines for the purpose of determination of

rates of depreciation. The purpose of the Study is to consider the basis for arriving at true and fair depreciation for pipelines used by oil and gas companies in India including the factors for arriving at the useful life of the pipelines.

With a view to promote better standards in the presentation of information in financial reports, the ICAI, through its Research Committee, has been holding an Annual Competition for the ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting. This Competition, inter alia, aims at making the Annual Report of an enterprise a better communication tool which provides true and fair financial information about the enterprise to its various stakeholders. The Competition for the year 2003-04 was held under three categories. Category I covered non-financial public and private sector enterprises; Category II covered financial institutions in public, private and co-operative sectors, such as, banks, insurance companies, NBFCs, etc., and; Category III covered not-for-profit organisations including companies registered under Section 25 of the Companies Act, 1956, educational and research institutions, and trusts. For the Competition for the year 2003-04, 125 entries were received from Non-financial public and private sector enterprises, financial institutions and Not-for-Profit Organisations (NPOs), etc. The Annual Report and Accounts of M/s Infosys Technologies Limited (for the year 2003-04) was adjudged as the best amongst the entries received for participation in the non-financial public and private sector enterprises category and, accordingly, the Silver Shield for Excellence in Financial Reporting has been awarded to that company. The Silver Shields for Excellence in Financial Reporting under categories for Financial Institutions and Not-for-Profit Organisations have been awarded respectively to the Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) and National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC). The entities whose annual reports and accounts have been adjudged as the second best amongst the participating entities were awarded Copper Plaque for Highly Commended Financial Reports. The entities which received this

Plaque for the year 2003-04 were Siemens Limited and Tata Chemicals Limited under the category for non-financial public and private sector enterprises; Cholamandalam Investment and Finance Company Limited under the category for financial institutions; and Financial Management Service Foundation under the category for Not-for-Profit Organisations. The above awardees were selected by the Panel of Judges, appointed by the ICAI, on review of accounting practices adopted by the participating enterprises for the period ending on any day between 1st April, 2003 and 31st March, 2004 (both days inclusive), without regard to their financial condition and operating performance. His Excellency Lt. General (Retd.) S.K. Sinha, PVSM, Governor of Jammu and Kashmir, presented the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2003-04 at a special function of the ICAI, organised on January 18, 2005 at The Ashok Hotel, New Delhi. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of State for Company Affairs (Independent Charge) was the Guest of Honour on this occasion.

5.4 Corporate Laws

The year 2004-05 was a year of achievement. The Committee completed successfully several projects undertaken by it. The Committee participated in the deliberations of the Expert Committee on Company Law headed by Dr. J. J. Irani and made presentations on the chapters relating to 'Accounts and Audit', 'Minority Interest' and 'Investors Protection'. Most of the suggestions were well received and formed part of the recommendations of the J.J. Irani Committee Report. The Committee also submitted its suggestions on the various matters referred to the ICAI by the MCA and other Government departments, such as, MCA-21 project, Simplified Exit Scheme, 2005 on defunct Companies, Concept Paper on Company Law, Amendments to Schedule VI to the Companies Act, Limited Liability Partnership Bill, Inspection Manual & Prosecution Manual, UNCTAD OECD Principles of Corporate Governance, World Bank's report on observance of Standards and Codes of Corporate Governance of India and for framing

of regulations of Competition Commission of India. During the year, the Committee has initiated to conduct training programme on Arbitration and training programme on Independent Directors to equip the members with expertise, competitive edge and professional excellence. The Committee organized several seminars and conferences covering a wide range of contemporary topics connected with corporate and allied laws. The Committee also organized four Training Programmes for officials of the Indian Company Law service at Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai during the year.

5.5 Fiscal Laws

The Fiscal Laws Committee submitted a second Pre-Budget Memorandum – 2004 in the month of May, 2004. This was done on the eve of the presentation of the Budget by the new Government. The ICAI delegation led by the President met Shri P. Chidambaram, Hon'ble Union Finance Minister on 12th August, 2004 and submitted the Post-Budget Memorandum, 2004. The representatives of the ICAI met Shri D. P. Sengupta, Joint Secretary – (TPL – I), Central Board of Direct Taxes (CBDT) to highlight the salient features of the Post-Budget Memorandum – 2004. The Committee also submitted the Pre-Budget Memorandum – 2005 and it is heartening to note that as many as six of the major recommendations of the ICAI were accepted and incorporated in the Finance Bill, 2005. Subsequently, the Post-Budget Memorandum – 2005 containing a critical analysis of the provisions relating to Fringe Benefit Tax and Banking Cash Transaction Tax was submitted to the Central Government. The CBDT constituted a panel to review the provisions relating to the Fringe Benefit Tax. The ICAI was represented in the panel. The Hon'ble Finance Minister, at the time of passing the Finance Bill, 2005 paid glowing tributes to the valuable contributions made by the ICAI.

The Committee made several important representations to the CBDT, among others, were the representation for modification of the provisions of section 277A of the Income-tax Act, 1961 and the representation on the

National Tax Tribunal Bill, 2004. In the context of National Tax Tribunal Bill, 2004 a presentation was made before the Department related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Subsequently, as required by the Chairman of the Standing Committee, a detailed submission was made in respect of the issues arising out of the above mentioned presentation.

The Committee made special arrangements for viewing the Union Budget – 2004 after which a special issue of the Journal was published containing many articles written by eminent members all over the country explaining the provisions of the Finance Bill, 2004. On behalf of the SAFA Committee, a study of VAT in SAFA countries was finalized. This study gives a good idea about the system of VAT prevalent in SAFA countries. A detailed background paper on the topic of Chartered Accountants and Taxation Services in the Indian context was prepared for consideration of the IFAC Board. Realising the growing importance of taxation of non-residents, the Committee brought out a publication on Taxation of non-residents which comprehensively deals with the statutory and judicial issues concerning taxation of Non-Residents. A background material on accounting and taxation was prepared for the purpose of conducting interactive sessions with the members of the Income-tax Appellate Tribunal.

A system of State-level VAT was introduced by a majority of the States of the Indian Union w.e.f. 1st April, 2005. The Committee took many pro-active measures which placed the ICAI in the forefront in the matter of ably assisting the Government in the implementation of this historic reform. A Guidance Note on Accounting for State-Level VAT, published by the ICAI, was dedicated to the nation by Dr. Asim Dasgupta, Convenor of the Empowered Committee of State Finance Ministers. A model VAT audit report was presented to Shri Ramesh Chandra, Member-Secretary to the Empowered Committee, who highly appreciated the initiatives of the ICAI. The Model VAT Audit Report was also forwarded to all the State Finance Ministers for their appropriate

consideration at the time of enacting audit provisions for VAT. The Committee along with the Continuing Professional Education Committee brought out a landmark publication on State-Level VAT in India – A Study.

The Committee submitted a detailed reply to the MCA containing the views of the ICAI on the representation of the Institute of Cost and Works Accountants of India in the matter of tax audit under the Income-tax Act. The Chairman of the Committee played a significant role in the Monitoring Committee relating to the Electronic Furnishing Return of Income Scheme, 2004. The Chairman of the Committee represented the ICAI in the Sub-Group of the Empowered Committee on PAN for popularizing the decisions of the Sub-Group. The Committee submitted suggestions to the Expert Group constituted by CBDT on Black Money and Assets.

Several seminars and conferences were organised during the period under Report. The All India conference on fiscal and corporate laws was held in Nagpur, a national seminar on tax treaties in Chennai, a conference on fiscal laws in Indore and many others.

5.6 Financial Markets And Investors' Protection

With the series of reforms in the Financial Markets, India is now seen as the potential place for investment and the Government and the Regulators have been taking all-round efforts to position the country on the global platform. The Government is undertaking various budgetary/statutory measures to infuse wider participation by the retail individual investors and encourage liberalized and larger Foreign Direct Investments in the Indian stock markets. Keeping in view the ethos and sentiments of the current developments and futuristic scenario, the Committee drew its blue print plan of action for the year 2004-05 and is successfully implementing the same in a phased manner.

Interactions with the regulatory authorities (namely SEBI and MCA) are in progress to

facilitate the sharing of expertise and knowledge on matters relating to Primary Market, Secondary Market, Mutual Funds, Disclosures Requirements, Corporate Governance and Investor Protection. Training Programmes on Independent Directors, Financial Services and Investor Awareness Programmes are among the priority initiatives during the course of the year. To ensure realistic achievements of the plan of action, the following were the significant initiatives taken and achievements made during the first phase:

- **Market and Investors:** The Committee organised its first series of programme for investors on the eve of announcement of the Budget 2005. A seminar was held on 7th March 2005 at Mumbai on the theme "FIIs for sustaining Capital Market". Eminent capital market experts and investment advisors addressed at the programme and were largely attended by the general public.
- **CAs and IPOs:** Keeping in view the re-surge in the Initial Public Offerings in the market, the Committee organized a one-day programme on IPO at Mumbai on 21st May, 2005. Similar programme was held at Nagpur on 25th June, 2005.
- **Participation in National Conference of Small Investors:** The Committee participated in the said conference organized by Investors Grievances Forum at Mumbai on 22nd & 23rd March 2005.
- **Participation at the deliberations of Expert Committee on Company Law:** On matters related to Investors' Protection and Minority Rights, the Committee presented its suggestions on 28th March and 6th & 7th April, 2005 at New Delhi before the Dr. J.J. Irani Committee on Company Law.
- **Interface with the SEBI & other regulator:** On 7th April, 2005, the President, Vice-President and the Chairman of the committee met Shri G. Anantharaman, Whole-time Member, SEBI and held deliberations on various matters including

rendering the support and expertise of ICAI to SEBI in the area of capital market. The Chairman of the Committee had interaction with Shri Bhagwat Swarup, Member, Income-Tax Settlement Commission, New Delhi on the possibilities of ensuring suitable provisions in legal statutes for investor protection.

- **Training Programme on Independent Directors:** With current listing requirements specifying the mandatory requirement for Independent Directors on the Board of listed companies and to enable the professionals to tap the potential opportunity, the Committee jointly with the Corporate and Allied Laws Committee chalked out three days training programmes for Independent Directors in various metro cities. Embarking upon the action plan of the Committee, the first two training programmes are scheduled in August, 2005 at Mumbai and Ooty respectively.
- **Futuristic Moves - Money Moves:** An All India TV Quiz Programme on Money Moves is contemplated and modalities for implementation of the programme are currently in progress.
- **Publications –** (i) Booklet on Investor Protection: The basic draft of the document is currently under consideration of the Committee and (ii) Revised Guidance Note on Clause 49: The basic draft of the document is currently under consideration of the Committee.

5.7 Expert Opinions

The Expert Advisory Committee of the ICAI has been established to answer queries of the members of the Institute on wide ranging issues relating to accounting and/or auditing principles and allied matters. However, queries which involve only legal interpretation of various enactments and matters involving professional misconduct and where queries concern a matter which is pending before the Disciplinary Committee of the Institute or an appropriate department of the government or

the Income-tax authorities are not answered by the Committee.

In the era of continuous development and growing importance of standard accounting practices, the members of the profession of Chartered Accountants have to discharge their duties with utmost skill and competence. In this process, they sometimes face peculiar situations, where implementation of various accounting and auditing standards becomes difficult. The core concepts propagated by the accounting and auditing standards have to be interpreted and implemented in each particular case with a high level of professional expertise. The Committee provides invaluable support by facilitating the members in the rendering of their services by advising and providing guidance in complex situations. During the period under Report, the Committee has finalised 57 Opinions on wide ranging subjects like valuation of inventories of diamonds, treatment of interest earned on investments against specific funds, contingencies, deferred tax liability, impairment of assets, spares, mandatory refurbishment costs, borrowing costs, etc.

The Opinions issued by the Committee are published in the Compendium of Opinions. Till now, twenty-three volumes of the Compendium, containing Opinions finalised by the Committee upto January 2004 have been released for sale. Volume XXIV of the Compendium, containing Opinions finalised by the Committee between February 2004 and January 2005 is under compilation.

The Opinions of the Committee represent the opinions of the Committee and not necessarily the opinions of the Council of the Institute. Based on the facts and circumstances of the query as supplied by the querist, accounting/auditing principles and practices and the relevant laws applicable on the date, the Committee finalises the particular Opinion. While finalising the Opinion, the Committee also considers not only the national developments in the areas concerned but also the relevant international literature including the emerging thoughts on the subject.

Some of the Opinions finalised by the Committee are published in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant' and are also hosted at the Institute's Website for the information of members at large.

5.8 Continuing Professional Education

5.8.1 Overview

The reporting period is a landmark in the Institute's endeavour to continue to maintain the status of Indian Chartered Accountants as a well-rounded professional comparable only with the best in the World. Every possible initiative has been taken and implemented by the CPE Committee (CPEC) to assist the members to maintain superior standards of professional services.

In line with the international best practices, the Statement on CPE has been revised so that:

- All members in practice (with certain exceptions) are required to obtain to their credit a minimum of 15 hours during the calendar year 2004 and 20 hours during the calendar year 2005.
- All the members who are engaged otherwise than in practice are mandatorily required to earn CPE credits w.e.f the Calendar Year 2006.

5.8.2 Empowering the Programme Operating Units (POUs)

With a dual object of maintaining uniformity in the subjects to be covered by the CPE POU's and to enable them to determine the CPE Credit hours, without approaching the CPE Directorate of the Institute, CPE Calendar has been released after due consultation process covering topics of practical relevance not only for the members in practice but also to the members in service. As in the early years, the CPE Calendar was divided into two parts viz., Obligatory Topics and Optional Topics. The obligatory topics includes the following:

- i. Value Added Tax (VAT)
- ii. Audit and Assurance Standards:
 - AAS 1 Basic principles Governing an Audit
 - AAS 2 Objective and Scope of Audit of Financial Statements
 - AAS 3 Documentation
 - AAS 4 Fraud and Error
 - AAS 6 Risk Assessments
 - AAS 7 Relying Upon the Work of an Internal Auditor
 - AAS 8 Audit Planning
 - AAS 11 Representations by Management
 - AAS 13 Audit Materiality
 - AAS 14 Analytical Procedures
 - AAS 17 Quality Control for Audit work
 - AAS 19 Subsequent Events
 - AAS 20 Knowledge of the Business
 - AAS 21 Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements
 - AAS 24 Audit considerations Relating to Entities using Service organisations
 - AAS 28 The Auditors Report on Financial Statements
- iii. International Taxation –particularly- with reference to DTAA.
- iv. Internal Audit
- v. Service Tax –Law and Practice
- vi. International Finance
- vii. Sarbanes-Oxley – Liability of Auditors

The optional topics include 85 topics of relevance to the members of the Institute in practice and in industry. The Calendar in addition also includes 8 broad heads of topics, which are of relevance to the members in industry specifically.

In order to enable the members to meet the increased quantum of CPE Credit hours, the CPE Programme Organising Units of the Institute particularly the Regional Councils, Branches of Regional Councils, CPE Study Circles and CPE Chapters have been advised to conduct certain minimum number of CPE programmes commensurate with the members being served by such POU's.

5.8.3 Maintaining Quality of CPE Programmes

The Committee has formed Regional CPE Monitoring Committees, inter alia, to monitor the quality of the CPE Programmes being organised by the CPE POU's. Monitors and supervisors as required under the CPE Advisory on Monitors and Supervisors are being nominated for CPE Programme Organizing Units for achieving the above stated objectives.

5.8.4 Services to the Members and POU's

A Knowledge Page is hosted in the Website of the Institute to meet the requirements of the Continuing Professional Education of the members. The page is available at http://www.icaai.org/knowledge/cpe_main.html.

The Committee has taken the initiative of maintaining the database of the CPE credit of the members online by developing an Online CPE Portal which shall start functioning very shortly. The system would allow mapping of the CPE credit hours entered by the members with the CPE hours entered by the respective POU, and the discrepancies if any are reported.

The Committee has been working on the following strategic initiatives:

- Conducting certificate courses on areas of super specialization for the members of the Institute.
- Organising more In House Executive Development Programmes to enable the members in Industry to meet the CPE requirements.
- Issuance of CPE Advisory on Unstructured Learning Activities
- Revision of the norms for the formation and functioning of the CPE Study Circles for the purpose of maintaining the required quality of the programmes so organised.
- Revision of the Statement on the Continuing Professional Education

- Revision of the course curriculum of the Post Qualification Course on Management Accountancy.

5.9 Professional Development

The Professional Development Committee has been making sustained efforts to explore, derive, develop, and make available opportunities for the members of ICAI in different sectors of the economy. The Committee, over the years has been quite vigorous in trying to generate more professional opportunities for the members by exploring/pursuing new/existing areas where the expertise of the members could be utilised in a productive and fruitful manner. The Committee also tried to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. As a part of this process, the Committee is continuously interacting with various regulatory/empanelled authorities and users of services of the profession etc., both in India and abroad.

The major achievements/endeavours of the Committee during the period under Report are given below:

- The usual Bank Empanelment Form has been expanded in scope to make it a Multipurpose Empanelment Form. Members/firms can fill up the form offline after downloading the form from the Website and can upload their Form after connecting to internet again.
- The Professional Development Knowledge Portal has been developed to provide the members with timely and necessary information on practice development and professional opportunities to the members.
- Discussions with the officials of the RBI on various matters relating to audit of banks.
- Various issues of direct interest to the members pursued with the Office of Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

- Meetings held with the officials of the SEBI regarding the empanelment of Chartered Accountants for inspection/audit of Stock Brokers and various other issues of mutual interest.
- Meeting with the officials of NABARD to discuss the possibility of working jointly (the ICAI and NABARD) on various issues relating to Regional Rural Banks.
- Meeting with the officials of the Ministry of Banking to discuss various issues of mutual interest.
- Meeting with the officials of the Khadi and Village Industries Commission to discuss the outsourcing of special audits of the NGOs under KVIO to Chartered Accountants.
- Meeting with the officials of the CBDT regarding ensuring compliance of Section 44AB of the Income Tax Act by Cooperative Societies.
- Meeting with the officials of the Asian Development Bank (ADB), Indo-US FIRE (D) Project and World Bank to discuss issues of mutual interest.
- Representations to various States/Union Territories regarding the introduction of VAT.
- Representations to Principal Finance Secretaries of various States regarding internal audit of Sub-Treasuries and Expending Departments.
- Representations to CMDs of all Public Sector Banks regarding creation of a separate cadre for specialized services in the area of accounting and finance.
- Representations to Minister, Panchayati Raj of various States regarding Financial and Accounting reforms and Capacity- building in Panchayati Raj Institutions.

- Information regarding allotment position for Bank Branch Audits for the year 2004-05 hosted on the Institute's website.

Besides the above, the Committee is continuously striving to achieve its Objectives, detailed below:

- To explore and exploit all available and potential opportunities whereby newer avenues for professional development and growth may be assured for the Institute's members.
- To educate the users on matters affecting the profession.
- To conduct courses, seminars, workshops on various subjects in so far as these relate to the core mission of the Committee.
- To determine the manner and the form in which guidance should be provided to Chartered Accountants in regard to the possible avenues that are developed for them.
- To improve the communication process with representative bodies of users of the services of the profession so that equal opportunity is given to all members of the profession with due regard to their professional abilities and attributes.
- To consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skills and talents of members of the Institute.
- To ensure that existing opportunities of professional development are fully utilised and maintained at equitable and growth-oriented levels.

The Committee is also cautious of its responsibility to educate members in the areas related to new avenues of professional opportunities. It is in view of this that the Committee has organized the following programmes/seminars: -

- Series of workshops on 'Consulting - Finding the Edge' held at Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Jaipur and Hyderabad
- Symposium on 'Strategic Municipal Financial and Accounting Reforms in Municipal Bodies' held at New Delhi.
- Training Programme on 'Sarbanes Oxley Act - An Orientation' held at New Delhi.
- All India Conference on 'Enrichment for Excellence' held at Chennai.
- Non-Residential Conference of Chairman, Directors and CFOs of Mutual Funds and Chartered Accountants held at Mumbai.
- Programme on Understanding the Financial Statements for the officials of SEBI held at Mumbai.

5.10 Peer Review Board

As a proactive measure, the ICAI released the Statement on Peer Review to meet the demands of high quality assurance, consistency and greater transparency. The Statement also lays down the framework for conduct of Peer Review. Reviews are for the purpose of enhancing quality of professional work and have no relationship whatsoever with any disciplinary or any other regulatory mechanism. The review begins with the assumption that a professional works professionally, it ends up with an enhancement of those attributes of professionalism that serve to keep the chartered accountants in the forefront of accounting and auditing profession globally. The objectives of Peer Review include - to ensure that members while performing attestation services comply with technical standards laid down by ICAI; to ensure that such a member has in place proper system (including documentation system) for maintaining the quality of attestation services performed by him; to ensure adherence to various statutory and other regulatory requirements; and to enhance the reliance placed by the users of financial statements for economic decision making.

For achieving the objectives of the Statement on Peer Review, a Peer Review Board was set up in 2002. The Board consists of 10 members appointed by the Council, of whom atleast six are from amongst the members of the Council. The Board has representatives from the MCA, C&AG and Industry (FICCI/ CII) as members. In addition, persons of eminence from legal, banking and education sectors etc., assist the Board in its deliberations as Special Invitees.

As far as possible, in order that the reviewers carry out review assignment(s) as per globally accepted standards, the Board has brought out a comprehensive Peer Review Manual providing an insight into various aspects of peer review process and modalities. Another important publication of the Board in this regard is the Training Modules for Peer Reviewers, which provides a training curriculum for reviewers to undergo after empanelment and, simultaneously, provides guidance to the training facilitators on how to conduct reviewers' training. A booklet on FAQs has also been published. In this booklet, efforts have been made to formulate questions likely to be posed and provide appropriate and satisfactory answers therefor.

The Board imparts training to empanelled reviewers all over the country. Extensive training programmes are being organized to ensure consistency and uniformity in conducting the review. The Resource Persons who were trained at an Interactive Workshop act as Faculty for the various training programmes.

The Peer Review Process visualized by the ICAI aims to cover all its firms in a phased manner over three stages, namely, Stage I, II and III.

For the purpose of selection of practice units to be covered under Stage I and Stage II of the peer review, declarations were called for, data were also collected from Regulators like the RBI, C&AG, CMIE, etc. and data regarding statutory auditors of branches of public sector banks were also collected from the Institute's records and a specially designed software

developed for random selection of practice units.

The Board invites reviewers and the reviewees to share their experience and as per the feedback received from some of them, both the reviewers and the reviewees have expressed that peer review has been a mutually beneficial exercise.

5.11 Committee for Members in Industry

5.11.1 Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities so as to provide for them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations, agencies of the Government, Government Departments and Ministries of the Central and State Governments in such manner as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to the members of the Institute in finding appropriate placement opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing placement services to the following three categories of members and students of the Institute:

- Newly Qualified Chartered Accountants through the process of Placement Programme
- Semi Qualified Accounting Professionals (Candidates who have completed their Chartered Accountancy Course Articleship)

- Qualified Chartered Accountants – who are presently serving in industry or practicing who would like to go in for service

All the above services are being administered through a Placement Portal www.placements-icai.org. The ICAI Placement Portal provides an opportunity to professionals in Finance and Accounting and the Industry to interact with the objective of building capacity for an international best practice oriented finance and accounting culture in Indian Industry.

5.11.2 Placement Programme (Campus Interviews)

The Committee organised Campus Interviews for Chartered Accountants qualified in the CA Final Examinations held in May 2004 and November 2004 during September – October 2004 and February – March 2005 respectively.

5.11.3 Qualified Chartered Accountants and Semi Qualified Accounting Professionals

The placement services to the other two categories are being administered through the Placements Portal. This portal is an online platform for the recruiting entities and the job seekers and provides an opportunity to both to meet their expectations out of the system.

5.11.4 CFOs Guild

The Committee is maintaining a Guild of CFOs. The Guild is for the members of the Institute who are occupying senior positions (GM & above) in Industry.

The Committee is working on the following strategic initiatives:

- Marketing of Placement services to further improve the final placement of member of newly qualified Chartered Accountants.
- Placement Seminars at Major Metros
- Revision of Publication 'How to face interviews and FAQs'

- Popularisation of Placement Portal
- Special drive on foreign jobs and approaching foreign job consultants
- Study Tours to foreign countries
- Publication of books having relevance to members in industry
- Institution and regular award of Best (CA) CMD / CEO / CFO
- Publication of CMII Newsletter
- Creation of database of members of eminence and those occupying key positions in industry
- Considering the ways and means to enhance the participation of the members in employment in the activities of the Institute
- MOU and Agreement with ICICI Bank Ltd. for recruiting newly qualified chartered accountants, which has led to recruitment of a very large number of candidates
- Organisation of Industry specific programmes

5.12 Information Technology

5.12.1 ISA Registration/ ET Pass/ AT Pass Status from 1/4/2004 to 30/6/2005

The realization that the best way to capitalize on the emerging opportunities is to transform the traditional competencies in auditing and accounting into techno-based assurance skills has impelled the ICAI members to seek knowledge update by joining Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit (ISA) in a big way. ISA Professional Training batches, ISA Eligibility Tests (ET) and Assessment Tests (AT) are conducted on a quarterly basis. The following table summarizes the ISA Registration/ ET Pass/ AT Pass position for the period under Report:

Particulars	ISA Registration	ET Pass	AT Pass
As on 31/3/2004	15,687	8,901	5,157
Between 1/4/2004 and 31/03/2005	4,542	4,425	3,514
As on 31/3/2005	20,229	13,326	8,671
Between 1/4/2005 and 30/06/2005	850	875	686
Total as on 30/06/05	21,079	14,201	9,357

5.12.2 IT Harmony Newsletter, the Voice of the Institute on Technology :

The 'IT Harmony' Newsletter issued by Committee on Information Technology has been highly acclaimed for the contents, design, thematic treatment and thought provoking articles on high topics. The following table lists themes of "E" Mode IT Harmony hosted on the ISA Portal at www.isaical.org in respective months:

Month	Theme
Apr-04	Identity Management
May-04	Sarbanes-Oxley & Rebuilding Investor trust
Jun-04	Convergence
Jul-04	Business Continuity Planning
Aug-04	Risks in an Organizational Set Up
Sep-04	Customer Relationship Management
Oct-04	Business Intelligence
Nov-04	Knowledge Management
Dec-04	IT/IS Audit Standards
Jan-05	Internet / Intranet and Extranet
Feb-05	Web Enabled Services
Mar-05	IT Infrastructure Management
Apr-05	Life Cycle Management Solutions
May-05	System and Process Assurance
Jun-05	IT Infrastructure in Banks

Apart from the Thematic and Contemporaneous coverage, other salient features covered in the newsletter are Interview with leaders in government, Business, Technology Institutions.

5.12.3 ISA Course Syllabus & Materials Review :

The Committee is revising the Syllabus & Materials for the ISA post qualification course to organise the ISA Professional Training batches from the 3rd Quarter of 2005 with the revised course structure and materials.

5.12.4 Online Test Practice Tests (OLPT) and Researched Online Study Material (ROSM) - Twin Services on e-learning mode:

The Committee provides the ISA COM online facility on 24/7/365 basis for the benefit of members spread out throughout the country. This facility provides two services - Online Practice Test (OLPT) & Researched Online Study Materials (ROSM). OLPT facility enables members to assess their level of knowledge and get exposure to the type and level of questions being asked in the ISA ET & AT examinations. The ROSM facility not only checks the level of understanding of ISA Candidates, but also provides one page review material on the topic to better understand key concepts. Access to this service is through the ISA Portal at www.isaica.org for specified period.

5.12.5 CAAT Course

The Computer Accounting & Auditing (CAAT) Course organized by the Institute provides hands-on training on use of computers. The following table provides course registration and completion status for the period under review:

Particulars	Registration	Batches	Completed
As on 31.3.2004	1,450	51	--
As on 31.3.2005	2,558	70	1,516
Between 1.4.2005 and 30.6.2005	187	3	31
Status as On 30.6.2005	2,745	73	1,547

5.12.6 ISA Course for Members of The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka

As an important international initiative, ICAI has signed an MOU to offer ISA Course for the benefit of members of The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL). Two batches of ISA Course were organized in the year 2003, Third batch in 2004, Fourth in 2005 and Fifth batch is scheduled from August, 2005. As a part of the MOU, the ICAI is extending course support for important components like professional training by faculties, course materials, Eligibility Test and Final Assessment Test. The course has been very well received leading to repeat batches.

5.12.7 ISA Awareness building program for members of the ICAN

As another important international initiative, the ICAI has organized an awareness building program on Information System Audit for the benefit of members of the ICAN on June 17-18, 2005.

5.12.8 Proof of Concept Laboratory (POCL)/ Centres of Excellence in Information Technology (CEIT) :

The pilot Proof of Concept Laboratory/ Centre of Excellence in Information Technology at Chennai is now operational to provide practical technology exposure to members by providing hands-on workshops on key areas. Workshops on IS Audit of Banks and use of CAAT tools are being organized every month for the benefit of members.

5.12.9 Conferences/ Seminars/ Workshops to provide Practical Training

The Committee has started organizing Conferences and Practical workshops on high topics. Conferences were organized at Kolkata, Mumbai, Pune and Delhi during the year. Also, practical workshops on IS Audit of Banks, use of CAAT Tools, using Excel as an Audit Tool, Network Security Audit have been organized at Faridabad, Delhi and Chennai.

5.13 Public Relations Activities Undertaken

5.13.1 A proactive strategy was continued to be pursued so as to put forward the Institute's viewpoints, building upon the brand equity of the profession, strength of accounting profession in India and Institute's perspective on contemporary issues as also to address the concerns about the profession as indicated herein: -

- Public Relations Committee continued to provide thrust to the PR activities of the Institute.
- Press interaction including with electronic media, at the Head office, Regional offices and various other cities in the country on the initiatives taken/proposed to be taken, policies and programmes and also for responding to the issues concerning the profession were organised. This included one to one meeting of the President with the leading journalists and TV Channels, on issues which confronted the profession.
- Focused interaction with key journalists, press and electronic media, parliamentarians, Government officials, Regulators explaining the view point and initiatives being taken by the Institute on the issues related to the profession nationally and internationally has been pursued.
- Emphasis on contemporary issues in public debate concerning the profession, in the programmes organised by the Institute, its Regional offices and Branches with a view to develop communication link between the Institute and members for their feedback has been laid.
- Promoting CA Curriculum through structured articles as well as interactive meetings with the press in national as well as regional news papers and TV Channels.
- Building a press database for ensuring wide disbursal of Institute's news throughout the country.
- Providing logistic support to the Committees constituted by the Government of India, under the Ministry of Company Affairs.
- Programmes on 'Consulting – Finding the Edge' were organized at Delhi, Kolkata and Ahmedabad to help the members in preparing technical and financial bids for consultancy assignments in a more effective manner.
- Programme on 'How to write effective Press releases' was organized for the officers of the Institute.
- ICAI Patrika being published quarterly to inform and disseminate the important developments at the Institute level.
- Proactive initiative for development of professional opportunities for members, creation of a positive image of the profession, highlighting the career prospects for CA students as also Services rendered by the Chartered Accountants through Advertisements in leading newspapers and magazines including Khaleej Times of Dubai.
- Strengthening the quality of response to the members and students, in the Institute's offices and through the internet, strengthening the grievance handling mechanism, and communication through the journals and student's news letter for improving the quality of services given a focused attention.
- Image building of the Institute both professionally and socially and Creation of general awareness through series of episodes on TV Spots is on anvil.
- Brochures on the Profile of the Institute and on Services rendered by Chartered Accountants will also be brought out shortly.
- The PR Committee has also proposed for holding Annual Convocation for chartered accountants.

- An Archive of the Institute is also on anvil.
- The Website of the Institute given a face-lift and made more informative and user friendly. Video clippings of important events are also being hosted on the website.
- Meetings with Chief Ministers and Finance Ministers of various states.
- Meeting with Secretaries of various Government Departments of Govt. of India and other State Governments.
- Council Members, as allowed by the Council, have been giving statements to the Press subject to certain conditions.
- Terms of Reference of the PR Committee have been amended so as to include promotion of social causes/image of the profession and the Institute.
- PR Policy of the Institute is being finalized by the PR Committee.

5.13.2 Media Events

- Union Ministry of Home Affairs (MHA) and the ICAI organized a joint seminar on Foreign Contribution Regulation Act, 1976 (FCRA) at New Delhi on 24-25th June, 2005 which was inaugurated by Hon'ble Union Home Minister Shri Shivraj Patil and Hon'ble Shri Sri Prakash Jaiswal, Minister of State for Home Affairs was the Guest of Honour at the inaugural session. The valedictory address was delivered by Hon'ble Union Finance Minister Shri P. Chidambaram. Union Home Secretary, Shri V.K. Duggal also addressed the seminar.
- Seminar on "Current Issues of Professional Relevance" jointly organised by Public Relations Committee and Insurance Committee at Chennai on June 25, 2005. The Seminar was inaugurated by Hon'ble Shri K. Rehman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha.
- Coinciding with the occasion the PR Committee also felicitated Hon'ble Shri K. Rehman Khan on his being elevated to the coveted constitutional post of Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri M.K. Garg, CMD of United Insurance Co. Ltd.; Shri M. Ramadoss, CMD of the Oriental Insurance Co. Ltd; Shri B. Sambamurthy, Executive Director of Indian Bank; Shri S.V. Narasimhan, Managing Director, Chennai Petroleum Corpn. Ltd; Shri G. Krishna Murthy, Chairman & CEO, Bharat Overseas Bank Ltd the brand ambassadors of the profession who have made it to the top echelons in insurance, banking and public sector companies were felicitated.
- National Seminar on Emerging Professional Opportunities in the WTO Regime on May 14, 2005 at Hyderabad. The programme was inaugurated by Mr. C. Ramachandraiah Member of Parliament and Mr. Konijeti Rosaiah, Minister of Finance, Government of Andhra Pradesh presided over the Seminar.
- Interactive Workshop on Simplification of Procedural Aspects under the Companies Act 1956 organised by ICAI under the aegis of the Union Ministry of Company Affairs on 16th June 2005 at New Delhi. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of Company Affairs inaugurated the Workshop and Secretary, Ministry of Company Affairs Smt. Komal Anand delivered the Valedictory address.
- Presentation of Model Audit Report for State Level VAT prepared by the ICAI to Shri Ramesh Chandra, Member Secretary to the Empowered Committee of the State Finance Ministers on May 4, 2005 at New Delhi
- Hon'ble Dr. Asim Kr. Dasgupta, Chairman of the Empowered Committee of State Finance Ministers on VAT dedicated Guidance Note on Accounting for State-level Value Added Tax brought out by ICAI, to the Nation on April 15, 2005.

Foundation stone laying of ICAI University at Jaipur by the Rajasthan Chief Minister Ms. Vasundhara Raje on February 3, 2005

- Celebration of the Chartered Accountants' Day on 1st July 2005 which was inaugurated by Shri H.R. Bhardwaj, Hon'ble Minister of Law & Justice. The function was also graced by Shri K. Rehman Khan, Dy. Chairman, Rajya Sabha, Hon'ble Shri Suresh Prabhu, MP and former Minister of Power and Hon'ble Shri C. Ramachandraiah, MP.
- Organisation of the 55th Annual Function of the ICAI held on February 4, 2005 which was inaugurated by Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry.
- Launch of new Post Qualification Course on International Trade Laws & WTO by Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry at the Conference on "New Challenges New Solutions in IT & WTO Era", at New Delhi in November 2004.
- ICAI and FICCI joint National Conclave on Corporate Laws, Disclosure Requirements and the Changing Face of Schedule VI on 8th July 2005 at New Delhi. Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Minister of State for Company Affairs (Independent Charge) was the Chief Guest.
- The Institute organised a function for presentation of the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2003-04. His Excellency Lt. Gen (Retd) S.K. Sinha, PVSM, Governor of Jammu & Kashmir and Hon'ble Shri Prem Chand Gupta, Union Minister of Company Affairs who was the Guest of Honour gave the Awards to the representatives of the organizations declared to be the winners.
- The Institute was able to make a humble collection of Rs 42.50 lakhs for contribution to the Prime Minister's Relief Fund for rehabilitation of the Tsunami victims in India. Cheque for the amount was presented by Shri Kamlesh S. Vikamsey,

President of the Institute to the Hon'ble Minister of Company Affairs Shri Prem Chand Gupta. Smt Komal Anand, Secretary, Ministry of Company Affairs and Shri Jitesh Khosla, Joint Secretary, Ministry of Company Affairs were also present on the occasion.

- National Workshop on Business Process Outsourcing focusing on Opportunities for Chartered Accountants on 24th November 2004 at New Delhi.
- Providing PR support for the programmes organised by the regional councils and the branches.

5.13.3 International

- Visit of Mr. Graham Ward, President, International Federation of Accountants (IFAC) and Mr. Ian Ball, Chief Executive IFAC to India from February 16-18, 2005.
- Meeting of the IFAC Public Sector Committee was hosted by the Institute from 1st to 4th November 2004 at New Delhi. Coinciding the meeting, a seminar on 'Enhancing Accountability and Good Governance In the Public Sector' was also organized which witnessed participation of about 45 foreign delegates from about 15 countries.
- ICAI and ICASL joint international conference on 'Emerging Global Opportunities' held on 24th-25th September 2004 in Kerala.
- On the occasion of 19th SAARC Charter Day on December 8, 2004 the Institute organised a debate on 'Communication Skills: Cutting Edge for CA Profession'. Mr. V. Ashok, Joint Secretary, SAARC, Ministry of External Affairs was the Chief Guest on the occasion.
- A delegation of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) led by Mr Pushpa Lal Shrestha, President ICAN visited India for a two-day round of discussion with the ICAI and mapped out the time bound

action plan for implementation of the MoUs signed between the two Institutes.

- Visit of delegation of State Audit Institution of Oman to New Delhi on June 4, 2005.
- Visit of Mutual Evaluation Team of Asia Pacific Group on Money Laundering to the Institute at New Delhi on March 21, 2005 led by Mr. Rick McDonell, Head APG Secretariat, Australia
- International Conference on 'eChallenges & Focus 2005' being organized by the Dubai Chapter of ICAI on March 17 – 18, 2005 at Dubai.

5.14 Trade Laws and WTO

The Committee on Trade Laws and WTO had been established with the mission to establish and assure the expertise and authority of the ICAI in all matters concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the ICAI through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfil national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

Moving ahead with its mission during the period under Report, the Committee continued to strive for capacity building of members in the rapidly changing world trade scenario in order to technically equip the members of the Institute to face the challenges and derive advantages to broaden the scope of their expertise in the new world trading regime and to contribute towards the economic development of India.

5.14.1 Launch of Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

The year proved to be a landmark one in the annals of the Committee with the launch of much-awaited Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation with the following underlying objectives: -

- To expand the Horizon of services of members of ICAI;
- To enable the members to gain visible evidence of specialisation in complex areas of International trading laws and agreements;
- To enable capacity building of members to offer premium services in emerging areas of international trading regime;
- To leverage opportunities in the evolving areas for developing dedicated practice in the field.

With the objective of creating a base of expertise amongst the membership capable of understanding and applying the multifarious National and International trade laws and agreements in the new world trade order, the Course was launched by Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry, Government of India on November 5, 2004 at New Delhi. Being a specialised Course designed to equip members of Institute to take advantage of the space created in the new world trade milieu, the Course has received encouraging response from the members spread across the entire country. Since the launch of the Course a total of 139 members had been registered for the first batch. Till 30/07/05, a total of 150 members have taken registration in the Course.

The underlying objectives of the Course were sought to be achieved by: -

- Release of the Prospectus for International Trade Laws & WTO course, highlighting its significance in strengthening the professional abilities of members in fast changing world trading environment;
- Release of comprehensive Study material for all the Papers of the Course by involving best of subject experts, from within the

country and outside, to help the members gain an insight into the complex topics;

- Recommending a list of suggested national and international readings that give readers additional information and details of the specific topics/subjects;
- Conducting Personal Contact Programme for enabling the candidates to have insights into the practical aspects and technicalities of the international trading laws and agreements that operate under the aegis of the WTO.

5.14.2 Successful Completion of the 1st Phase of the Personal Contact Programme (PCP) under the Course

The 1st phase of Personal contact programme for the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO was successfully organised at New Delhi and simultaneously at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur through Video-Conferencing from 1st to 14th of July 2005. The programme was unique in the sense that for the first time the 14-days long program of the ICAI was also attended by Candidates sitting at specified centers in Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur all being connected with Delhi through Video-Conferencing technology. The programme was interactive whereby all the members attending the Programme from such locations were able to actively participate and interact in the programme. Eminent faculty and senior Government officials in Ministry of Commerce, Ministry of Textiles, Ministry of Agriculture, Permanent Mission of India for WTO at Geneva, Export Inspection Council of India, faculty from Jawaharlal Nehru University, Delhi University, Indian Institute of Foreign Trade, people from trade and industry, professionals and other research based organizations in the field of WTO gave presentations and delivered lectures during the PCPs and was very well received by the participants.

5.14.3 'The WTO Pathfinder – A Technical Update on WTO Matters'

During the period under Report, three issues of the 'The WTO Pathfinder– A Technical Update on WTO Matters' were brought out one each in August 2004, December 2004 and April 2005. The publication being an awakening campaign material continued to carry useful technical updates on WTO for the benefit of members and other stakeholders. Some of the important topics dealt with in these issues are as follows:

- July Framework Agreement of WTO - How Far Have We Moved Ahead
- Trade Policy Review: An Overview of the Mechanism and the Recent Review(s)
- Textiles & Clothing: Future from 2005
- India's Foreign Trade Policy (2004-09)
- General Agreement on Trade in Services: Basic Elements, Negotiations in Accountancy Services
- Moving ahead: from Process to Product Patent Regime
- China's WTO compliance
- Competition Law & Policy – An Understanding
- WTO News

5.14.4 Seminars/Conferences/ Awareness Programmes

- During the period under Report, the Committee on Trade Laws & WTO organised a National Seminar on "Emerging Professional Opportunities in the WTO Regime" on 14th May, 2005 at Hyderabad, hosted by Hyderabad Branch of SIRC. The Seminar was inaugurated by Hon'ble Shri C. Ramachandraiah, Member of Parliament, and a Member of the Profession and was Presided over by Shri Rosaiah Konejeti, Hon'ble Minister for Finance, Government of Andhra Pradesh. The Programme was also attended by Dr. Mohan Kanda, IAS, Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh. A Key Note Address on the theme

'Emerging Professional Opportunities in the WTO Regime with special reference to Competition Law and Policy' was delivered by Shri Vinod K. Dhall, IAS, Member, Administration, Competition Commission of India. During Technical Sessions Dr. S. Chakravarthy, (IAS Retd.), Former Member MRTP Commission and Former Special Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, Shri R. Gopalan, IAS, Joint Secretary, Ministry of Commerce, Government of India and Shri R.K. Gupta, IRS, Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India chaired the Technical Sessions on Competition Law & Policy – Opportunities for Accounting Professionals, Export of Services – An Acknowledged Opportunity and Cross Border Transactions – Issues and Emerging Opportunities for Accounting Professionals respectively. The program also included a Special Address on Emerging Role of Accounting Professionals in VAT Regime by Shri V. Bhaskar, IAS, Commissioner of Commercial Taxes, Hyderabad. The Seminar, which was well attended by members, received wide media coverage.

- A National Conference on 'New Challenges New Solutions in IT & WTO Era' from November 4-6, 2004 was organised by the Committee on Trade Laws and WTO at New Delhi jointly with the Committee on Information Technology and NIRC of ICAI. During the Special Session of the Conference Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry launched the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO. Shri R. Gopalan, Joint Secretary, Ministry of Commerce chaired the Technical Session on Realities of Liberalisation of Trade in Services, and the Technical Session on Emerging Professional Opportunities in the WTO Regime was chaired by Shri T. K. Viswanathan, Secretary, Legislative Department, Ministry of Law & Justice, Government of India. The Conference was well attended by a large number of officials from the Ministry of Commerce, Ministry of Law & Justice, Ministry of Small Scale

Industries etc., members, media and others. The Conference had issues and themes right from identifying potential, introspecting ourselves and the need to realigning our professional competence to meet the demands of the industry.

- Awareness Programmes on 'Imperatives of WTO Regime and Accountancy Sector - Challenges and Opportunities' were organised at Hyderabad with Hyderabad Branch of SIRC of ICAI on September 25, 2004, at Jalandhar with Jalandhar Branch of NIRC of ICAI on October 4, 2004, and at Kolkata with EIRC of ICAI on June 17, 2005. A comprehensive Background Material on 'Basics of WTO and Impact & Opportunities for Chartered Accountants in the WTO Regime' was also brought out for the purpose.

5.14.5 Knowledge Sharing

The Knowledge sharing page developed by the Committee and displayed at the website of the ICAI under the link "KM" (knowledge management) continued to provide useful and relevant information on the basic understanding of WTO. The page intends to keep the members abreast of latest development in the ever-changing global trading environment.

5.14.6 Memorandum of Understanding between ICAI and IIFT

A Memorandum of Understanding between the ICAI and the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) is proposed to be entered into for technical collaboration in the field of WTO, particularly in relation to Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO. The proposed MOU aims at: -

- Sharing of faculty as resource persons;
- Support by the Indian Institute of Foreign Trade towards the organization of Personal Contact Programmes for Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation;

- Sharing of library and other infrastructure of IIFT to ICAI members registered for the Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation;
- Exchange of technical and other documents related to the development of knowledge base in the area of International Trade Laws and WTO;
- Bringing out Joint research and studies in areas of WTO resulting in joint publications;
- Organisation of Joint seminars, workshops on topics of contemporary interest on mutual cost sharing basis; and
- Exchange of technical know how and expertise to facilitate transfer of knowledge and expertise.

5.14.7 *Assessment of Initial Offers under GATS*

The Committee has been making an assessment of the Initial Offers under current GATS negotiations, in so far as sector specific/horizontal limitations have been inscribed, by various WTO Member Countries in the areas of services which a Chartered Accountant can render such as accounting, auditing, book keeping, taxation, computer related services to include the software, data processing and data base services, management consultancy, legal and financial services for bringing out a Research Study to suggest possible strategies for deriving comparative advantages there from.

5.15 **Committee on Insurance**

- The Committee launched the Post Qualification Course in Insurance and Risk Management (DIRM) for the benefit of members of ICAI in April 2003. The subjects cover the elaboration, inter alia, of the principles and practice of life and general insurance, insurance accounting and management, regulatory framework, asset and liability management, solvency margin, technical aspects related to various general and life insurance products, risk management measures, reinsurance,

application of information technology tools in the management of insurance business and controls and the strategies on product formulation and ancillary areas. The Course has been framed with the vision to equip the members with the insurance industry-specific knowledge.

- The Committee organized a National Conclave on Insurance on 6th November, 2004, at Hyderabad. The Chairman, IRDA was the Chief Guest.
- An All India Conference on Current Issues of Professional Relevance was organized jointly by the Committee on Insurance and PR Committee on 25th June, 2005. The Conference was inaugurated by Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri K. Rahman Khan. Topics on Insurance, Banking, Taxation, Service Tax, Fringe Benefit Tax, Banking Cash Transaction Tax, Drafting of Documents for Real Estate and IT & BPO were discussed at the Conference. Eminent Speakers addressed the various Sessions. The Conference was attended by 800 participants.
- The Committee maintained close liaison with the IRDA on issues concerning the industry and the ICAI.
- The Course, being an industry-specific specialization, has received tremendous response in terms of registration. Till 30th June, 2005, 2566 Members have been enrolled for the Course. The region-wise break-up of the candidates is as follows:

Region	As on 31 st March, 2005	As on 30 th June, 2005
Western	443	463
Southern	974	983
Central	454	469
Eastern	279	286
Northern	360	365
Total	2510	2566

- The Second Technical Examination was held between 5th & 9th Nov. 2004 and 266 candidates appeared for the same. 73

candidates were declared successful at the second Technical Examination. The third Technical Examination was held between 6th & 10th May, 2005.

- Orientation Course for candidates declared successful at the Technical Examination held in May & November, 2004 organized at various places. The total number of participants was 45 & 95 respectively.
- Knowledge Portal launched on Institute's website www.icaai.org continues to be maintained. It contains News Section, Contemporary Quotient, Course Information/Announcements and Press Room. It is beneficial for members in practice & service associated with insurance sector and also for members pursuing IRM Course.
- Technical Guide on Inspection of Investment Function of Insurance Companies issued.
- Course Material has been revised.

6. INTERNATIONAL INITIATIVES

During the year, the Committee carried on the process of evaluation of the Institute's qualification by overseas accounting bodies for the purpose of allowance of exemptions to the Institute's members from examination and training forming part of the overseas bodies' qualification. Being a long drawn process involving the evaluation of qualification, training, continuing professional education and disciplinary requirements as also having regard to the current state of negotiations under GATS involving domestic sensitivities, the results of the process are slow; yet at the same time the Institute is continuing its efforts for early culmination of the process.

The prominent role played by the Institute is evidenced in form of nomination it enjoys in the governing boards of international accounting bodies namely the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian

Federation of Accountants (SAFA) in addition to their various functional committees. The Institute's representative currently holds the office of Vice-President of SAFA. In addition to the governing boards, the Institute is represented on :

Committees of IFAC :

- Education Committee,
- Small and Medium Practitioners Permanent Task Force,
- Developing Nations Permanent Task Force,
- International Public Sector Accounting Standards Board
- Professional Accountants in Business Committee

Strategic Committee of CAPA

SAFA

- Centres of Excellence on Education, Training & CPD
- Centres of Excellence on Standards and Quality Control
- Centres of Excellence on Ethics and Independence of Auditors
- Centres of Excellence on Best Presented Accounts Award & Best Corporate Governance Award
- Working Group to Recommend upon Way Forward for Restructuring of SAFA
- Working Group on Accrual Accounting in South Asian Region
- Working Group on Best Corporate Governance Practices in South Asian Region
- Working Group on Networking of Firms
- Task Force on Study of Cost Indices of major Products in SAARC Countries
- As Advisor (uptil December 2004)
- As Permanent Secretary

The Institute hosted the 20th Anniversary Conference on "Integrated Financial Markets in the SAARC Region" of the South Asian

Federation of Accountants (SAFA) on August 27-28, 2004. Regulators such as the Securities and Exchange Board of India, Securities and Exchange Commission of Pakistan, Securities and Exchange Commission of Sri Lanka and the Securities Board of Nepal presented respective viewpoint on the theme.

The Institute also hosted the meetings of SAFA Assembly, Advisory Body comprising of Past Presidents, Task Force on Study of Cost Index of Major Products in SAARC Region and heads of member bodies on research initiatives of the member bodies on August 26 - 27, 2004 at New Delhi.

A joint conference on "Enhancing Accountability and Good Governance in the Public Sector" was organised with the Public Sector Committee of the International Federation of Accountants (IFAC) on November 1, 2004 at New Delhi.

- The Institute also hosted the meeting of the Public Sector Committee of IFAC on November 2 - 4, 2004 at New Delhi.
- The Institute organised a study tour to China to undertake a study of its capital market regulations, banking and insurance industry, stock market mechanism, university education system etc. and interaction with the respective Chinese authorities. The tour was organised from November 23, 2004 to December 3, 2004.
- A seminar on the theme of 'Redefining the Accounting Profession' was organised under the auspices of the State Audit Institution, Sultanate of Oman on November 25 - 26, 2004 at Muscat, Oman.

Twenty six students from the chartered accountancy member bodies from Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka participated in the 17th All India ICA India Students Conference organised on December 25 - 26, 2004 at Nagpur, India.

- An exchange programme for the Indian chartered accountancy students enabling their orientation towards the professional environment in other South Asian countries was organised with the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) during January 2005.
- A Conference on the Role of the Profession in Developing Economies was organised by the Institute at Abu Dhabi on January 9 - 10, 2005.
- A joint conference was also organised with ICA of Pakistan on the theme Accounting Profession: New Horizons at Lahore, Pakistan on January 14 - 15, 2005.
- The Indonesia Chapter of the Institute with its objective to organize professional development and learning activities held a seminar on January 30, 2005.
- A joint conference with the Institute of Chartered Accountants of Nepal was organised on the theme 'Professional Accountants: Looking Beyond Frontier' at Kathmandu, Nepal on January 30 - 31, 2005.

At the invitation of the Institute, Mr. Graham Ward, President, International Federation of Accountants (IFAC) and Mr. Ian Ball, Chief Executive IFAC were in India from February 16-18, 2005. Their visit coincided with the multifaceted discussions with Government, Regulators, CFOs, members of the profession and media to have the mutual sharing of Indian perspective and make the Indian Government and Regulators empathize with the emerging developments globally and steps taken by IFAC. During their three-day visit, they met Hon'ble Commerce and Industry Minister, the Hon'ble Minister of State for Company Affairs (Independent Charge), the Reserve Bank of India Governor, the Comptroller and Auditor General of India and officials of Securities & Exchange Board of India. President, IFAC asserted that IFAC was in full favour of

unhindered movement of accounting professional and was also working with leading World bodies like the World Bank and other regulators to establish best practices in the accountancy profession. IFAC President advocated for a greater role of the accountancy profession in India in the international arena. Coinciding with the visit, a conference 'Changing Paradigm in Accounting Profession' was organised at Mumbai on February 18, 2005.

A high-level team of evaluators of the Asia / Pacific Group (APG) on Money Laundering, a regional body responsible for implementation and assessment of the international standards to contain money laundering and financing of terrorism in member jurisdictions, visited the ICAI on March 21, 2005.

- An International Conference on 'E-Challenges & Focus 2005' was organised on March 17 – 18, 2005 by the Institute's Chapter at Dubai.
- Dubai chapter of the Institute organised a technical Seminar on May 29, 2005, on the recent developments in the financial reporting standards and their implications and in the field of Financial Management.
- The Institute entered into a Memorandum of Understanding with the Institute of Chartered Accountants of Nepal on July 18, 2004 at Kathmandu, Nepal focusing *inter alia* on the provision of technical support for the establishment and implementation of accounting and auditing & assurance standards, guidance notes, code of ethics etc, for members of the Nepalese Institute formulation of Continuing Professional Education mechanism, designing and development of study material and training system for ICAN students, suggesting measures for promotion and support of research activities and joint conferences between the two bodies.
- A delegation of the Institute of Chartered Accountants of Nepal comprising its President and Executive Director visited the Institute on December 6 - 7, 2004 to discuss the modalities and finalisation of action plan in respect of assistance to ICA of Nepal by the Institute.
- President, Vice President and a Council Member of ICA of Nepal visited the Institute from May 2 – 5, 2005 and held wide ranging discussions on rendering of assistance by the Institute to ICA of Nepal in areas of Peer Review, conduct of ISA Course, revision of syllabi and Continuing Professional Education.
- The Institute has committed its support to ICA Nepal *inter alia* in the introduction of Peer Review framework and Post Qualification Course in Information System Audit for the ICA Nepal membership and has conducted an awareness program on Peer Review System and Information Systems Audit on June 17-18, 2005 at Kathmandu.
- In furtherance of the process of bilateral cooperation, members of the Institute holding certificate of practice have been permitted to acquire the membership of the ICA of Nepal upon passing their examination in (i) Commercial Laws; (ii) Direct Tax; and (iii) Indirect Tax and practice in Nepal in form of firms only, in which the share of the foreign citizen(s) shall not exceed 51 percent.
- A Memorandum of Understanding was also signed with the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka on July 18, 2004 to support the conduct of the Course on Information and Systems Audit (ISA) for the members of the Sri Lankan Institute providing *inter alia* for the deputation of Institute's officials / faculty members for the conduct of professional training, provision of background material, provision of facility of Research Online Study Material

(ROSM) and online practical tests for candidates, arrangement for the conduct of Assessment Tests for the conduct and administration of the course.

- During a study tour to China organised by the Institute in November 2004, discussions were held with the officials of Chinese Institute of Certified Public Accountants. In order to reinforce the ties of cooperation between the two Institutes, it was agreed to set up a technical desk at each of the Institutes for dedicated handling of queries of members of the two bodies, exchange and render support in development of technical documentation and offer expertise to each other in the areas of examination, peer review, financial report review, continuous professional education, post qualification courses etc. A Memorandum of Discussions between the two Institutes outlining the above decisions is under finalization.
- Negotiations are being held with the Institute of Certified Public Accountants of Singapore (ICPAS) for entering into MRA in Accountancy Sector under the aegis of India - Singapore Comprehensive Economic Co-operation Agreement (CECA).
- The Committee also explored the prospects of supporting the accountancy profession in countries where the profession does not have a constitutional set up.

An approach paper in respect of the Institute's proposal titled 'Technical Cooperation to UAE for Institutionalization of Accountancy Profession and Capacity Building' has been submitted to the office of the Consular General of India in the UAE.

- A delegation from the State Audit Institution, Oman (SAI) led by H. E. Mr. Nasser H. Al-Rawahy, Deputy President, SAI visited the Institute on June 4, 2005

to discuss the role of ICAI in institutionalization of accounting profession in Oman including setting up of its own accounting body. The proposed Memorandum of Understanding (MoU) between SAI and the Institute is geared towards SAI's collaboration with ICAI and setting up of a branch office of the Institute at Muscat, Oman.

- The Institute was represented on the Roundtable on Implementation of International Accounting and Auditing Standards held on October 15, 2004 in Basel, International Auditing and Assurance Standards Board and National Standard Setters meeting held on February 10 - 11, 2005 in London, meeting of Standard Setters in SAFA Region on February 23, 2005 held in Colombo and meeting of the Intergovernmental working group of experts of International Standards of Accounting and Reporting (ISAR) on SMEs.

In the month of May 2005, the Institute launched *ICAI International*, an electronic quarterly communiqué purported for members of the Institute based overseas.

- The Committee has compiled a set of Frequently Asked Questions from the perspective of the Institute's members based in foreign countries. The same have been hosted on the Institute's web-site.
- The Institute opened two new chapters during the year in Nigeria and Port Moresby (Papua New Guinea) expanding the total number of Institute's chapters worldwide to 15.
- The Institute continued to address the issue of promoting mutual recognition arrangements for the Indian profession with other international accountancy bodies and at the same time addressed the domestic concerns as well. The

Institute's communications have highlighted that the Govt.'s offer in accountancy sector be guided by national interest and take into account the concerns of the profession by not diluting the initial offer made for accountancy services. The Institute has pressed on the need for seeking effective commitments/offers and removal of professional and non professional barriers from the major trading partners so that the Indian accounting professionals get an effective access to these countries.

- The Institute continued to participate at the various meetings called by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India for presenting its perspective on the ongoing negotiations in the Accountancy Sector.
- The Delegation of the European Commission to India, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka under the EU-India Small Projects Facility Program for the year 2004 had awarded a project to the Institute titled **FINANCIAL AND ACCOUNTING REFORMS: CAPACITY BUILDING AND RELATED STRATEGIES**.
- Based on the recommendation of the Committee, the Council of the Institute has decided to allow CPE credit to Institute's members for attending the seminars, conferences, etc. organised by the South Asian Federation of Accountants (SAFA) or under the aegis of SAFA by its chartered accountancy member bodies.
- The Institute is also hosting an International Conference on the theme "Accounting Profession: Adding Value to New Horizons of Economic Growth" on September 1 – 2, 2005 at New Delhi.
- The Institute shall host the meetings of SAFA Assembly and its Centres of Excellence and Working Groups from September 1 – 3, 2005 at New Delhi.

- The Institute would be hosting the meetings of the Developing Nations Permanent Task Force of IFAC during the latter half of 2005.
- The Institute has also received in-principle approval of the International Innovation Network (IIN) to host the IIN Conference for 2006 and the meeting of its Coordination Committee in January 2006. IIN is an organisation of accountancy institutes from approximately 20 countries in Europe, Africa, Asia and the Americas representing over one million accountants worldwide.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

7.1.1 HRD Training Programme

The ICAI organised training programmes on following areas/subjects to sharpen knowledge & skill and to bring attitudinal changes for providing enhanced and better services to its members & students and also to all concerned :

- Regular Training Programmes/Workshops for Officers and staff of the Institute covering areas like Individual Empowerment, Attitude and Executive Effectiveness, Stress Management, Time Management & Communications.
- Subsequent round of the series on Yoga Therapy
- Specially designed series of Managerial Effectiveness/Executive Development Programmes for middle, senior and top level Executives
- Periodic/continued sessions on sharing of knowledge, experience and identification of areas of concern/priority aiming Secretaries to Non-Standing Committees
- Awareness and Interactive Sessions for New Entrants

- Weekly Workshop Accounting Standards and allied topics
- Periodic Interactive Orientation Courses for Officers
- Periodic Interactive Sessions for Staff at various levels
- Seminar on MIS and its Effectiveness
- Workshop on VAT
- Workshop on Library Services
- Subsequent series of Computer Training

Further HR Initiatives aiming at grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management, etc. are as follows :

- Open the month with the grievance seeking and initiation of hardship mitigating process/steps
- Departmental Monday Meetings
- Periodic employee counselling on areas requiring additional/focussed employee attention
- Continued support to lower rung of employees to bring them to mainstream by upgrading performance and delivery levels to the required benchmark

Thus, regular HR training programmes were held spanning more than 2,750 man hours at the headquarter and regional office levels.

7.1.2 Human Resources - Welfare Measures

The ICAI has always recognised that its Human Resources are the most important asset for all its success in past and also strongly believe that this asset may overcome all hurdles for all times to come and place the ICAI as a **Guiding Star**. It continued to provide enhanced Welfare measures for its employees, during the year as well.

7.2 Use of Information Technology in Member's and Student's Services

7.2.1 Virtual Institute

The Council is happy to announce taking the 'Virtual Institute' to the global world. The first task of centralization and integration of members and students on all India basis has been completed. There are some operational problems but the goal is in sight and these problems are expected to be resolved shortly.

The Virtual Institute has a sophisticated Infrastructure and Data Center as the primary delivery center (PDC) of the application. After an exhaustive study Chennai was identified as the location of the PDC and New Delhi as the Disaster Recovery (DR) site. Chennai and New Delhi together with the other regional offices combine to form a Wide Area Network. All regional offices are linked up with Chennai through high bandwidth leased lines. The branches connect to the PDC through a dialup VPN since their usage is intermittent and limited to one or two persons. A 2 mbps pipe between Delhi and Chennai not only supports the daily traffic between the two locations but also takes care of the online synchronization of the DR database at New Delhi.

The data center is a high-end establishment with Oracle 9i database server with Real Application Cluster (RAC) running on Sun Cluster, Citrix application server farm and a web server farm. The DR site hosts a scaled down setup. In the event of a disaster at the PDC, the data is secured and critical operations resuscitated by connecting to the DR site.

The Virtual Institute application, the result of two years of concerted effort, sits atop the entire infrastructure. The application is accessed within the WAN environment through the Citrix thin computing client. Internet users (members and students) access the application through the web server on their browsers.

The progress achieved so far in this project has tied together the operations of all the five regional offices into a unified centralized system. With this all operational functions of the ICAI have been brought onto a common intranet with seamless flow and availability of information. An online Internet channel to the Students and Members by the name 'ICAI e-

seva services to members & students' has been provided on the ICAI website to enable students & members to interact with the Institute. The facility enables members and students to pay fees online using payment gateway.

7.2.2 Communication Backbone:

The Institute has switched over its communication backbone to Reliance network. The Institute has been using Reliance mobile services, data lines by way of Virtual Private Network and Internet services since beginning of this year.

7.2.3 ICAI's Enterprise e-mail server:

The Institute's enterprise e-mail server has been upgraded with robust anti spam/ anti virus controls having features such as personal & global address books, corporate directory, web based calendaring and scheduling, mail policy, and web based administration for unlimited number of users.

7.2.4 Online Multi Purpose Empanelment Form

The IT department of the Institute enabled Professional Development Committee to announce an Online Multi Purpose Empanelment Form. The usual Bank Empanelment Form was expanded in scope and made into a multipurpose empanelment form facilitating the ICAI to respond to various entities' requests for panels from the database created through the responses to the Multipurpose Empanelment Form.

7.2.5 Online access to List of Members

A facility has been provided on the ICAI website for online access to List of Members as on April 1, 2005. The facility enables a search based on either membership number or name. General Public will be in a position to find out whether somebody declaring himself as a Chartered Accountant is a member of the ICAI using this facility.

7.2.6 Online publications sale:

During the year, it was decided to introduce a concept of online selling of Institute publications. Accordingly, a system was developed which enables users to select the publications and pay the price of the publications as well as courier charges online using credit cards. The publications subsequently gets couriered to the user as per the address indicated at the time of making online request on the ICAI site for purchase of publications.

In addition to the above, a facility was introduced to enable members and students to pay their fees online using credit cards and Electronic Clearing System (ECS).

7.2.7 E-regulation

The ICAI is a sub-certifying authority for issuance of digital certificates. ICAI is the 1st Institution to acquire a digital certificate issuing capability as a sub-certifying authority.

As a part of e-regulation, The Institute introduced a facility for Digital Signing of online forms/ data submitted and establish a secured channel for communication between the client machine (i.e. members/ employees) and web server using secured HTTP connection using the digital signatures issued, ICAI sub-certifying authority. To start with, this facility was introduced using digital signatures on e-mails. A system is being introduced wherein students and members will be in position use digital signatures for online signing of all regulatory forms with the ICAI. Additionally for added security and access control the ICAI integrates Digital Certificate based access control mechanism to enable members & students to file online forms. Currently the digital certificates issued by the ICAI enables members to act as e-intermediary with Income Tax department.

7.2.8 ICAI Portal

During the year, a decision was taken to revamp the ICAI website and make it an

Interactive portal. Currently the development in this direction is taking place and soon the ICAI website will be made into an interactive portal. The ICAI website was moved from the Internet Service Provider's premises to the ICAI's own premises. A facility for online viewing of library book titles based on author/ keyword search was also introduced.

7.2.9 Intranet

The ICAI intranet facility has been put to effective use. All internal communication of the office happens on intranet. Online complaint register for users for issues relating to Information Technology department as well as Administration department has been introduced on the intranet facilitating the users to track their complaints/ requests. A system for online viewing/ printing of salary slip, income tax statement and personal details has also been implemented on the intranet.

7.3 Audit Committee

The Council of the ICAI constituted the Audit Committee with a view to overseeing its reporting process and disclosure practices in respect of financial information. The focus of the Committee while reviewing the annual financial statements and reports before submission to the Council was primarily on:

- adherence to the Accounting policies and reconciliation etc.
- compliance with Accounting Standards and applicable legal requirements.
- weighing the adequacy of internal control system.
- efficacy of the data security and integrity etc.
- evaluation of financial and risk management policies.

During the year, the Committee while functioning within the ambit of its Terms of Reference, had detailed discussions with both the internal and statutory auditors of ICAI at regular intervals. The Committee reviewed the overall position of ICAI accounts and shared the views and suggestions of the auditors apart

from evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control systems including data security, integrity etc. It recommended various measures to ensure uniformity in accounting principles among regional offices and adherence to laid down policies of ICAI.

The Committee felt necessary to hold Central as well as Regional Audit Committee meetings at regular intervals i.e. atleast once in every two months with a view to review the position of accounts and audit observations. Accordingly, the Regional Audit Committees also met at periodic intervals to take stock of the situation at respective regional offices and suggested measures for greater and more effective internal controls to enhance operational efficiency. After reviewing the observations of the Regional Audit Committees, the Central Audit Committee recommended its views to the Executive Committee to arrive at a policy decision and for further improvement in overall efficiency which was ultimately accepted by the latter.

The Committee also reviewed the scope of work for internal auditors and made it more comprehensive to cover almost all the major areas of control aspects including, financial and risk management. The Committee also initiated a move towards creation of a database of all internal and statutory auditors of ICAI for effective communication with and free flow of information from them as well as monitoring timely compliance of audit observations and consequently, early finalization of yearly accounts.

7.4 Financial Reporting Review Board

The Financial Reporting Review Board was established in July 2002 with a view to further strengthen the financial reporting framework prevalent in the country and to bring an overall improvement in the quality of attestation services being rendered by the members of the profession. The Board reviews the general-purpose financial statements of the enterprises with a view to determine compliance, *inter alia*, with the accounting standards issued by the ICAI.

The year under report was the first year of effective functioning for the Board. During the year, the Board took-up review of general-purpose financial statements of twenty companies for the financial year 2002-03, selected on a random basis. As per the Operating Procedures of the Board, the preliminary review of these statements was conducted by the Technical Reviewers selected from the panel maintained by the Board. The review reports submitted by the Technical Reviewers were considered by the Financial Reporting Review Group constituted for this purpose. The Board then considered the reports submitted by the Group. The review of these 20 companies has since been completed. Out of twenty cases, the Board has referred six cases to the Secretary of the ICAI for examining the same, in terms of the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949. The Board has also referred five cases to the regulatory bodies relevant to the enterprises for appropriate action against the enterprises. (Out of these five cases, four cases are the same that have been referred to the Secretary of the Institute).

After completing the reviews of the above-mentioned twenty companies, the Board has selected 125 companies for review of general-purpose financial statements for the year 2003-2004, on a random basis. For conducting these reviews, the Board has empanelled 80 Technical Reviewers on the panel of reviewers maintained by it and constituted six Financial Reporting Review Groups in different parts of the country. The review of these financial statements has already commenced.

7.5 Committee for Review of Education and Training (CRET)

7.5.1 The goal of accounting education and practical experience is to produce competent professional accountants capable of making a positive contribution over their lifetimes to the profession and society in which they work. The profession needs to ensure that individuals who become professional accountants achieve an agreed level of competence, which is then

maintained. The means by which individuals develop and maintain competence is through education and practical experience, followed by continuing professional development.

7.5.2 ICAI has been making continuous efforts to strengthen Education and Training of the students as it considers them the backbone of the profession. As a matter of policy, the ICAI has been conducting periodic review of the Education and Training. The present scheme of Education and Training in force from October 2001 is based largely on the recommendations of the Review Committee (1998). With view to meeting challenges posed by information revolution, economic reforms and globalisation combined with international developments, the Council of the Institute constituted the High Powered Committee on Review of Education and Training in May, 2003 with the following terms of reference:

- To review the existing system of education and training for membership of the Institute in order to determine and ensure its relevance and adequacy in the context of the changing environment and demands on the profession.
- To consider and adopt appropriate measures to ensure that the system meets the benchmarks and other prescriptions embodied in the International Education Standards, with reference to Pre-qualification as well as Post-qualification developed by International bodies such as the Education Committee of the International Federation of Accountants.
- To review the existing curriculum in order to consider and adopt appropriate changes in the contents of Professional Education Programs for students.
- To consider and adopt measures to gain increasing international recognition, acceptance and application of our education and training process and Mutual Recognition Agreements.
- To consider issues concerning Continuing Professional Education and Development for

Members (including Post-membership examination).

- To consider such other matters arising from the foregoing as the Committee may determine.

7.5.3 The Committee adopted a comprehensive approach to appraise the present system of education and training in terms of its strengths and weaknesses and determination of competency profile in terms of users' needs before formulating any scheme of education and training including design and analysis of questionnaires, commissioning of separate study groups, inviting view from the general public, etc.

7.5.4 The Council of the Institute at its 252nd meeting held in July, 2005 approved Report of the Committee for Review of Education and Training. As per recommendations, the proposed overall scheme of pre-qualification education and training leading to the membership of the ICAI be as under:

- Enroll with the Board of Studies for the Common Proficiency Test (CPT) after passing Class X examination (or its equivalent) or thereafter;
- Taking the Common Proficiency Test after appearing in 10+2 examination (or its equivalent) or thereafter provided there is a gap of at least three calendar months between the enrolment for CPT and appearance at CPT; and passing both;
- Register for practical training and enroll with Board of Studies after passing CPT and 10+2 (or its equivalent) for undergoing theoretical instruction for Professional Competence Course (PCC) and practical training simultaneously;
- Undergoing integrated theoretical instruction and practical training for a period of three and a half years while pursuing Professional Competence Course and Final Course;

- Undergoing compulsory Information Technology Training (ITT) of minimum of 100 hours (or as decided by the Council from time to time including modalities thereof) which may commence immediately after appearing at CPT examination or during practical training relevant to professional subjects included in the chartered accountancy course (to be decided by the Board of Studies from time to time in consultation with the Council) to be eligible to appear for the Professional Competence Examination;
- Passing the Professional Competence Examination after 18 months of commencement of practical training;
- Undergoing General Management and Communication Skills Course of minimum 100 hours (or as decided by the Council from time to time as to duration and modalities thereof) after passing the Professional Competence Examination but before enrolment as a member of the Institute.
- Passing Final Examination conducted by the Institute held either during the last six months of the practical training or thereafter, provided there is minimum one examination gap between the Professional Competence Examination and Final Examination, if such Final Examination is taken up during the practical training.

7.5.5 It is proposed to increase the Practical Training from existing three years to three and half years to ensure that effective three years Practical Training (net of leave period) is imparted in harmony with the International Standards. The thrust on Information Technology Training and General Management Communication Skills course also intends to produce a well-rounded professional. With the introduction of the new scheme, the total duration of time in becoming a CA shall be around four years as against the five years and three months as at present.

7.5.6 In the era of Communication and Information Technology, the Council has recommended extensive use of e-learning facility in imparting theoretical education. The proposed restructuring of subjects is also likely to see emphasis on Business Ethics, Information Technology apart from traditional core areas like accounting including management accounting, auditing, taxation including indirect taxation and financial management. Assessment methods are also likely to undergo radical change because there will be dominant emphasis on multiple-choice type questions at CPT stage while case-study method would be the main focus of Final Examination. It is proposed that no restriction of attempts be imposed on all three examinations, namely, Common Proficiency Test (CPT), Professional Competence Examination (PCE) and Final Examination.

7.5.7 The modalities of the overall scheme as finalized by the Council of the Institute are being fine-tuned and, consequently, the proposed amendments in the Chartered Accountants' Regulations, 1988 shall be forwarded to the MCA. Keeping this in view, the new scheme may come into force in 2006.

7.6 Committee on Internal Audit

7.6.1 Mission

The Committee on Internal Audit was constituted as a Non-Standing Committee of the ICAI on 5th February 2005 to reinforce the primacy of the ICAI as a promoter, source and purveyor of knowledge relating to internal audit and other aspects related to it in the Society so as to enable its members to provide more effective and efficient value added services relating to this field to the Industry and others and help the latter to systematic and strengthen their governance process by systematising and strengthening their control and risk management process.

7.6.2 Objective

The objective of the Committee is to review the existing Internal Audit Practices in India and to develop Standards on Internal Audit (SIAs), to

develop Guidance Notes and Issue Clarifications on the issue arising from SIAs, so that these may be issued under the authority of the Council of the Institute.

7.6.3 Preface to the Standards and Guidance Notes on Internal Audit

During the year, the Committee finalised the Preface to the Standards and Guidance Notes on Internal Audit. The Preface is intended to serve as a foundation as well as benchmark to important issues such as the scope and function of the Committee on Internal Audit, defining the term "internal audit", the procedure for formulation of the Standards on Internal Audit, applicability of the Standards and Guidance Notes on Internal Audit, implications of the non-adherence to these Standards and Guidance Notes, disclosures with respect to these Standards and Guidance Notes, effective date of the Standards etc.,

7.6.4 Modular Training Programme on Internal Audit

The Committee also provided technical support in the form of the Background Material for the following programmes of the ICAI:

- Three-day Residential Modular Training Programme on Internal Audit at Kodai canal (jointly with the Committee for Continuing Professional Education).
- Two Day National Conference on Internal Audit at Mumbai (jointly with the Western India Regional Council of the ICAI)

7.6.5 Knowledge Page

During the year, the Committee has widened the coverage of and totally revamped its Knowledge Page. It currently contains such information as Terms of Reference, Constitution of the Committee, Significant Achievements, Preface to the Standards and Guidance Notes on Internal Audit and FAQs.

7.6.6 Projects in Progress

During the year, the Committee has constituted study groups to prepare the drafts of the following proposed Standards on Internal Audit:

- Basic Objectives and Principles Governing an Internal Audit
- Planning an Integral Audit
- Documentation
- Assessment of Internal Controls

7.6.7 Other activities

During the year, the Committee has also approved the following projects:

- Draft Assessment of Internal Controls w.r.t. Clause 49 of the Listing Agreement
- Draft Guidance Note on Internal Audit of Treasury in Banking Industry
- Internal Audit and Corporate Governance
- Importance of Soft Controls against Hard Controls

8. Other Matters

8.1 Annual Function of the ICAI

The 55th Annual Function of the ICAI was held on 4th February, 2005 at New Delhi. Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister for Commerce & Industry was the Chief Guest. Prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, shields and certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were awarded. The Function was attended by a very large number of invitees including senior Government Officers, members, students, officers and staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

8.2 Chartered Accountants' Day

In commemoration of the Chartered Accountants Day, a Function was organised on 1st July, 2005 at New Delhi. Hon'ble Shri H.R. Bhavadwaj, Union Minister for Law & Justice was the Chief Guest. Hon'ble Shri K. Rahman Khan, FCA, Deputy Chairman, Rajya Sabha, Hon'ble Shri Suresh P. Prabhu, FCA, Member of Parliament and Hon'ble Shri C. Ramachandraiah, FCA, Member of Parliament were the Guests of Honour. Special addresses were delivered by them. Besides the above, the Branches at various places also organised the Function locally in a befitting manner.

In commemoration of the this occasion, all buildings of ICAI at Headquarters, Regional Offices and their Branches were named as 'ICAI Bhawan'.

8.3 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988

8.3.1 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949

As reported in the last annual report, the Council of the Institute finalised the recommendations of the Working Group on the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 and submitted the same to the Central Government on 3rd August, 2002 for its consideration. Meanwhile, the Central Government came out with The Chartered Accountants (Amendment) Bill, 2003 in December, 2003. The same was placed before the Rajya Sabha by the Central Government which has been subsequently referred to the Parliament Standing Committee on Finance. The ICAI's response to the said Bill had been submitted. It is expected that the amended Act would come in to force any time.

8.3.2 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

- (i) During the year, the Central Government accorded its approval in principle to draft amendments in Regulations 25B(2) and 28B(3)

– Admission criteria of the Professional Education (Examination - I) and Professional Education (Examination - II) and Regulation 48(1) for increasing the rates of stipend payable to articled clerks joining training after passing PE-II Examination. The said draft amendments were published in the Gazette of India for inviting objection(s)/suggestion(s) within 45 days time from the respective date(s) on which the said publications were made available to public. On expiry of the specified period, further course of action will be initiated to mitigate the hardship being faced by the students.

8.4 Central Council Library

The Central Council Library provides Books, Journals, Newspapers and Reference facilities to Members, Students and Faculties of different Directorates of the Institute, Secretaries of the different Committees, Nucleus Libraries at Headquarters, Scholars from different Universities and PE-I Course Students. The library is also providing photocopy & Internet Services to the Members, alongwith a list of Articles compiled from various Professional Journals and Newspapers, a list of which is published every month in the Institute's Journal under the title *References- "Accountant's Browser"*. Noida office of the Institute and Vishwas Nagar Student Library have also been provided with Library facilities by the Central Council Library. Networking through Delnet, a Network of Libraries in India & abroad is Operational and the Computerization of Library material including Books, Journals, Articles, Members record is available on Library Software. A strong base of more than 11,000 articles including articles from ICAI Journal "Chartered Accountant" is also available in Library Software. Besides above, the library has also acquired PROWESS LAN Version, corporate database of more than 8000 Companies. Grand Zurich Software for Legal Decisions, ITR online, Excus-a Software for Electronic Library for Excise, Customs and Service Tax and Allied Laws is also available alongwith CDs on different subjects in the Central Council Library. Library is providing Web services appearing in

www.ica.org/libraryservices in Institute's Website such as:- Accountant's Browser, Articles from the Chartered Accountant, Bibliographic details of : Conference/Seminar, CD's available in Library, The Chartered Accountant's Index (Journal of ICAI) , List of Recommended Books for PE-I, PE-II & Final study of ICAI, Library Security Deposit Rules Students/Members, Library News & Views, List of Journals /Newspapers subscribed by the Library, Photographs available in the Library, Recent Additions of Books ,List of SAFA Books, Suggest Books/Journals etc.

Besides above, Library facilities are also provided at the Regional Offices and Branches throughout the Country. Efforts are on to link different Regional Libraries to Central Council Library Database after computerizing these Libraries. Library is also downloading/acquiring the important Publications from IASB, IFAC, AICPA, ICAEW, AASB & other International Professional Bodies for the reference of Members & Faculties at Central & Regional Libraries.

8.5 Editorial Board

8.5.1 'The Chartered Accountant', journal of the ICAI is the 'Brand Ambassador' for it. Further, journal is the most visible and recurrent indicator of the ICAI's profile for the members, students as well as external audiences. Continuing with its zealous drive to uplift the ICAI's Brand Ambassador 'The Chartered Accountant' journal to an international standard, The Editorial Board of the Institute has performed many a remarkable feat this year. Be it content quality, in-depth topical coverage, international standard layout/designing, paper quality, overall look and feel, greater reach or timely delivery of the journal, the Board has scored on all counts.

Having attained a higher level of professional standard, the journal has developed into a far more valuable tool of information and professional knowledge this year, not only for members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad. With ever-widening

reach and readership base, the total circulation the journal stands at more than 1,65,000 today.

8.5.2 During the period under the report, following were the key achievements of the Editorial Board:

(i) Features and Articles:

- During the period from July 2004 to June 2005 in all 1760 pages were printed in comparison of 1400 pages printed during corresponding last year. Further, as many as 202 articles were published during the year under report in contrast to 86 articles published during last year. Articles published were on all topical issues relevant for the members covering Accounting, Audit, Taxation and Law.
- A number of new features and sections including 'Professional Horizons', 'Tech 4 You', 'Career Watch', 'Accounting & Auditing Standards', 'Inside ICAI', 'Interview', and 'Readers Queries' (with incentives for best answers), etc. have been introduced.
- With a view to provide most relevant and focused information the Board has decided to bring out theme issues. The journal was brought out on the following themes:

Budget 2004-05 - July 2004

Corporate Laws - September 2004

Tax Reforms and Finance - October 2004

Risk Management - November 2004

Alternate Dispute Resolution -December 2004

Audit Quality Management - January 2005

Banking and Finance -February 2005

Union Budget 2005-2006 - March 2005

Bank Audit - April 2005

Corporate Governance - May 2005

Value Added Tax - June 2005

(ii) Contributors:

- A host of leading personalities, experts and faculty from the fields of accountancy, trade, commerce, industry, insurance and finance, etc. from India and abroad, have contributed in the journal.
- A standard panel of expert authors from different professional areas has been formed to ensure publication of quality and topical content in the journal. Comprehensive guidelines have also been prepared for the authors in this regard.
- Honorarium for reviewers of the articles has been increased while a new approach of getting the articles reviewed by two reviewers has been adopted to ensure error-free content in the journal.

(iii) Layout, Design and Printing:

- A holistic change in the basic layout, design and overall look and feel of every section of the journal has been approved to give a major facelift to the journal with effect from July 2005 Special Issue.
- A new printing, publication, despatch and delivery arrangement has been entered into for the journal with effect from July 2005 Special Issue on the theme 'Accountancy Profession in Global Perspective' which has been planned to be brought out in new look style of international standard.
- It has been decided to publish the entire journal in '4-colour format', upgrade the paper quality, initiate a comprehensive brand promotion and advertisement generation exercise and to ensure delivery of the journal on 1st of every month under the new printing and publication arrangement.
- The design and feel of the Mast Head of the journal has been upgraded to match international look with effect from October 2004 issue. The 'Spine Printing' module, giving the name/volume number/ price of the journal in the spine of the journal, has been introduced from September 2004 issue. The Cover Page of the journal has

been redesigned to match global standards with effect from February 2005 issue.

(iv) Other Initiatives:

- A complete list of circulars issued by different departments and ministries is being hosted on the ICAI website and the same is being continuously updated month-wise in addition to the publication of Circulars section in the journal with effect from March 2005 issue.
- The reach of the journal has widened with inclusion of the names of all the Members of Parliament, Secretaries to the Government of India, Chief Ministers and Chief Secretaries of all the state governments.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2005, 8,778 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 1,23,546 as on 1st April, 2005.

During the year ended 31st March, 2005, 3,246 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 3,459 in the previous year

Total Members as on 1.4.2005

Category of Members	Fellow	Associate	Total of Columns
In Full Time Practice	45,586	21,283	66,869
In Part-time Practice	3,521	7,768	11,289
Not in Practice	6,387	39,001	45,388

9.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants' Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the ICAI and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical

needs etc. The number of life members of the fund increased from 54,904 as on 31st March, 2004 to 63,071 as on 31st March, 2005. The financial particulars of the Fund are as follows :

	During the year ended 31.3.2004	During the year ended 31.3.2005
1. Total Assistance provided	39,41,223	44,26,777
2. Administrative Expenses	4,77,879	5,40,441
3. Surplus of the Fund	13,91,599	13,81,087
4. Balance of the Fund	1,59,67,275	1,73,48,362
5. Balance of Corpus	4,10,49,000	4,94,54,000

10 STUDENTS

10.1 Students Statistics

The total number of students enrolled for the PE-I, PE-II and Final Course during 1st April, 2004 and 31st March, 2005 are as under :

Course	2003-2004	2004-2005
PE-I	38188	39000
PE-II	30395	33063
PE-II with articles	3837	1127
FINAL	11390	11061

The total number of students on the rolls of the Board of Studies as on 31st March, 2005 (excluding those students who were registered for PE-I Course) was 3,28,550 as against 3,07,462 as on 31st March, 2004.

10.2. Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2005 accreditation was granted to 43 Institutions for organising the classes for students of PE (Course-I) and 30 Institutions (including 2 Branches) for PE (Course-II). During the year there was no addition to the number of Institutions for Final Course and 7 Institutions (including 1 branch) continues to be accredited for Final Course. The names of 10 Institutions each for PE-I and PE-II Courses were deleted for non-payment of Annual Levy for the financial year 2004-2005. As on 31st March, 2005, the total number of accredited Institutions for PE (Course-I) is 178 and PE (Course- II) is 95. 36 Institutions organised

classes for the benefit of students of PE (Course- I) for November 2004 and 57 Institutions organised the classes for May, 2005 Examinations. 25 Institutions organised classes for the PE (Course- II) students for November, 2004 and 20 Institutions for May, 2005 Examinations.

10.3 Review of Study Materials

As a part of continuous process, the study materials are reviewed by various subject experts and their comments and suggestions wherever considered appropriate are incorporated in the next print of the study module after due editing and verification.

10.4. Students' Counselling

Counselling Services have been in operation in Regional Headquarters to help students getting clarified their academic queries in various subjects of the curriculum.

10.5 Computer Training Course of 250 Hours

The number of students registered for computer training course of 250 hours in different regions for the period of 1st April, 2004 to 31st March, 2005 are as follows:

Western region	4422
Southern region	3282
Eastern region	1691
Central region	2503
Northern region	2305

To make the training available to the students in the vicinity of their residence, the Board of Studies widened the scope of accreditation and 61 more Institutions (including 2 Regional Councils, 7 Branches) operating at city level were granted accreditation for conducting the course.

10.6 Course on General Management and Communication Skill

During the year, 175 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 42

Centres across the country for the benefit of 8,000 participants.

10.7 Seminars and Conferences

During the year, the Board continued its policy of promoting organisation of One Day Seminars, Elocution/Quiz Contests and Regional/State Level Conferences. Branch /Regional Levels Elocution/Quiz Contests were organized by 5 Regional Councils and 25 Branches. Final Elocution/Quiz Contest was held at Jodhpur in January, 2005.

- S.I.R.C., Chennai, E.I.R.C., Kolkata, Baroda Branch of W.I.R.C and Ernakulam Branch of S.I.R.C., Asansol Branch of E.I.R.C., have organized Regional/Sub Regional Conferences on 27/28.11.2004, 1.8.2004, 18/19.6.2004, 4/5.8.2004 and 5.12.2004 respectively. Hisar Branch of N.I.R.C. organized State Level Conference on 20/21.8.2004.
- The Jaipur Branch organized National Convention for C.A. Students on 17th & 18th January, 2005.
- 17th All India C.A. Students Conference was organized by the Board of Studies at Nagpur.
- 2 Regional Councils and 23 Branches of different Regional Councils organized One Day Seminars. S.I.R.C. and 8 Branches of Regional Councils conducted other Educational Events.
- Southern Regional Office and Trichur Branch of S.I.R.C. organized Faculty Development Programmes on 18-19.12.2004 and 18.6.2004 respectively.

10.8 Scholarships

During the year ended 31st March, 2005, Scholarship were granted to 96 students [24 Merit Scholarships, 4 Merit-cum-Need based scholarships, 68 Need-based scholarships]. Further, scholarships were awarded to 37 students out of the income from various endowments set up for the purpose.

10.9 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' newsletter – 'The Chartered Accountant Student' containing useful articles, academic updates, write-ups and other relevant announcements continued to be popular and proved useful to the students. The publication proved to be popular among the members too.

The first prize (Rs. 2000/-) for the best article was awarded to Ms. Lakshmi Jayaram, Kochi, for her article on "Peer Review" published in the Newsletter of Ernakulam Branch of SICASA.

10.10 Introduction of Open Book System in the Sunday Test Paper Scheme

The Scheme of Open Book System in the Sunday Tests has been introduced for Business and Corporate Laws, Company Laws and Secretarial Practice, Direct and Indirect Tax Laws.

10.11 Conducting Virtual Classes

The first inaugural virtual class was conducted on 1st February, 2005. Shri R. Bupathy, an eminent faculty and past President of ICAI, delivered a lecture on "Issues in Taxation on Business Income".

10.12 Online Examinations for Eligibility Tests for Professional Education (Course – II) on pilot basis.

During the year, 5 Online Examinations (in 20 batches) for Eligibility Tests for the subjects of Information Technology, Income tax and Financial Management of Professional Education (Course – II) were conducted in association with an external vendor.

10.13 Online Opinion Poll

The Board has initiated a series of Online web-poll seeking opinion on different aspects related to the students.

10.14 Students Exchange Programme

Under the aegis of Students Exchange Programme, 26 students (ICAP-7, ICAB-4, ICAN-11, ICASL-4) of SAFA member bodies visited India and participated in 17th All India CA Students Conference at Nagpur. 9 students of ICAI also went to Lahore at the invitation of ICAP in January, 2005.

10.15 Development of E-Learning Module

The area of education and training is undergoing a sea change due to the many new forms of technology that are becoming available. Web-based learning, CD-ROM training and interactive computer simulations are transforming the future of education. E-education in its various forms is becoming an integral part of the educational system internationally. At the preliminary level, the ICAI is interacting with the students through a specifically created e-mail id guidance@icai.org. This is monitored by a consultative group of faculty and provides on-line help to the students. Students who do not have the facility to get the guidance for solving their academic problems arising in the course of their preparation can take advantage of the scheme.

During the year, the Board continued to focus itself in imparting education mainly through distant education mode to the students of the professional course of Chartered Accountancy as well as Professional Education Courses. It also played a crucial role in the functioning of four non-standing Committees, viz., Auditing & Assurance Standards Board, Committee on Commerce Education & Career Counselling, Committee on Financial Markets & Investors' Protection, Fiscal Laws Committee. Besides, it is also providing technical support to Peer Review Board.

The Board is in process of creating On-line Chatting, expanding the scope of online Examinations for Eligibility Tests and PE-II and Final Courses.

10.16 Self-development Booklet Series

Self-development booklet on Audit Documentation was brought during the year.

10.17 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of a spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 34 branches of Students' Association have already been set up.

10.18 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2005, 57 scholarships of the value of Rs. 300 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. The membership of the Fund was 349 as on 31st March, 2005 as against 346 as on 31st March, 2004. The balance in the credit of the Fund was Rs. 9,02,384/- as on 31st March, 2005 as against Rs. 6,86,834/- as on 31st March, 2004.

10.19 Recognition of CA Course for Ph. D. Programme

With constant follow-up with various Universities, the Committee on Commerce Education & Career Counselling has been successful in obtaining recognition for CA Course from 76 Universities besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of PHD/Fellow Programme.

11. Regional Councils and their Branches

11.1 The Institute has five Regional Councils, namely, Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their

Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.1.1 The total number of branches of Regional Councils is 104.

11.1.2 The total number of Chapters of the Institute outside India is 15.

11.1.3 The total number of Reference libraries all over India is 24.

11.2 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 54 branches have their own premises.

11.3 Rotating Shield

The Institute awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded each year to the Best Branch. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional Basis have been instituted from the year 1999. For the year 2004 these Shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2005 to the following winners:-

- Best Regional Council - Western India Regional Council
- Best Branch of Regional Council - Nagpur Branch of Western India Regional Council
- Best Students' Association - Western India Chartered Accountants Students' Association
- Best Branch of Students' Association
 - Western Region - Baroda Branch of WICASA
 - Southern Region - Ernakulam Branch of SICASA

Considering their performance, the following branches were separately awarded certificates for Highly Commended Performance:-

- Baroda Branch of Western India Regional Council
- Hubli Branch of Southern India Regional Council
- Salem Branch of Southern India Regional Council

11.4 New Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the ICAI has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level seven more decentralised offices have been set up at Surat, Nagpur and Vadodara (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Southern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

12. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2005 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13. APPRECIATION

13.1 The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 2004-2005 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

13.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2004-2005.

13.3 The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to the dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced the programmes organised by the organs of the ICAI.

13.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

13.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2004 - 2005 by all officers and staff of the Institute.

STATISTICS AT A GLANCE**MEMBERS (FROM 1.4.1997)****TABLE I**

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1.4.1997	Associate	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	Fellow	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	Total	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	Associate	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	Fellow	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	Total	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1.4.2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546

MEMBERS (FROM 1.4.1950)**TABLE II**

	As on 1.4.1950	As on 1.4.1951	As on 1.4.1961	As on 1.4.1971	As on 1.4.1981	As on 1.4.1991	As on 1.4.2001
Fellows	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
Associates	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
Total	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

	As on 1.4.2002	As on 1.4.2003	As on 1.4.2004	As on 1.4.2005
Fellows	47064	49637	52707	55494
Associates	54666	60619	63384	68052
Total	101730	110256	116091	123546

STUDENTS GROWTH PROFILE (FROM 31.3.1996)

	During the year 1995-96	During the year 1996-97	During the year 1997-98	During the year 1998-99	During the year 1999-2000	During the year 2000-01	During the year 2001-02
Foundation/ PE (Course I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
Intermediate /PE (Course II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
Final	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
Total	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

	During the year 2002-03	During the year 2003-04	During the year 2004-05
Foundation/ PE (Course I)	35524	38188	39000
Intermediate /PE (Course II)	33283	34232	34190
Final	11102	11390	11061
Total	79909	83810	84251

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006

** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

COMPOSITION OF NINETEENTH COUNCIL (2005 – 2006)

PRESIDENT	VICE-PRESIDENT	PERIOD
Shri Kamlesh S. Vikamsey, FCA	Shri T.N. Manoharan, FCA	5 th February, 2005 onwards
SECRETARY Dr. Ashok Haldia		

MEMBERS OF THE NINETEENTH COUNCIL (2005 – 2006)**ELECTED MEMBERS:**

Shri Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
Shri Amarjit Chopra	New Delhi
Shri Anuj Goyal	Ghaziabad
Shri Charanjot Singh Nanda	New Delhi
Shri G. Ramaswamy	Coimbatore
Shri H.N. Motiwalla	Mumbai
Shri Harinderjit Singh	New Delhi
Shri J.P. Gokhale	Mumbai
Shri Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
Shri K.P. Khandelwal	Kolkata
Shri Kamlesh S. Vikamsey	Mumbai
Shri Manoj Fadnis	Indore
Shri Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
Shri R. S. Adukia	Mumbai
Shri S. Gopalakrishnan	Hyderabad
Shri S. Santhanakrishnan	Chennai
Shri S.C. Vasudeva	New Delhi
Shri Shanti Lal Daga	Hyderabad
Shri Sunil Goyal	Jaipur
Shri Sunil Talati	Ahmedabad
Shri T. N. Manoharan	Chennai
Shri Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
Shri V. Murali	Chennai
Shri Ved Jain	New Delhi

NOMINATED MEMBERS:


Ms. Bulbul Sen (w.e.f. 18.01.05)	New Delhi
Shri Jitesh Khosla	New Delhi
Shri K.C. Parashar	Jodhpur
Shri Pawan Kumar Sharma	Guwahati
Shri Sidharth Kumar Birla	New Delhi
Shri T.G. Srinivasan (w.e.f. 08.11.04)	New Delhi

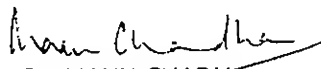
AUDITORS

Shri Shashi Kumar, FCA	New Delhi
Shri Manu Chadha, FCA	New Delhi

AUDITOR'S REPORT TO THE COUNCIL

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2005 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on the date incorporating the accounts of the Institute's offices, Computer Centres, Regional Councils and their branches audited by other auditors and that their reports have been duly considered while preparing our report. These financial statements are the responsibility of the management of the Institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We further report that :-
 - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;
 - d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards.
 - e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:
 - i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2005 ;
 - ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date and
 - iii) In the case of the cash flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.


Ca. SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492


Ca. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place : New Delhi
Date : 9th July, 2005.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2005

	Schedule	Amount As At 31-03-2005	Rs. in lacs Amount As At 31-03-2004
SOURCES OF FUNDS:			
Capital Reserves	I	4224.69	3800.12
General Reserve	II	3002.01	2354.40
Other Reserves	III	99.11	87.68
Earmarked Funds	IV	5835.19	5090.84
TOTAL		13161.00	11333.04
APPLICATION OF FUNDS:			
<u>Fixed Assets:</u>			
	V		
Gross Block		5661.71	4237.54
Less: Depreciation and Amortisation		2408.74	1866.69
Net Block		3252.97	2370.85
Capital Work in progress including capital advances		2820.65	841.75
<u>Investments:</u>			
	VI		
Earmarked Fund Investments		5835.19	5090.84
Other Investments		2133.74	3644.40
		7968.93	8735.24
<u>Current Assets, Loans & Advances :</u>			
Interest Accrued on Investments		717.58	797.91
Inventories	VII	287.25	270.87
Accounts Receivables	VIII	98.48	147.77
Cash & Bank Balances		620.78	605.22
Loans & Advances	IX	1130.56	590.09
Sub - Total		2854.65	2411.86
<u>Less: Current Liabilities & Provisions</u>			
Fees/Income Received in Advance	X	2832.90	2034.61
Creditors for Expenses		437.90	539.99
Provision for Gratuity		155.20	158.99
Other Liabilities		310.20	293.07
Sub - Total		3736.20	3026.66
Net Current Assets		(881.55)	(614.80)
TOTAL		13161.00	11333.04

Statement of significant accounting policies

XIV

Notes forming part of Accounts.

XV

Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Ca. DEEPAK DIKSHIT	Ca. ASHOK HALDIA	Ca. T. N. MANOHARAN	Ca. KAMLESH S. VIKAMSEY
JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
 Ca. SHASHI KUMAR
 CHARTERED ACCOUNTANT
 MEMBERSHIP NUMBER-86492

Sd/-
 Ca. MANU CHADHA
 CHARTERED ACCOUNTANT
 MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place : New Delhi

Date : 9th July, 2005.

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2005**

		Rs.in lacs	
		Amount	Amount
	Schedule	Year ended	Year ended
		31/03/2005	31/03/2004
INCOME			
Fees	XI	7008.08	6355.99
Publications		374.02	444.60
Seminars		1153.74	813.18
Interest on Investments		313.67	420.15
Other Income	XII	385.23	365.51
Prior Period Income		34.97	16.00
	TOTAL	9269.71	8415.43
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		1812.89	1800.26
Printing & Stationery		1239.71	1036.12
Seminar Expenses		998.93	709.59
Postage, Telegrams & Telephones		468.58	408.23
Rent, Rates & Taxes		356.38	250.15
Travelling & Conveyance-Inland		532.36	475.66
Overseas Relations:			
-Travelling	97.93	57.76	
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies	54.09	54.08	
-Other Expenses	12.31	164.33	120.05
Repairs & Maintenance		202.34	206.65
Publications		149.92	129.88
Other Operating Expenses	XIII	1493.94	1354.64
Election Expenses			118.64
Contribution to National Foundation for Corporate Governance			100.00
Loss on sale of Investments in Units of Unit Trust of India			25.35
Depreciation and Amortisation		549.79	301.66
Prior Period Expenses		44.68	33.71
	TOTAL	8013.85	7070.59
NET SURPLUS		1255.86	1344.84
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (b)]		538.69	527.71
Employees Benevolent Fund [Policy No.III (c)]		10.00	9.65
General Reserve		707.17	807.48
	TOTAL	1255.86	1344.84

Statement of significant accounting policies

XIV

Notes forming part of Accounts.

XV

Schedules referred to above form an Integral Part of the Income and Expenditure Account

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Ca. DEEPAK DIKSHIT	Ca. ASHOK HALDIA	Ca. T. N. MANOHARAN	Ca. KAMLESH S. VIKAMSEY
JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
Ca. SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492

Sd/-
Ca. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place : New Delhi

Date : 9th July, 2005.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2005			
	(Amount Rupees in Lakhs)		
	2004-2005	2003-2004	
A. Cash flows from operating activities			
Net Surplus		1255.86	1344.84
Adjustments for:			
Depreciation and Amortisation	549.79	301.66	
Deferred Revenue Expenditure	0.00	1.65	
Loss on Sale of Investments	0.00	25.35	
Interest on investments	(313.67)	(420.15)	
	236.12	(91.49)	
Operating surplus before working capital changes		1491.98	1253.35
Increase in Inventories	(16.38)	(52.11)	
Decrease in Interest accrued on Investments	80.33	200.86	
Decrease in Accounts Receivables	49.29	(52.67)	
Increase in Loans & advances	(540.47)	(33.68)	
Increase in Fees/Income received in advance	798.29	5.09	
Decrease in Creditors for Expenses	(102.09)	(34.07)	
Decrease in Provision of Gratuity Fund	(3.79)	(20.69)	
Increase/Decrease in Other Liabilities	17.13	(13.79)	
	282.31	(1.06)	
Net cash from operating activities		1774.29	1252.29
B. Cash flows from investing activities			
Acquisition of Fixed Assets	(1431.91)	(982.19)	
Capital Work in Progress	(1978.90)	(135.54)	
Acquisition of Investments	766.31	(792.91)	
Interest on investments	313.67	420.15	
Income from Earmarked Funds Investments	302.26	271.47	
Capital Receipts	269.84	454.60	
Loss on Sale of Investments	0.00	(25.35)	
Net Cash from Investing Activities		(1758.73)	(789.77)
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents		15.56	462.52
Cash and Cash equivalents at the beginning of year		605.22	142.70
Cash and Cash equivalents at the end of year		620.78	605.22

Statement of significant accounting policies

XIV

Notes forming part of Accounts.

XV

Schedules referred to above form an Integral Part of the Cashflow Statement

Sd/-
Ca. DEEPAK DIKSHIT
JOINT SECRETARY

Sd/-
Ca. ASHOK HALDIA
SECRETARY

Sd/-
Ca. T. N. MANOHARAN
VICE PRESIDENT

Sd/-
Ca. KAMLESH S. VIKAMSEY
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
Ca. SHASHI KUMAR
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-86492

Sd/-
Ca. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place : New Delhi

Date : 9th July, 2005.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE I
CAPITAL RESERVES**

	Rs. in lacs	
	Amount As At 31.03.2005	Amount As At 31.03.2004
(A) General:		
Opening balance	1106.10	1097.50
Add:		
- Membership Fees [Policy No. III (a)]	24.05	20.67
- Donations for Buildings	52.59	28.58
Transferred from:		
- General Reserves	16.10	7.91
- Other Reserves	0.77	-
- Earmarked Funds - Others	3.81	3.21
Less:		
- Adjustments towards EIRC/Chandigarh land		(51.77)
TOTAL (A)	1203.42	1106.10
(B) Education:		
Opening balance	2694.02	1934.00
Add: Transfer from Computerisation Fund [Policy No. III (d) (i)]	-	401.83
Add: Transfer from Education Fund [Policy No. III (d) (iii)]	327.25	358.19
TOTAL (B)	3021.27	2694.02
GRAND TOTAL (A) + (B)	4224.69	3800.12

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE II
GENERAL RESERVES**

	Amount As At 31.03.2005	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2004
Opening balance	2354.40	1609.96
Add:		
Appropriation from Income and Expenditure Account	707.17	807.48
	707.17	807.48
Less transfer to:		
- Earmarked Funds -Research	1.25	1.97
- Earmarked Funds -Medals	0.06	3.09
-Earmarked Fund - Others	28.53	44.25
-Other Reserves	13.62	5.82
-Capital Reserves -General	16.10	7.91
	(59.56)	(63.04)
TOTAL	3002.01	2354.40

**SCHEDULE III
OTHER RESERVES***

	Amount As At 31.03.2005	Rs in lacs Amount As At 31.03.2004
Opening balance	87.68	77.14
Add transfer from:		
- General Reserves	13.62	5.82
Less transfer to:		
- Capital Reserves	0.77	
- Earmarked Funds -Others	(0.77)	0.05
Net Depletion/Addition during the year	(1.42)	4.77
TOTAL	99.11	87.68

* Other Reserves are reserves such as Library Reserves and Coaching Classes Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches .

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE IV****EARMARKED FUNDS**

	Amount As At 31.03.2005	Rs. in lacs Amount As At 31.03.2004
RESEARCH FUNDS		
Opening Balance	453.15	398.71
Transfer from General Reserve	1.25	1.97
Contribution received during the year	17.85	20.70
Income during the year	<u>51.71</u>	<u>31.97</u>
Less: Payments during the year	(0.30)	(0.20)
SUB-TOTAL (A)	<u>523.66</u>	<u>453.15</u>
ACCOUNTING RESEARCH FOUNDATION AND BUILDING FUND		
Opening Balance	257.77	238.57
Income during the year	19.90	19.20
SUB-TOTAL (B)	<u>277.67</u>	<u>257.77</u>
COMPUTERISATION FUND		
Opening Balance		371.89
Appropriation from Income & Expenditure Account		
Income during the year		<u>29.94</u>
Less: Transfer to Capital Reserves - Education [Policy No.III(d)(i)]		(401.83)
SUB-TOTAL (C)		<u></u>
EDUCATION FUND		
Opening Balance	2663.85	2308.50
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No. III(b)]	538.69	527.71
Income during the year	<u>205.65</u>	<u>185.83</u>
Less: Transfer to Capital Reserves - Education [Policy No.III(d)(iii)]	(327.25)	(358.19)
SUB-TOTAL (D)	<u>3080.94</u>	<u>2663.85</u>
MEDALS AND PRIZES FUNDS		
Opening Balance	79.18	57.48
Contribution received during the year	9.54	17.59
Income during the year	5.57	4.55
Transfer from General Reserve	0.06	<u>3.09</u>
Less: Payments during the year	2.60	3.50
Adjustments	<u>0.90</u>	<u>0.03</u>
SUB-TOTAL (E)	<u>90.85</u>	<u>79.18</u>

contd...

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IV

EARMARKED FUNDS (Contd)

	Amount As At 31.03.2005		Rs. in lacs As At 31.03.2004	
<u>STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS</u>				
Opening Balance		26.97		25.34
Contribution received during the year			0.91	
Income during the year	<u>2.08</u>	2.08	<u>2.07</u>	2.98
Less:Payments during the year		(0.87)		(1.35)
SUB-TOTAL (F)		<u>28.18</u>		<u>26.97</u>
<u>PENSION FUND</u>				
Opening Balance		920.03		613.85
Additions during the year	<u>92.99</u>		301.22	
Income during the year	<u>71.03</u>	164.02	<u>49.41</u>	350.63
Less:Payments during the year		(50.73)		(44.45)
SUB-TOTAL (G)		<u>1033.32</u>		<u>920.03</u>
<u>LEAVE ENCASHMENT FUND</u>				
Opening Balance		356.31		278.12
Additions during the year	<u>66.20</u>		89.62	
Income during the year	<u>27.51</u>	93.71	<u>22.39</u>	112.01
Less:Payments during the year		(38.53)		(33.82)
SUB-TOTAL (H)		<u>411.49</u>		<u>356.31</u>
<u>EMPLOYEES BENEVOLENT FUND</u>				
Opening Balance		59.59		46.86
Appropriation from Income & Expenditure Account [Policy No.III (c)]	<u>10.00</u>		9.65	
Income during the year	<u>4.60</u>	14.60	<u>3.77</u>	13.42
Less:Payments during the year		(0.51)		(0.69)
SUB-TOTAL (I)		<u>73.68</u>		<u>59.59</u>
<u>OTHER FUNDS (Regional Councils & Branches)</u>				
Opening Balance		273.99		203.73
Contribution received during the year	<u>8.04</u>		22.31	
Income during the year	<u>17.48</u>		11.32	
Transfer from Other Reserves			0.05	
Transfer from General Reserve	<u>28.53</u>	54.05	<u>44.25</u>	77.93
Less: Transfer to Capital Reserves- General	<u>3.81</u>		<u>3.21</u>	
Adjustments	<u>0.12</u>		0.22	
Payments during the year	<u>8.71</u>	(12.64)	<u>4.24</u>	(7.67)
SUB-TOTAL (J)		<u>315.40</u>		<u>273.99</u>
GRAND TOTAL		<u>5835.19</u>		<u>5090.84</u>

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "V"
FIXED ASSETS

ASSETS	G R O S S B L O C K				DEPRECIATION AND AMORTISATION BLOCK				N E T B L O C K		Rs In lacs										
	Cost as at 1.4.2004	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2005	Upto 1.4.2004	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2005	W.D.V as on 31.3.2005	W.D.V as on 31.3.2004											
A.Tangible Assets:																					
1. Land - Free Hold	214.70	26.90	(141.17)	100.43	0.00			0.00	100.43	214.70											
2. Land -Lease Hold (Note No. 2.3)	299.14	16.00	144.85	459.99	24.49	5.19	3.84	33.52	426.47	274.65											
3. Buildings	1027.20	163.56	661.39	1852.15	357.72	65.82	8.57	432.11	1420.04	669.48											
4. Electric Installations & Fittings	198.65	46.25	0.23	245.13	85.85	13.06	(1.16)	97.75	147.38	112.80											
5.Computers	965.02	93.94		1058.96	589.32	247.52	(0.77)	836.07	222.89	375.70											
6. Air Conditioning	202.76	90.83	(0.43)	293.16	81.52	25.62	(0.26)	106.88	186.28	121.24											
7. Furniture & Fixtures	502.02	120.32	(2.96)	619.38	201.79	35.83	(4.09)	233.53	385.85	300.23											
8. Lifts	80.63	21.02		101.65	22.31	7.57		29.88	71.77	58.32											
9.Office Equipments	312.17	30.13	(9.52)	332.78	169.71	22.93	(6.21)	186.43	146.35	142.46											
10.Vehicles	31.30	0.27	(0.23)	31.34	13.37	3.60	(0.05)	16.92	14.42	17.93											
11.Library Books	278.94	36.27	(7.61)	307.60	278.94	36.27	(7.61)	307.60	0.00	0.00											
B.Intangible Asset:																					
Software	125.01	14.50	119.63	259.14	41.67	86.38		128.05	131.09	83.34											
<hr/>																					
TOTAL											4237.54	659.99	764.18	5661.71	1866.69	549.79	(7.74)	2408.74	3252.97	2370.85	
Previous Year Figures												3207.09	1032.50	(2.05)	4237.54	1555.51	301.66	(0.48)	1866.69	2370.85	1641.58

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE "VI"
INVESTMENTS

	Amount As At 31-03-2005	Rs in lacs Amount As At 31-03-2004
A. LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)		
Units 2002/1964 Scheme		0.61
(II) Government of India-8% (taxable) Bonds-2003	2400.00	1100.00
(III) Fixed Deposits with scheduled Banks	3909.12	5112.04
B. CURRENT INVESTMENTS		
Fixed Deposits with scheduled Banks	1659.81	2522.59
Total Investments	7968.93	8735.24
ALLOCATED TO:-		
Earmarked Fund Investments	5835.19	5090.84
Other Investments	2133.74	3644.40
Total	7968.93	8735.24

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII:

INVENTORIES

	Amount As At 31.03.2005	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2004
Publications and Study Materials	176.88	166.39
Paper for Study Materials & Publications (Including Stock of Paper with Printers - Rs.81.63 lacs Previous year Rs.78.94 lacs)	90.64	83.88
Stationery & Other Items	19.73	20.60
Total	287.25	270.87

SCHEDULE VIII:**ACCOUNTS RECEIVABLE**

	Amount As At 31.03.2005	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2004
Other Receivables	104.68	155.37
Less: Provision for doubtful receivables	(6.20)	(7.60)
	98.48	147.77
Total	98.48	147.77

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE IX:****LOANS & ADVANCES (Considered Good)**

	Amount As At 31.03.2005	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2004
Loans and Advances-Staff	228.16	233.18
Interest Recoverable from Staff Loans	86.18	77.39
Security Deposits	31.92	18.95
Other - Advances & Pre-payments	784.30	260.57
Total	1130.56	590.09

SCHEDULE X:**FEES/INCOME RECEIVED IN ADVANCE**

	Amount As At 31.03.2005	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2004
Examination Fees	1306.74	843.38
Journal Subscription	4.12	0.53
Membership/Students's Fee	369.90	358.79
Tuition Fee	951.07	590.62
Information System Audit Course Fee	101.54	125.49
Insurance and Risk Management Course	16.89	58.44

International Trade Laws & WTO Course	3.40	
Seminar Fees & Other Collections	79.24	57.36
Total	2832.90	2034.61

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XI

FEES :

	Amount Year ended 31/03/2005	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2004
Distant Education Fee	2154.77	2110.83
Examination Fee	2227.58	1672.52
Membership Fee	1359.13	1310.79
Information System Audit Course Fee	490.80	647.77
General Management Skill Course Fee	418.77	335.16
Coaching Class Income (Regional Councils & Branches)	237.11	192.08
Insurance and Risk Management Course	75.59	58.89
Students' Registration Fee	9.87	10.97
CAAT Course Fee	20.32	8.26
Entrance Fee	8.78	6.89
International Trade Laws & WTO Course	3.40	
Students' Association Fee	1.96	1.83
TOTAL	7008.08	6355.99

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XII

OTHER INCOME

	Amount Year ended 31/03/2005	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2004
Students' Newsletter	10.29	8.83
Income from Journal -- Subscription	104.48	75.81
News Letters (Regional Councils & Branches)	33.18	23.31
Computer Centres	44.62	36.61
Fees for filing Disciplinary Cases	0.22	0.35
Campus Interview	72.53	51.70
Expert Advisory Committee Fee	9.80	5.45
Interest on Staff Loans	15.47	15.21
Provisions no longer required written back	6.21	35.88
Others	88.43	112.36
	<u>Total</u> 385.23	<u>365.51</u>

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

OTHER OPERATING EXPENSES

	Amount Year ended 31/03/2005	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2004
Fees & Expenses to Examiners, Consultants and Others	798.39	743.76
General Management Skill Course	264.00	217.73
Coaching Class Expenses (Regional Councils & Branches)	133.14	110.46

Advertisements	43.49	63.42
Office Meeting Expenses	52.64	38.08
Computer Centres	20.69	15.64
Merit Scholarship	1.46	2.20
<u>Audit Fee</u>		
- Head Office	2.48	2.43
- Other Offices	5.96	5.19
Deferred Revenue Expenditure	-	1.65
Other Expenses	171.69	154.08
Total	1493.94	1354.64

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIV

STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.

I ACCOUNTING CONVENTION

The accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards and are on accrual basis unless otherwise stated.

II REVENUE RECOGNITION

- a. 1/3rd portion of the Entrance Fees from Associate members is treated as Income.
- b. Annual Membership Fee, Fee for Certificate of Practice, Tuition Fee, Course Fee, Examination Fee and Subscription for Journal is recognized in the first year to the extent it represents income of the year on the basis of matching concept, the balance receipt is carried to succeeding year/years and recognized in the relevant year based on the matching concept.
- c. Income from Investments
 - i. Dividend on investments in units is recognized as income on the basis of entitlement to receive.
 - ii. Income on Interest bearing securities and fixed deposits with banks is accounted for on accrual basis.
 - iii. Income from investments is allocated to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of weighted average method.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO CAPITAL RESERVE AND EARMARKED FUND

- a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from Associate Members are directly taken to Capital Reserve – General.
- b. Donations received during the year for buildings and for Research purpose are accounted for directly under the respective Reserves Account.
- c. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education fund.

- d. 0.75% of Membership Fee (Associate and Fellow and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Funds.
- e. Transfer to Capital Reserve – Education from the following earmarked funds :-
- | | |
|---|---|
| i) From Computerisation Fund | 100% of the cost of purchase of computers and related accessories in relation to Decentralised Offices and Head Office computerization Project. |
| ii) From Accounting Research Foundation Fund. | 100% of the cost of Fixed Assets and other Building relating to Accounting Research Foundation. |
| iii) From Education Fund | 50% of the cost of additions (net of deductions) to other Fixed Assets. |

V FIXED ASSETS/DEPRECIATION

- a. Fixed Assets ~~excluding~~ leasehold land are stated at historical cost less depreciation.
- b. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.
- c. Depreciation on additions is provided on monthly pro-rata basis except library books which is fully depreciated in the year of purchase.
- d. Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Executive Committee/Council of the Institute based on the useful life of the respective assets :
- | | |
|--|-----|
| Buildings | 5% |
| Air conditioners & Office Equipments | 15% |
| Lifts, Electrical Installations & Furniture & Fixtures | 10% |
| Vehicles | 20% |
| Computers | 60% |
- e. Intangible Assets (Software) is amortized equally over three years.

V INVESTMENTS

- a. Investments held or intended to be held for a period of more than one year are considered long term investments and are carried at cost. Diminution in value other than temporary is provided for.
- b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI INVENTORIES

Inventories of paper, stationery, publications and study material are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- a. Transactions denominated in foreign currencies are normally recorded at the exchange rate prevailing at the time of the transaction.
- b. Overseas Office's Income and expenses are translated at average rate. Its monetary assets and liabilities are translated at year-end rates. Non-monetary items are translated at the rates on the date of transaction.
- c. Any income or expense on account of exchange difference either on settlement or on translation is recognized in the profit and loss account.

VIII. TERMINAL/RETIREMENT BENEFITS.

- a. Year's liability towards gratuity is based on actuarial valuation and the contribution made to LIC on this account is charged to Income and Expenditure Account.
- b. Year's liability towards pension and leave encashment is based on actuarial valuation and the amount so determined is charged to income and expenditure account and separate earmarked funds are maintained for the same.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**SCHEDULE XV****NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS****1. CONTINGENT LIABILITIES**

- 1.1 Rs.24.68 Lacs towards disputed amount for Property/Building Tax in respect of three branches (Previous year Rs. 19.50 Lacs).
- 1.2 Rs. 17.75 Lacs in respect of claims (Previous year Rs. 17.75 Lacs) from various parties not acknowledged by the Institute.

2. NOTES

- 2.1 Estimated amount of capital commitment (net of advances) – Rs. 66.54 Lacs (Previous Year Rs. 227.80 Lacs).
- 2.2 Leasehold Land includes Rs. 2.51 lacs(Previous year Rs.2.51 lacs) relating to the Land at Hubli which is under litigation. Possession of this land is yet to be handed over to the Institute.
- 2.3 The Institute regulates the profession of Chartered Accountancy in India and operates in one operational segment predominantly in India.
- 2.4 Loans and Advances include Interest free advance for a sum of Rs. 589.93 lacs (previous year Rs.24.69 lacs) to ICAI Accounting Research Foundation.
- 2.5 Prior period Income includes following

	2004-05 Rs. in Lacs	2003-04 Rs. in Lacs
Examination Fees	46.66	-
Seminar Income	(17.63)	-
Others	5.94	16.00
Total ---->	<u>34.97</u>	<u>16.00</u>

Prior period expenses includes following:-

Depreciation/Amortization	12.53	-
ISA Expenses	-	11.97
Seminar Expenses	4.20	-
Others	27.95	21.74
Total ---->	<u>44.68</u>	<u>33.71</u>

- 2.6 In view of the income exempt under Section 10 (23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax/Deferred Tax Asset/Liability is considered necessary.

- 2.7 AS-3 has been compiled with and indirect method used to determine the Cash Flow Statement.
- 2.8 Only directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.
- 2.9 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary to make it comparable with current year's presentation.

[ADVT. III/VI/104/2005-Exty.]
Dr. ASHOK HALDIAY, Secy.